# लोक-सभा
# वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड १३, १९६३ / १८८४ (शक)

[१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३ / २९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)]

3rd Lok sabha

Preservation Unit
21-5-92
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

Chamber Fumigated 18·10·73

चौथा सत्र, १९६३/१८८४ (शक)

(खण्ड १३ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

# विषय-सूची

## तृतीय माला, खण्ड १३–अंक १ से १०—१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३/२९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)


अंक १—सोमवार, १८ फरवरी, १९६३/२९ माघ, १८८४ (शक)

| | |
|---|---|
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डालना तथा सदन से बाहर चले जाना | १–३ |
| राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया | ४–९ |
| विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति | १० |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | १०–११ |
| बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक— | |
| प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना | १२ |
| संविधान संशोधन विधेयक— | |
| संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना | १२–१३ |
| दैनिक संक्षेपिका | १४–१६ |

---

अंक २—मंगलवार, १९ फरवरी, १९६३ / ३० माघ, १८८४ (शक)

| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १ से ६, और ९ से १२ | १७–४२ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ७, ८, १३ से २७ और ३० | ४२–५१ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५० | ५१–७२ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हुई घटना के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | ७२ |
| जमुना कोयला खान में हुई दुर्घटना | ७२–७४ |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में | ७४ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ७४–७७ |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ | ७७ |
| अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१ | ७७ |

कार्य मंत्रणा समिति ७७

बारहवां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ७८

बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ७८

रेलवे आय-व्ययक, १९६३-६४—उपस्थापित

श्री स्वर्ण सिंह ७८-१००

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिये समिति १००-०१

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक १०१

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०१-०४

खंड २ और १ १०४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १०४

कृषि पुर्नवित्त निगम विधेयक, १०५-११९

विचार करने का प्रस्ताव

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव ११९-२८

दैनिक संक्षेपिका १२९-३६

---

अंक ३—बुधवार, २० फरवरी, १९६३/१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१ से ४२ १३६-६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५५ १६२-७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१ से ८६, ८८, ८९, ९१ और ९२ १७०-८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १८७

कारीगरी और स्वर्णकारों में कथित बेकारी

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८७

प्राक्कलन समिति १८७-८८

चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन

सभापति तालिका १८८

कार्य मंत्रणा समिति १८८

बारहवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १८९-२३४

दैनिक संक्षेपिका २३५-३८

**अंक ४—शुक्रवार २१ फरवरी १९६३ / २ फाल्गुन १८८४ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . २३९—६४

तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से ७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८२ . . . २६५—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४ से १०० और १०२ से १२४ . २७२—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २८५—८७

अमरीका तथा राष्ट्रमंडल के संयुक्त वायु सेना के शिष्टमंडल का भारत आगमन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ . . . २८७

लोक लेखा समिति . . . . . २८७

छठा प्रतिवेदन

सोना नियंत्रण सम्बन्धी भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियमों के बारे में याचिका . २८७

संघ राज्य क्षेत्रों का शासन विधेयक—पुरस्थापित . . . २८७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . २८८—३१५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१६—१९

**अंक ५—शुक्रवार २२ फरवरी, १९६३ / ३ फाल्गुन १८८४ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९४, ९६ से ९९ और १०१ से १०४ . ३२१—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ और १०० . . . ३५२—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५ से १२९, १३१, १३३ से १४८ और १५० . ३५३—६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३६४—६५

प्रस्तावित मलयेशिया संघ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६५—६७

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा पटल पर रखी गई . . . . ३६८

प्राक्कलन समिति

बारहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन . . . . ३६८

सभा का कार्य . . . . . . ३६८

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ३६९—८६

विधेयक पुरस्थापित — . . . . ३८६—८७

(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा १३ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का ]

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक, (धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

(३) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक (नई धारा ७क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्या का]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, (धारा ४ और ६ का संशोधन) . ३८७—९८
[श्री श्याम लाल सर्राफ का]

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

सिनेमा फिल्मों की (अधिकतम ) लम्बाई विधेयक [श्री रामेश्वर टांटिया का ] ३९८—४०८

विचार करने का प्रस्ताव

बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) . ४०८
[श्री दी० चं० शर्मा का]

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४०८

कार्य मंत्रणा समिति . . . . . . ४०८

तेरहवां प्रतिवेदन

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४०९—१४

अंक ६—सोमवार २५ फरवरी १९६३ / ६ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०५ से ११४ . . . ४१५—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११५ से १३२ . . . ४४०—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १७६ और १७८ से १९५ . ४५३—७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ४७१—७२

(१) मिलिटरी लाइन्स, सागर में पानी की एक टंकी का फट जाना

(२) बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वहां के भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ४७२
कार्य मंत्रणा समिति
तेरहवां प्रतिवेदन . . . . . ४७३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ४७३—५३१
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३२—३६

अंक ७—बुधवार २७ फरवरी १९६४ / ८ फाल्गु १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३४, १४८ और १३५ से १४३ . ५३७—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १४७ और १४९ से १५२ . ५६२—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या १९६ से २३३ . . . ५६५—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५८०—८४
(१) १८ फरवरी को गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस का कथित अनधिकृत प्रवेश
(२) बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीय करण के बारे में वक्तव्य
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५८४—८५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
तेरहवां प्रतिवेदन . . . . . ५८५
निर्यात के लिये भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रायायत के बारे में वक्तव्य . ५८६
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ५८७—६३४
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३५—३९

अंक ८—गुरुवार २८ फरवरी १९६३ / ९ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १५३ से १६६ . . . ६४१—६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ६६७—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १६७ से १७० और १७२ . . ६६९—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३४ से २३९ और २४१ से २६० . ६७१—८३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६८३—८४

समुद्रीय बीमा विधेयक . . . . ६८५

संयुक्त समिकिता प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति . . . . ६८५

तेरहवां और बीसवां प्रतिवेदन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ . . ६८६—९८

कृषि पुर्दवित निगम विधेयक . . . ६९८—७२४

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ४७ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६३–६४—उपस्थापित . ७२४—४७

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ७४८—४९

(१) वित्त विधेयक, १९६३

(२) अधिलाभ कर विधेयक, १९६३

(३) अनिवार्या जमा योजना विधेयक, १९६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ७५०—५४

शुक्रवार, १ मार्च, १९६३/१० फाल्गुन, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

डा० राजेन्द्र प्रसाद का निधन . . . ७५५—५९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७६०

अंक १०—शनिवार २ मार्च १९६३ / ११ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से २०६ और २०९ . . ७६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७३ से १९३, २०७, २०८ और २१० से २२२ ७८७—८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६२, २६४, २६६, २६७, २६९ से ३७० और ३७२ से ३९० . ८०२—५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मनीपुर के रास्ते भारत में नागा विद्रोहियों का कथित प्रवेश . . ८५९—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८६१—६३

राष्ट्रपति का संदेश . . . . . ८६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण की जांच करने वाली समिति . . . . . . ८६४

प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . ८६४

राज्य सभा से संदेश . . . . . ८६४

सभा का कार्य . . . . ८६४–६५

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३—पुरस्थापित . . ८६५–६६

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . ८६६—८६

दैनिक संक्षेपिका .

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—2961 (Ai) LSD—11-5-63—160.

# लोक-सभा वाद-विवाद

## लोक-सभा

सोमवार, २५ फरवरी, १६६३

६ फाल्गुन १८८४ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**लद्दाख से चीनियों का हटना**

+
*१०५. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम
श्री स० चं० सामन्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह
श्री विभूति मिश्र :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी लद्दाख से हट गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों से ; और

(ग) क्या वहां से चीनियों के हट जाने के बारे में चीन सरकार से अब तक कोई सूचना मिली है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). हमें जो सूचना मिली है, उसके अनुसार चीनियों ने दावा किया है कि उनकी सेनाएं लद्दाख में उस



2857 LSD—1.

रेखा के पूर्व में हट गई हैं, जिसे वे "वास्तविक नियंत्रण रेखा" (लाइन ग्राफ एक्चुग्रल कन्ट्रोल) कहते हैं।

(ग) चीन की सरकार ने सूचना दी थी कि उनकी सेनाएं उन इलाकों से २० किलोमीटर दूर हट गई हैं जो पश्चिमी क्षेत्र में कथित "वास्तविक नियंत्रण रेखा" के पूर्व में हैं।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : जिस सीमा की रेखा को हमने बताया था कि यहां तक चीन की फौजें रहनी चाहियें, उससे कितनी ग्रधिक सीमा चीनी फौजें दबाये हुए हैं ग्रौर वापिस नहीं गई हैं? एक्चुग्रल लाइन ग्राफ कंट्रोल जिसे वे कहते हैं वे हमारी सीमा के कितनी भीतर तक है ग्रौर उससे हटने के लिए चीन सरकार क्या कह रही है?

**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा ग्रणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं समझा नहीं ग्रापकी बात। हमने यह कहा था कि वे ८ सितम्बर की लाइन पर चली जायें। ८ सितम्बर की लाइन कोई सीधी लाइन नहीं थी। वह घूमती घामती थी। उसे नापें तो कहीं से तो वे तीस किलोमीटर पीछे चले गये हैं, कहीं से ग्रठारह, कहीं से कम कहीं से ज्यादा। किधर से नापें, देखा जाता है। इस वक्त जो हालत है वह यह है कि कोलम्बो तजवीजों को उन्होंने मंजूर नहीं किया है। वे हट तो गए हैं उन सब जगहों से लेकिन वे इस पर ऐतराज करते हैं कि हमारे ग्रड्डे वहां कायम हों।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : कोलम्बो सम्मेलन ने जिन प्रस्तावों को पेश किया था ग्रौर जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था, उस सम्बन्ध में चीन सरकार के कौन-कौन से ऐतराज बाकी हैं ग्रौर हमारी सिविल पोस्ट्स कायम हो सकी हैं या नहीं जहां से चीनी फौजें हट गई हैं?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लद्दाख की निस्बत ग्राप कह रहे हैं? इसी का तो मैंने जवाब दिया है।

†**श्री हेम बरुग्रा** : क्या यह सच है कि चीन ने इस विसैन्यीकृत क्षेत्र में हमारे द्वारा ग्रसैनिक ग्रथवा सैनिक चौकियां स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ग्रापत्ति की है ग्रौर यदि हां, तो लद्दाख में चीनियों द्वारा खाली किये गये इन क्षत्रों की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या उन क्षेत्रों पर किसी का ग्रधिकार नहीं है ग्रथवा हमारा ग्रसैनिक नियंत्रण उन पर है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चीनियों ने बहुत सा ग्रौर संभवतः वह समस्त क्षेत्र खाली कर दिया है जिसके खाली करने का उन्होंने वचन दिया था, परन्तु बिल्कुल सही स्थिति बताना कठिन है। फिर भी दक्षिणी भागों में उनके गश्ती दल ग्राते हैं ग्रौर उनके द्वारा खाली किये गये ग्रधिकांश भागों में हमने ग्रभी तक कोई भी ग्रसैनिक चौकी नहीं स्थापित की है।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न यह है कि क्या वे हमें चौकियां बनाने से रोक रहे हैं? इसका उत्तर दिया जाना चाहिये।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : कोलम्बो राष्ट्रों ने सुझाव दिया था कि चीनी सेनाओं को वर्तमान स्थिति से २० किलोमीटर पीछे हट जाना चाहिये। क्या वे इस सुझाव के अनुसार पीछे हट गये हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे वहां से २० किलोमीटर पीछे हट गये हैं और वह क्षेत्र विसैन्यीकृत गलियारा कहलाता है। वे उसके परे हैं। परन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया था, इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में हमने अभी तक कोई असैनिक चौकियां नहीं स्थापित की हैं।

†**श्री बसुमतारी** : लद्दाख के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा कि चीनियों ने कोलम्बो प्रस्तावों को लिखत में स्वीकार नहीं किया है परन्तु फिर भी क्या वे वहां तक हट गये हैं जिसे कि प्रधान मंत्री ने हमारे लिये हितकर बताया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

इस का जवाब दे दिया गया है।

**डा० गोविन्द दास** : अभी भी क्या चीनी लद्दाख से हट रहे हैं या उनका यह हटना अब बन्द हो गया है और अब नहीं हट रहे हैं?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जिस ज़मीन से वे हटने वाले थे बीस किलोमीटर, वह तो हट चुके हैं। अब अपनी उस लाइन से पीछे हट रहे हैं या जमे हुए हैं, मैं नहीं कह सकता हूं। वह तो अलग बात है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : लद्दाख में नेफा क्षेत्र से भिन्न नीति अपनाये जाने के क्या कारण हैं? नेफा में हमने उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया है; हमने चीनी सेनाओं द्वारा खाली किये गये उन क्षेत्रों में अपने असैनिक अधिकारियों और गश्ती दलों को भेजा है। परन्तु लद्दाख में प्रधान मंत्री ने बताया कि हमने वैसा नहीं किया है। इस भिन्न नीति अपनाने के क्या कारण हैं? क्या हमको लद्दाख में वैसा करने से रोका गया है जैसा कि हमने नेफा में किया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें किसी ने नहीं रोका है। वास्तव में कुछ स्थानों में हम आगे बढ़ गये हैं और इस सम्बन्ध में समस्त कार्रवाई का निर्णय पूर्णत: सैनिक अधिकारियों के हाथ में है।

†**श्री रंगा** : क्या इसका मतलब यह है कि सरकार ने सेना से सलाह-मशविरा किया था और उसे खाली किये गये क्षेत्र पर कब्ज़ा करने की स्वतंत्रता दे दी है और कब्ज़ा करने तथा चौकियों की स्थापना का निर्णय सैनिक प्राधिकारी ही करेंगे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह वास्तव में सैनिक मामला है जिसका निर्णय वही करेंगे। इसमें स्वतंत्रता देने का कोई प्रश्न नहीं है। वे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मामले की चर्चा अवश्य करते हैं परन्तु निर्णय करना उन्हीं के हाथ में है।

†**श्री रंगा** : कुछ समझ में नहीं आया।

**डा० मा० श्री अणे** : क्या यह समझना ठीक होगा कि किन्हीं सैनिक कारणों से उस क्षेत्र पर कब्ज़ा नहीं किया जा रहा है और हमने किसी को ऐसा कोई वचन नहीं दिया है कि अन्तर्कालीन अवधि में हम उस स्थान पर कब्ज़ा नहीं करेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : जहां तक चीन का सम्बन्ध है, कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में दो शर्तें हैं। एक शर्त है सेनाओं का मैकमोहन सीमान्त तक हटाया जाना और दूसरी शर्त है उनके द्वारा लद्दाख में खाली किये गये क्षेत्र में चौकियों का नियंत्रण। चीनी अपनी चौकियों को कायम रखना चाहते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि वे १९५९ के पूर्व भी वहां थे और हमने जो अन्य चौकियां स्थापित की थीं वे १९५९ के बाद स्थापित की गई थीं इसलिये हमें उनको छोड़ देना चाहिये। चीनी इस आधार पर ही कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वास्तव में यही विवाद का विषय है।

†**श्री रंगा** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या हमने अपनी सेना को यह स्पष्ट बता दिया है कि यदि मौसम ठीक रहे तो उन क्षेत्रों पर यथाशीघ्र कब्जा कर लिया जाना चाहिये जिनको चीनियों ने खाली किया है, चाहे उसके आगे हम भले ही न जा सकते हों ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम आगे बढ़े हैं और हमने कई स्थानों पर असैनिक चौकियां स्थापित की हैं, परन्तु मुख्यतः यह सैनिक मामला है। जहां तक सेना को स्पष्ट बताने का सम्बन्ध है, इन मामलों का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता है। वे समय-समय पर विदेश सचिव अथवा अन्य अधिकारियों से मिलते हैं और उनके साथ इसकी चर्चा करते हैं। वास्तविक निर्णय सेना के हाथ में ही है।

**मरमागाओ बन्दरगाह**

+
†*१०६. { **श्री सुरेन्द्रपालसिंह** :
**श्री गोकर्ण प्रसाद** :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मरमागाओ बन्दरगाह के विकास के प्रश्न की जांच करने के लिए कुछ समय पहले एक जांच समिति बनाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम रहा ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) समिति का प्रतिवेदन अभी सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार से यह कहा है कि वह पत्तन उसे सौंप दिया जाये ताकि उसका भारत के पश्चिमीतट पर नौसेना के बड़े अड्डे के रूप में विकास किया जा सके ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : प्रतिरक्षा मंत्रालय, परिवहन तथा संचार मंत्रालय और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के एक अध्ययन दल ने इस मामले का अध्ययन किया था। प्रतिरक्षा मंत्रालय उसका नौसेना के अड्डे के रूप में विकास करना चाहता है। परन्तु परिवहन तथा संचार मंत्रालय का यह विचार है कि वह असैनिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये अधिक उपयोगी होगा। अतः हम दोनों मंत्रालयों के तर्कों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इस पत्तन का विकास इस प्रकार किया जाए कि दोनों की मांगें पूरी हो सकें।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस मामले में निर्णय कब तक हो जायेगा ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : बहुत शीघ्र।

## कोलम्बो प्रस्ताव

+

†*१०७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कोया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री कजरोलकर :
श्री हेडा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन सीमा समझौते के बारे में कोलम्बो प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है और यदि हां तो क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस मामले में चीन की अन्तिम प्रतिक्रिया क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) भारत सरकार ने कोलम्बो प्रस्तावों की पूर्ण स्वीकृति की सूचना लंका की प्रधान मंत्री को दे दी है।

(ख) भारत सरकार को इन प्रस्तावों के संबंध में चीन की सरकारी प्रतिक्रिया के बारे में अभी तक कोई निश्चित सूचना नहीं मिली है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमारे कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के पश्चात् चीन के रवैये के संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? हमने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है और चीनियों ने उनको स्वीकार नहीं किया है। हम नहीं जानते कि वे क्या करना चाहते हैं। क्या उनके साथ लाभकारी बातचीत होने की कोई संभावना है अथवा हमें निरन्तर प्रतीक्षा करते रहना होगा? चीन के हमारे इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद के रवैये के संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमारी प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं है। हम वह करते जा रहे हैं जो सामान्यत: संभव है। लेकिन जाहिर है कि यदि चीन उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करता तो वे व्यर्थ होंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि चीन इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करता है तो हम उसकी स्वीकृति के लिये कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे। यह प्रश्न का एक भाग है। स्थिति इस प्रकार है। देश में बहुत असंतोष व्याप्त है। यदि हम बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहेंगे तो वह हमारे लिये घातक होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम चीन के नए हमले का सामना करने अथवा उनसे अपना राज्यक्षेत्र खाली कराने की तैयारी कर रहे हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किसी बात के लिये प्रतीक्षा करने का कोई प्रश्न नही है। हम प्रतिरक्षा संबंधी तैयारी करते हैं और आवश्यक कदम उठाते हैं। हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं है।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : कोलम्बो प्रस्ताव जो भारत सरकार के सामने आये उन के बारे में ख्याल किया जाता था कि चीन ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब मालूम हो रहा है कि चीन उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। राज्य मंत्री महोदय ने बतलाया कि अभी चीन से सरकारी तौर पर कोई चीज़ नहीं मालूम हो सकी है, केवल अखबारों में छप रहा है कि चीन उनको स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस में कहां तक तथ्य है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार और सीलोन सरकार में क्या लिखा पढ़ी हो रही है।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चीन की सरकार की तरफ से मुख्तलिफ बयानात हुए हैं। उन से ऐसा मालूम होता कि है कि वह उनको स्वीकार नहीं कर रही है। कोई जाब्ते की सूचना हमारे पास नहीं आई है, न इस सिलसिले में चीन से हमारा कोई पत्रव्यवहार हुआ है। जो हुआ है वह कोलम्बो के जरिये से ही हुआ है। कोलम्बो वाले कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

उन से हमारा ताल्लुक है। हम उन से कहते हैं। वह भी उन से बतलाते हैं। उन को मालूम होना चाहिये कि उन का क्या फैसला हो रहा है।

**श्री यशपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐबनार्मल हालात में हमारे प्रधान मंत्री नार्मली क्यों मूव कर रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : ऐबनार्मल हालात में प्राइम मिनिस्टर साहब नार्मली क्यों मूव कर रहे हैं, इस का क्या जवाब हो सकता है?

**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : भारत चीन विवादास्पद सीमा रेखा के विषय में क्या हमारी सरकार सेना से निवृत्त अथवा सेना में विद्यमान सेनापतियों से परामर्श करती रहती है?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रश्न को पूरा समझा नहीं, इस लिये जवाब क्या दूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी पूरी तरह नहीं समझा।

**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या भारत सरकार इस रेखा के झगड़े के बारे में अपने मिलिटरी के रिटायर्ड और आन ड्यूटी जनरलों से परामर्श करती रहती हैं या नहीं?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत सरकार का काम है कि वह अपने मिलिटरी सलाहकारों से हर वक्त सलाह ले। बल्कि भारत सरकार के एक खास नुमाइन्दे जो कि डिफेन्स मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, वह डिफेन्स मिनिस्ट्री से रोज मिलते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। वह हैं ही डिफेन्स मिनिस्ट्री में। मैं भी मिलता रहता हूं। जो पुराने हमारे आफिसर्स हैं, रिटायर्ड उन्हें हम ने मिलिटरी अफेअर्स कमेटी में रक्खा है। इस में जो पुराने अफसरान हैं और जो आज कल के चीफ आफ स्टाफ हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वह मिलते रहते हैं, मश्वरा करते रहते हैं और एक दूसरे की राय मालूम करते हैं।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : जैसा प्रधान मंत्री जी ने संसद् के पिछले अधिवेशन में कहा था, और समाचारपत्रों में भी कुछ ऐसे समाचार प्रकाशित हुए थे, श्रीमती भंडारनायके के द्वारा उन्होंने कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में चीन से कुछ और स्पष्टीकरण मांगे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण सरकार के पास आये हैं, और यदि आये हैं तो क्या प्रधान मंत्री उन से सन्तुष्ट हैं?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं, हम ने कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है। जब कोलम्बो प्रस्ताव आये थे उस वक्त उन्होंने सफाई पेश की थी। हम ने उन से कोई बहस नहीं की थी। हम ने उन से पूछा था कि उसके माने क्या हैं। उन्होंने बतलाया। उसे हम ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम ने कोई बहस नहीं की। हम ने खाली लिखा कि वह हमें बतला दें कि चीनी जवाब क्या है।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : कोई उत्तर आया है या नहीं?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आये तो कई उन के पत्र और तार हैं, लेकिन यह बात साफ नहीं हुई।

†श्री हरि विष्णु कामत : चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की और हमने कोलम्बो प्रस्तावों की स्वीकृति की घोषणा की। क्या गत मास कोलम्बो राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में हुई चर्चा के दौरान चीनियों के साथ बात करने के लिये चीन में बन्द भारतीय युद्धबन्दियों की मुक्ति एवं पुनर्वशावर्तन की पूर्वशर्त रखी गई थी?

†अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न बात है जो इस प्रश्न के अन्तर्गत उत्पन्न नहीं होती है।

†श्री ह० प० चटर्जी : क्या वर्तमान स्थिति में चीन सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक होने की कोई दूर की भी संभावना है?

†अध्यक्ष महोदय : दूर की संभावना के संबंध में कोई कैसे बता सकता है।

श्री बड़े : जैसा अभी प्रेस में भी आया है, क्या यह सच है कि कोलम्बो प्रपोजल्स के ऊपर फिर कैरो में मीटिंग होने वाली है, और क्या शासन के पास इस की कोई इन्फार्मेशन आई है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं आई है?

†श्री हेम बरुआ : चूंकि चीनी मंत्रि परिषद् के सभापति श्री लिऊ-शाओ-ची ने यह कहा बताते हैं कि "हम भारत पर एक बार हमला कर चुके हैं और यदि वह कुछ सीखेगा नहीं तो हम उस पर बार बार हमला करेंगे" इसलिये में यह जानना चाहता हूं कि क्या चीन के इस रवैये को देखते हुए सरकार कोलम्बो प्रस्तावों के संबंध में पुनर्विचार करेगी?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार यह नहीं समझती कि इन दो बातों में क्या संबंध है।

†श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या कोलम्बो राष्ट्रों ने इन प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में कोई अंतिम तारीख निश्चित की है जिसके बाद वे रद्द हो जायेंगे?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : अंतिम तारीख निश्चित करने का कोई प्रश्न नहीं है। वे हमारे मार्ग में किसी भी प्रकार बाधक नहीं हैं। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं।

†श्री हेडा : क्या हमने कोलम्बो राष्ट्रों को इस बात का संकेत किया है कि हम उन प्रस्तावों के संबंध में चीन की प्रतिक्रिया की निरन्तर प्रतीक्षा करते रहेंगे?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वैसा हमने नहीं किया है। चीन के उन प्रस्तावों को स्वीकार करनें अथवा न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय वह हमारे मार्ग में बाधक नहीं है। चीन के प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर ही कुछ प्रतिक्रिया होगी अन्यथा नहीं।

†श्री नाथ पाई : हमने उन प्रस्तावों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है और चीन ने सिद्धान्तः और गत्यावरोध सा उत्पन्न हो गया है। क्या इन प्रस्तावों के प्रवर्तक इस गत्यावरोध को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न कर रहे हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इतना ही मालूम है कि वे आपस में और उनमें से कुछ चीन सरकार के साथ भी लिखापढ़ी कर रहे हैं।

†**श्री नाथपाई** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि हमारे उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने और चीन के न करने से जो गत्यावरोध उत्पन्न हो गया है क्या उसे दूर करने के लिये कोलम्बो राष्ट्र कोई प्रयत्न कर रहे हैं और इसका उत्तर दिया जा चुका है।

**श्री कमलनयन बजाज** : क्या प्रधान मंत्री महोदय इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि कोलम्बो प्रपोजल्स जो थे उन को ले कर सीलोन के प्रधान मंत्री जी पहले चीन गये । वहां पर उन के बारे में सारी बातचीत कर के बाद में वह वहां से यहां भारत आये । चीन ने सिद्धान्त रूप में उन्हें स्वीकार किया । यहां आने पर हमें जो कुछ उस में शंकाएं थीं वह हम ने पूछीं ....

**अध्यक्ष महोदय** : अब सारी हिस्ट्री न दुहराइये ।

**श्री कमलनयन बजाज** : मेरा सवाल इतना है कि जब कि वह चीन से प्रस्ताव लेकर मिल कर आयीं और प्रिंसिपल में वे वहां मंजूर हो गये और फिर यहां आने के बाद जो शंकाएं हमारी थीं उनका उन्होंने हमें स्पष्टीकरण और जवाब दे दिया और हमने उन स्पष्टीकरणों के साथ कोलम्बो प्रस्तावों को मंजूर कर लिया तो फिर चीन को उस से वापिस जाने की दरकार क्या थी और इसका कारण क्या है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यहां पूरे तीन दिन तक इस सम्बन्ध में बहस हुई है और सब समझाने की कोशिश की गई है । अब मैं कैसे जवाब दूं, चीन की तरफ से, जा कर खुद लिखिये चीन को ।

†**श्री बड़े** : यह कहना अति अनुचित है कि हमें उत्तर लेने के लिये चीन जाना चाहिये ।

†**श्री नाथपाई** : श्री बजाज के लिये यह चिन्ता का विषय नहीं क्योंकि दल का सचेतक है और प्रधान मंत्री जो उतर देते हैं उन्हें उनको मानना पड़ता है, किन्तु समूची सभा के लिये, प्रधान मंत्री का रवैया गलत है और आपत्तिजनक है जब वह किसी सदस्य को कहते हैं कि स्वयं जा कर सूचना प्राप्त कर लो । क्या वह मा० सदस्यों के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के लिये इस सभा के समक्ष उत्तरदायी नहीं हैं ? (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, यह उत्तर देने का अप्रत्यक्ष मार्ग है ।

†**श्री रंगा** : क्या इस से यह समझा जाए कि जब यह प्रधान मंत्री से आता है, तो सब कुछ पारित होगा ? यह ऐसे ही दिखाई देता है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह केवल विरोधी पक्ष का विशेषाधिकार है—सब कुछ पारित होगा, जहां संगत हो या असंगत ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : यदि यह विरोधी दल का विशेषाधिकार है ....

†**श्री हरि विष्णु कामत** : समूचा रवैया गलत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : उन को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये । क्या प्रधान मंत्री ने कोलम्बो शक्तियों को यह बताने का कभी कष्ट किया है कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हम ने प्रस्ताव मान लिये हैं और चीनियों ने नहीं माने, हम उन्हें ....

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस मामले में इतने क्रोध और आवेश का कोई कारण नहीं है । प्रश्न यह था कि चीनी क्यों विशेष रवैया अपना रहे हैं, कम से कम यही सारांश था । अब प्रधान मंत्री कहते हैं कि प्रश्न चीनियों से पूछा जाना चाहिये, न कि इस सरकार से । इतना ही हुआ है ।

†श्री नाथपाई : सरकार का क्या अनुमान है ?

†श्री हरि विष्णु कामत : हम सभा के नेता से अपेक्षा करते हैं कि वह उत्तम आदर्श स्थापित करें । वह नेता हैं । उन्हें हमारा मार्ग दर्शन करना है ।

†श्री हेम बरुआ : एक औचित्य प्रश्न है । प्रश्न काल का उद्देश्य सरकार से सूचना प्राप्त करना है और हमें सरकार से सूचना प्राप्त करने से सम्बन्ध है । यदि सरकार हमें सूचना नहीं देती तो सरकार को ऐसा नहीं चाहिये कि हमें किसी विदेशी सरकार से पूछने को कहे । क्या आप समझते है कि इन को ऐसा करना चाहिये ?

†अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । सरकार वही सूचना दे सकती है, जिसे रखने का इसे विशेषाधिकार है या जो वास्तव में इस के पास है । इस सरकार का यही उत्तरदायित्व है । अन्य सरकारों या चीन के पास जो जानकारी हो, वह यह सरकार नहीं दे सकती । मा० सदस्यों को यह बात अनुभव करनी चाहिये ।

†श्री उ० म० त्रिवेदी : औचित्य प्रश्न है कि आपने जो सुझाव दिया है उसका अर्थ यह है कि जो प्रश्न पूछा गया था वह असंगत था । यदि यह बात है, प्रश्न की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिये थी । किन्तु जब अनुमति दे दी गई है तो मा० प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बात उचित नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, अगला प्रश्न ।

### हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड

†

*१०८. { श्री सुबोध हन्सदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में 'टर्वोजेट इंजन'[१] का प्रथम रूप' तैयार हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने और परीक्षा की जाने की आशा है ?

†प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रथम रूप का निर्माण १९६३ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की अपेक्षा की गई है और उसके पश्चात् प्रयोग आरम्भ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१Turbojet Engine.

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस इंजन का डिजाइन भारतीय इंजीनियरों ने किया है अथवा क्या विदेशी विशेषज्ञों से कोई प्रविधिक सहायता ली जाएगी ?

†**श्री रघुरामैया** : यह सर्वथा देशी प्रयत्न है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस इंजन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पुर्जे हिन्दुस्तान विमान फैक्टरी में बनाये जाते हैं या विदेश से मंगवाये जाते है ?

†**श्री रघुरामैया** : हिन्दुस्तान विमान फैक्टरी में ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यह प्रयत्न कितनी देर से किया जा रहा है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं ठीक से नहीं कह सकता कि यह कब आरंभ हुआ था, किन्तु हम अब उस स्थिति पर आ पहुंचे हैं जहां पहला रूप पूरा हो जाएगा जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया गया है ।

**संयुक्त समिति द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा**

+

†*१०९. **श्री रा० गि० दुबे** :
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
**श्री भक्त दर्शन** :
**श्री भागवत झा आजाद** :
**श्री विश्राम प्रसाद** :
**श्री नि० रं० लास्कर** :
**श्री सरजू पाण्डेय** :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त समिति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों का, वहां की गरीबी तथा पिछड़ेपन के कारणों की जांच करने के लिये, दौरा किया था ;

(ख) क्या उच्च समिति ने कोई प्रस्तापनायें पेश की हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इसी प्रकार के दलों को देश के अन्य जाने हुये पिछड़े क्षेत्रों तथा चिरकालीन अकाल वाले क्षेत्रों का दौरा करने के लिये भेजने का है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त अध्ययन दल इस समय पहले से एकत्रित सांख्यकी का अध्ययन करने में तथा उन क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्ध रखने वाली कुछ नई जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित करने में लगा हुआ है ।

(ग) योजना आयोग के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : इस समिपि के सदस्य कौन थे और इस के निर्देश निबंधन क्या थे ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : उन को पहले तो इन क्षेत्रों में मजूरी, रोजगार और कम आय वर्ग के निर्वाह स्तरों, दूसरे द्रुतगामी आर्थिक विकास के उपायों विशेषकर औद्योगिक,

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन और संचार सा नों के विकास के कार्यक्रमों के द्वारा भूमि पर के भार को कम करना, और तीसरे १९६३–६४ में इन क्षे ों के विकास के लिये विशेष व्यवस्था सम्बन्धी बातों का अध्ययन करके प्रतिवेदन देना है।

†श्री रा० गि० दुबे : क्या सरकार बता सकती है कि क्या इस समिति ने कोई अन्तरिम सिफारिशें की है ?

†श्री के० रा० पट्टाभिरामन् : अध्ययन हो रहा है और उनकी सिफारिशें हमारे पास आती रही हैं। उन सब को शीघ्र मिलाया जाएगा और हमें आशा है कि सितम्बर तक अन्तिम रूप में प्रतिवेदन तैयार हो जाएगा।

†श्री पे० वेंकटासुब्बया : क्या अकाल रक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाद्य उत्पादन, और यदि हां, तो क्या सरकार देश के सदैव अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का अनुमान लगाने और उन क्षेत्रों में अकाल को समाप्त करने के लिये कुछ सहायता देने का प्रयत्न करने का विचार करती है ?

†श्री के० रा० पट्टाभिरामन् : अवश्य ही। गहरे कुएं उन स्थानों पर खोदे जा रहे हैं जहां खोदे जाने चाहियें। छोटे सिंचाई कार्यक्रम भी उन क्षेत्रों में किये जाते हैं जिनको उनकी शीघ्र आवश्यकता है।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या संयुक्त राष्ट्र के युनिसेफ संगठन के साथ किसी व्यवस्था के अधीन उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रदेशों में व्यवहारिक पौष्टिक तत्व कार्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस कायक्रम का ब्योरा क्या है ?

†श्री के० रा० पट्टाभिरामन् : उनका प्रारंभ में अध्ययन के तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से सम्बन्ध है। तब यह समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैलाया जाएगा ?

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या मा० मंत्री जी को विदित है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में अर्थात बुन्देलखंड क्षेत्र में कुछ पिछड़े हुये क्षेत्र हैं और क्या इस योजना का वहां भी विस्तार किया जाएगा ?

†श्री के० रा० पट्टाभिरामन् : उन्हें यह बात मालूम है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत से क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं और दक्षिण उत्तर प्रदेश में भी हैं। मैं समझता हूं कि मा० सदस्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग का उल्लेख कर रही हैं।

†कुछ माननीय सदस्य : दक्षिण उत्तर प्रदेश।

†श्री के० रा० पट्टाभिरामन् : और दक्षिण उत्तर प्रदेश।

श्री सरजू पाण्डेय : पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन जिलों का सरवे किया गया है, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और जोनपुर। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो ग्यारह जिले हैं, जो कि पिछड़े हुये कहे जाते हैं, उन के बारे में कोई जांच की जायगी या नहीं ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) : जो टीम वहां पर गई है, वह इस किस्म के सवालों पर गौर करेगी कि वहां की क्या समस्यायें हैं, क्या प्राबलम्ज़ हैं। वह उन की टाइप स्टडी करेगी। उस में से जो कुछ भी नतीजे निकलेंगे, जो भी कनक्लूज़न्ज़ होंगे, उनका अमल दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी किया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री म० ला० द्विवेदी** : द्वितीय और तीसरी पंच-वर्षीय योजनाओं में पिछड़े हुए क्षेत्रों की जांच-पड़ताल और वहां की ग़रीबी को हटाने के लिये योजना बनाई गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कमेटी जांच करने के लिये गई थी, वह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों गई और वह दूसरे पिछड़े हुये इलाकों में क्यों नहीं गई और वहां पर काम क्यों नहीं हो रहा है।

**श्री नन्दा** : देश के दूसरे प्रान्तों में भी इस किस्म का कुछ काम हो रहा है। दूसरे प्रान्तों से इस बारे में मसाला इकट्ठा करने के लिये कहा गया है, और वे कर भी रहे हैं, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड कहे जाने चाहियें, इसके क्या क्राइटेरिया होने चाहियें, क्या इण्डीकेटर्ज़ हैं। इस बारे में उन को बताया गया है और उस की बिना पर वह सूचना इकट्ठी कर रहे हैं। उन के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उस ढंग से बैकवर्ड डिक्लेयर किए गए हैं। उस के सिवा और भी कुछ न कुछ एन्क्वायरी हो रही है।

**श्री रा० शि० पाण्डेय** : मध्य प्रदेश में विशेष कर झाबुआ और सरगूजा, ये दो ज़िले ऐसे हैं, जहां पर आदिवासियों की दशा दयनीय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन के बारे में इस प्रकार की कोई कमेटी बनाई जायगी।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सवाल तो सिर्फ़ यू० पी० का है।

†**श्री न० रं० लास्कर** : प्रारंभ में अकले उत्तर प्रदेश को ही लेने तथा अन्य ज्ञात पिछड़े क्षेत्रों को न लेने का मुख्य कारण क्या है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस सवाल को तो यू० ी० तक ही रहने दीजिए।

**डा० महादेव प्रसाद** : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण के लिये कुछ टाइप निश्चित कर लिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस टाइप को निश्चित करने का आधार क्या था।

**श्री नन्दा** : यू० पी० गवर्नमेंट के साथ मश्वरा कर के ऐसा किया गया था।

†**डा० क० ल० राव** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में निर्धनता के कारण सर्व विदित हैं और आवश्यकता इस बात की है कि उनको दूर करने के उपायों को कार्यान्वित किया जाए ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है।

†**श्री बसुमतारी** : केवल उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों की ही जांच करने के लिये समिति बनाने के मुख्य कारण क्या हैं, तथा अन्य राज्यों के लिये क्यों समिति नहीं बनाई गई जब कि वहां बहुत से पिछड़े क्षेत्र हैं ?

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्** : योजना आयोग ने सब राज्यों से पत्र-व्यवहार किया। नौ राज्यों ने अभी उत्तर नहीं दिया। उनसे पूछा गया था (१) कौन से पिछड़े क्षेत्र हैं और (२) वे किन क्षेत्रों को ऐसा समझते हैं जिनको योजना आयोग या राज्यों से तुरन्त सहायता की आवश्यकता है।

**डॉ० गोविन्द दास** : अभी मंत्री जी ने बताया कि इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राज्यों को लिखा गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि किन राज्यों ने अभी तक उस का उत्तर दिया है और जो भिन्न-भिन्न राज्य हैं, उन में से कितने राज्य ऐसे हैं, जहां इस प्रकार के पिछड़े हुए क्षेत्र मौजूद हैं ?

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्** : अभी तक आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और जम्मू व काश्मीर से उत्तर नहीं आये।

---

†मूल अंग्रेजी में

## विदेशी वायुसेना विशेषज्ञ दल की भारत यात्रा

+

†*११०. श्री सुरेन्द्रपालसिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा ग्राजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री वाजी :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री कोप्पन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री शिव मूर्त्ति स्वामी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री कजरोलकर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है क संयुक्त राज्य ग्रमेरिका का ग्रौर राष्ट्रमंडल के वायुसेना के विशेषज्ञों का एक दल भारत ग्राया था ;

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनके यहां आने का क्या प्रयोजन था; और

(ग) क्या उसने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवतराव चह्वाण)** : (क) : जी हां।

(ख) भारत की वायु सुरक्षा की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि नहीं कि सरकारी प्रवक्ता द्वारा कम स्पष्टता से परिभाषिक 'वायु छाता' संबंधी हमारी अनौपचारिक बातचीत इस देश में भ्रांति का वातावरण फैलाने के लिए उत्तरदायी है और कुछ लोग इस से लाभ उठाने के उत्सुक हैं । और यदि ऐसी बात है तो सरकार ने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ताकि कोई भ्रांति पैदा न हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके संबंध में एक वक्तव्य पहले दिया जा चुका है ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है और उससे स्थिति का स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : जब यह दल या मिशन अपनी रिपोर्ट देगा तो क्या यह संबंद्ध सरकारों को दी जाएगी, जिन्होंने यह सद्भावना मंडल भेजा था, या भारत सरकार को भी दी जा जाएगी ?

†**श्री यशवतराव चह्वाण** : ये मिशन अपनी सरकारों को अपनी रिपोर्ट देंगे, इस सरकार को नहीं ।

†**श्री रंगा** : मैं समझता हूं कि यह बात नहीं है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या हम स्वयं एक स्थायी बुनियादी वायु संरक्षण प्रणाली की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसे हम उन विदेशी शक्तियों के साथ किसी प्रकार के सन्दिग्ध आर्थिक समझौते के बिना, जो हमारी आवश्यकताओं के संबंध में अपनी निजी सरकारों को रिपोर्ट देनी प्रतीत होती हैं, अपने सीमित साधनों से चला सकें ।

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : निश्चय ही, हम अपनी आवश्यकताओं के लिये कार्रवाई कर रहे हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या इस दल को हमारे वायु संरक्षण की अल्पकालीन एवं दीर्घ कालीन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का काम सौंपा गया था ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : साधारण तया, वे उन आवश्यकताओं पर विचार करने के लिये आये थे, जो हमने बताई थीं, और मैं समझता हूं कि उस में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों आवश्यकताएं शामिल हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या हमने अपनी आवश्यकताएं निर्धारित कर ली हैं या उनका अनुमान लगा लिया है और इस दल को दे दी हैं और कब तक इस बात चीत के पूरा होने की संभावना है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : साधारण तया इस दल की चर्चाओं में हमारा अनुमान भी शामिल था। कितना समय लगेगा यह नहीं कहा जा सकता।

†**श्री प्र० के० देव** : कुछ समय पूर्व हम ने सुना कि चीन अणु बम का विस्फोट करके 'आण्विक क्लब' में शामिल हो रहा है। क्या विदेशी वायु मिशन ने इस पहलू पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मुख्य प्रश्न से अणुबम के प्रश्न पर चले गये हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : भारतीय विमान बल के लिये अपनी आवश्यकताओं की सूची बनाते समय क्या हमने इस बात का ध्यान रखा है कि पाकिस्तानी वायुबल उपकरण, अर्थात् राडार और अन्य सामान, अमरीकी सैनिक सहायता द्वारा इतना अधिक तैयार किया गया था, कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर अनधिकृत उड़ाने कर सका था ? क्या हमने इस बात का ध्यान रखा है और इस प्रकार हमारी आवश्यकताओं के बारे में अमरीकी मिशन का ध्यान आकर्षित किया गया है।

†**श्री यशवत राव चह्लाण**: यह प्रश्न इस दल की बातचीत में नहीं आया।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह सहायता किस आधार पर प्राप्त होगी, क्या यह उधार पट्टा आधार पर होगी या युद्ध संबंधी कार्रवाई के आधार पर, या वित्तीय आधार पर या किसी दूसरे आधार पर ?

†**श्री यशवंत राव चह्लाण** : ये अग्रतर ब्योरे की बातें हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अगले प्रश्न में आ रहा है ।

†**तिरुमल राव** : क्या यह सच है कि हमारा विमान बल अफसर आगन्तुकों या अमरीका और राष्ट्र मंडलीय विमान अधिकारियों के साथ भली प्रकार मिले हुए थे और यदि हां, तो क्या वे भारत सरकार को भी कोई रिपोर्ट पेश करेंगे ?

†**श्री यशवंत राव चह्लाण** : अवश्य, वे समय समय पर हमें बतलाते रहे कि बातचीत में क्या हो रहा है।

## अमरीकी सैनिक सहायता

+

†*१११ {
**श्री प्र० चं० बरुआ** :
**श्री म० ला० द्विवेदी** :
**श्रीमती सावित्री निगम** :
**श्री स० चं० सामन्त** :
**श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
**श्री हेम राज** :
**श्री बृज राज सिंह** :
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
**श्री रामेश्वर टांटिया** :
**श्री हेडा** :
**श्री बड़े** :
**श्री रघुनाथ सिंह** :
**श्री पें० वेंकटासुब्बया** :
**श्री कजरोलकर** :
}

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के तारांकित **प्रश्न संख्या** ३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के संचालक, श्री बेल, हाल में नई दिल्ली आए थे, तथा उन्होंने अमरीकी शस्त्र सहायता के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन बातों पर चर्चा हुई ; और

(ग) यदि इस चर्चा की दृष्टि से कोई निर्णय किया गया हो तो वह क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण)** : (क) श्री बैल ने, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के निदेशक का कार्यभार सम्भालने पर, अमरीका से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों को आर्थिक समस्याओं से परिचित होने के लिये विभिन्न देशों की यात्रा की। वह जनवरी, १९६३ में भारत भी आये। यहां पर उनकी बातचीत मुख्य रूप से भारत को आर्थिक सहायता के बारे में थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मि० बैल के अलावा क्या कोई दूसरा मिशन फौजी सहायता के लिए या हवाई सहायता के लिए भारत में आया था ? और यदि हां, तो उसने क्या-क्या बातें देखीं और क्या निर्णय दिया और क्या भारत सरकार की जरूरतें उस से पूरी हो सकेंगीं ?

**श्री यशवंतराव चह्वाण** : मैं वास्तव में इसे नहीं समझता, क्योंकि . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : सवाल आप ने बैल के बारे में किया और अब आप उसको छोड़ कर दूसरे पर जाते हैं कि उन्होंने क्या सिफारिशें कीं ?

**श्री म० ला० द्विवेदी** : यह यू० एस० मिलिट्री एड के बारे में सवाल है। इस के अन्दर हम दूसरी बातें भी पूछ सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने जो सवाल में रेफ्रेंस दिया है ३७७ नम्बर सवाल का वह भी बैल की बाबत है और अब . . . . . .

**श्री म० ला० द्विवेदी** : अच्छा मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। मि० बैल के आर्थिक सम्बन्ध में जो सलाह दी है, वह क्या है और यू० एस० ए० से इस संबंध में हमें क्या सहायता मिल सकेगी ?

†**श्री यशवंतराव चह्वाण** : जहां तक श्री बैल का संबंध है, बातचीत मुख्य रूप से वित्त मंत्री के साथ थी। संभवतः प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये था। वास्तव में श्री बैल ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ कोई बातचीत नहीं की। जहां तक वायु सहायता का संबंध है, मैं कुछ मिनट पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

**श्री बड़े** : क्या यह सच है कि मि० बैल ने भारत के खिलाफ रिपोर्ट दी है और कहा है कि जो कुछ दिया जाता है उसका भारत बराबर उपयोग नहीं करता है ?

**श्री यशवंतराव चह्वाण** : मुझे कोई सूचना नहीं है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मि० बैल ने क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के किसी अधिकारी से भी बातचीत की कि उनको क्या सहायता की आवश्यकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों के अलावा, यदि हां, तो क्या परामर्श दिया ?

†**श्री यशवंतराव चह्वाण** : रक्षा मंत्रालय से कोई बातचीत नहीं हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

**चीन-पाक सीमा करार**

+

*११२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री भगवत झा आजाद :**
**श्री रा० गि० दुबे :**
**श्री सोनावने :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री गुलशन :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री बड़े :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री कजरोलकर :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **प्रधान मंत्री** २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और चीन के बीच हुए सीमा करार के बारे में भेजे गए विरोधपत्र का उत्तर पाकिस्तान सरकार से मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सीमा करार का ब्यौरा उपलब्ध है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी नहीं। अभी तक औपचारिक उत्तर नहीं आया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ?

(ग) जी नहीं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं समझता हूं कि यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान का विदेश-कार्य मंत्री यह करार करने के लिये चीन जा रहा है। इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** भारत सरकार की प्रतिक्रिया स्पष्टतः इसके विरुद्ध है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यात्रा का उद्देश्य ठीक है या यात्रा का समय ठीक है। हम ने यह बात पाकिस्तान सरकार को पूर्णतया साफ कर दी है और यद्यपि उन्होंने हमें कोई औपचारिक उत्तर नहीं भेजा, हमारे उच्च

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुक्त ने पाकिस्तान के विदेश कार्य मंत्री से मिल कर यह बात पूर्णतः स्पष्ट कर दी थी और विदेश कार्य मंत्री ने उसे किसी प्रकार का उत्तर दिया ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** वास्तव में, उनके कार्य से उत्तर आ गया है । इस से अधिक जोरदार उत्तर नहीं दिया जा सकता था। पाकिस्तान के साथ उसी विषय पर कोई बातचीत जारी रखने में क्या युक्ति युक्तता है, जिसके बारे में पाकिस्तान पूर्णतया हमारी अवहेलना कर रहा है और एक ओर चीन के साथ सांठ-गांठ कर रहा है और दूसरी ओर एशियाई देशों में हमारे विरुद्ध जोरदार प्रचार कर रहा है ? कल उनके एक मंत्री द्वारा सीलोन में कुछ कहा गया बताया गया है ; उन्होंने यही काम अफ्रीका में किया है। इन परिस्थितियों में क्या प्रधान मंत्री यह समझते हैं कि उनके साथ बातचीत जारी रखना उचित है, जिसका हमारे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे लिये युक्तियुक्तता का संतुलन करना जरा कठिन है । मैं समझता हूं कि मा० सदस्य इस बात को चुनौती देने में ठीक हैं, जो पाकिस्तान ने ऐसे समय पर की है । उन्होंने जो कहा है उस में निश्चय ही कुछ सार है । फिर भी, हमें सब बातों पर मिल कर सोचना पड़ता है, हम इस पर विचार कर रहे हैं और जैसी परिस्थिति होगी, हम तदनुसार फैसला करेंगे । किंतु मैं इस समय इसके बारे में कोई पक्की बात नहीं कह सकता ।

†**श्री सोनावने :** यह बताया गया है कि पाकिस्तान इस महीने की २७ तारीख को चीन के साथ एक सीमा सन्धि करने वाला है । क्या हमने अपने मित्र देशों पश्चिमी देश और रूस आदि को इस बात से अवगत करा दिया है और इसके संबंध में उनकी राय पूछी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री नाथ पाई ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या सरकार को निश्चय है कि यह तथाकथित समझौता, जो वास्तव में ऐसे दो देशों के बीच अवांछनीय गठबंधन है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है, उस भूमि की सीमा करने तक सीमित है, जिसे वे अपना क्षेत्र कहते हैं, किन्तु जो भारतीय क्षेत्र है, और दूसरे, इस संधि में इन दोनों आक्रमण कर्ताओं के बीच भारत के विरुद्ध भविष्य में इकट्ठी कार्रवाई के लिये कोई गुप्त खंड नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें इस संधि के बारे में कुछ पता नहीं और मैं मा० सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं । जो कुछ कहा गया है वह यह है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार सीमा का सीमाबंधन कर रहे हैं।

†**श्री प्र० के० देव :** आज के समाचार पत्र में कहा गया है कि तथा कथित पाकिस्तान सिंक्यांग सीमा पर ४१ खम्भे बनाये जाएंगे । निर्माण किस स्थान या त्रिसीमा से आरम्भ होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री उ० मू० त्रिवेदी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : उन के विदेश-कार्य मंत्री की पीकिंग यात्रा के प्रति हमारी असहमति व्यक्त करने को दृष्टिगत रखते हुए, क्या हम ने पाकिस्तान को बता दिया है कि काश्मीर प्रश्न सम्बन्धी हमारी सम्पूर्ण भावी बातचीत तुरन्त समाप्त कर दी जानी चाहिये ?

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जा चुका है कि सरकार विचार कर रही है कि क्या करना चाहिये ?

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने पाकिस्तान को अपने विरोध पत्र में कहा है कि सरकार ऐसे सीमा समझौते को पाकिस्तान का अमैत्रीपूर्ण कार्य मानेगी ? क्या पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के साथ रावलपिंडी या कराची में हुई चर्चाओं के दौरान में प्रत्यक्षतः वा अप्रत्यक्षतः यह मामला उठाया गया था ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां। हमने ऐसा किया है और यह भी कहा है कि वे जो भी समझौता करेंगे, हमारे द्वारा मान्य नहीं होगा ।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या हाल ही में किसी समय अमरीका और इंगलैंड की सरकारों का पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनाई गई इस नीति के बारे में भारत सरकार को मालूम हुआ है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : अमरीका और इंगलैंड की सरकारें काफी अच्छी तरह जागरूक हैं और वे भली भांति जानती हैं कि क्या हो रहा है। हमारे द्वारा उन को बतलाने की बात नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उनके द्वारा हमें बताने के बारे में है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि किस-किस को बताना चाहिये। किन्तु इस के बारे में उनके आज उपस्थित प्रतिनिधियों से बात चीत हुई है ।

†डा० मा० श्री अणे : जहां तक पाकिस्तानी प्रतिनिधि, श्री भट्टो का व्यवहार उन क्षेत्रों पर, जिनके बारे में बातचीत चल रही है, भारतीय स्वायत्तता को पूर्णतया अस्वीकार करना है, मैं जानना चाहता हूं कि अब कौन सी सांझी आधार हैं जिस पर दोनों पक्ष अब बात कर कर सकते हैं, इस बात को छोड़ कर कि इच्छा मात्र है ......

†अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न दूसरे रूप में पूछा गया था ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : काश्मीर की बहुत सी समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ भी मध्य में आ जाता है क्योंकि जब तक हमारा केस वहां है। क्या हम ने चीन और पाकिस्तान के भी इस करार के सम्बन्ध में विरोधपत्र भेजे जाने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कुछ लिखा है, यदि लिखा है, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : इस संबंध में हमारे जो नुमांइदे हैं, उन्होंने सुरक्षा परिषद् के सामने ४ मई को और २२ जून, १९६२ को हमारे जो इस बारे में खयालात हैं, वे रखे थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## नेफा में असैनिक प्रशासन

\+

*११३. श्री प्र० के० देव :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री हेडा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री हेमराज :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० स० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में चीनियों द्वारा खाली किये गये ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिन में असैनिक प्रशासन कायम हो गया है ;

(ख) चीनियों द्वारा क्या किसी प्रकार की रुकावट डाली गयी है ; और

(ग) उन खाली किये गये क्षेत्रों में चीनियों द्वारा क्या अपने जासूस भी छोड़े गये हैं ?

**†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) नेफा से चीनियों के चले जाने के बाद निम्नलिखित स्थानों पर असैनिक प्रशासन पुनः स्थापित कर दिया गया है :—

बोमडीला
तवांग
नाचो
मेचुका

---

†मूल अंग्रेजी में

म्नी गांग
गेलिंग
वालोंग
किबितु

(ख) नेफा में असैनिक प्रशासन की पुनः स्थापना में चीनियों द्वारा डाली गई रुकावट की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

(ग) नेफा में चीनियों द्वारा खाली किए गए क्षेत्रों में उनके द्वारा रखे गये जासूसों के संबंध में सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

†**श्री प्र० के० देव** : उत्तर से ऐसा मालूम होता है कि हमारा असैनिक प्रशासन आक्रामक की दया पर है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उत्तर में ऐसी कोई बात नहीं है।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या असैनिक प्रशासन की स्थापना का यह अर्थ है कि हमने वहां पर शांति तथा व्यवस्था स्थापित करली है और लगान वसूल करना शुरू कर दिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां। वैसा ही सामान्य असैनिक प्रशासन है जैसा ८ सितम्बर से पहले था।

†**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि हम अपने सैनिक नेफा में नहीं भेज सकते हैं इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार असैनिक प्रशासन तथा असैनिक जनता की सुरक्षा के लिये कोई कार्यवाही करने का है अथवा उसने की है यदि चीनी वापस लौटते हैं तो ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह एक काल्पनिक प्रश्न है कि चीनी यदि आक्रमण करें तो क्या कदम उठाने चाहिय।

†**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि हमने नेफा में अपना असैनिक प्रशासन बना लिया है तथा अपने सैनिकों को वहां नहीं भेज रहे हैं इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि यदि चीनी वहां पर आते हैं तो वहां की जनता की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं क्योंकि चीनियों द्वारा वहां पर छोड़े गये जासूस आदि विद्रोही कार्यवाही में अब भी संलग्न हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने कितनी ही बातें कहीं कि यह होगा और हमको यह करना चाहिये। असैनिक प्रशासन में पुलिस, सशस्त्र पुलिस आदि सभी होती हैं। वह वहां पर बिना किसी कठिनाई के अपना काम कर रहे हैं। परन्तु वह जानना चाहते हैं कि यदि चीनी पुनः आक्रमण करें तो उनका किस प्रकार सरक्षण होगा। यह प्रश्न सेना से संबंधित है। उनका यह कहना गलत है कि हम अपने सैनिक वहां पर नहीं भेज सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** हम भेज नहीं रहे हैं।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : हम धीरे-धीरे काम कर रहे हैं। हम असैनिक स्थानों का कब्जा कर रहे हैं। पम अपने दस्तों को वहां भेज रहे हैं और हम जब चाहें तब अपनी सेनायें वहां पर भेज सकते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : चीनी इसको मान लेंगे (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । श्री त्यागी ।

†**श्री त्यागी** : क्या कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार मैकमोहन रेखा तक हम अपनी सेनाओं को भेज सकते हैं ? यदि हम उस रेखा तक नहीं जा सकते हैं तो क्या केवल सामरिक कारणों से अथवा अपने आप अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगा कर अथवा विदेशों से अन्य किसी प्रकार के दबाव के कारण हम अपनी सेनाओं को वहां पर नहीं भेज रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं । कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार हम अपनी सेनायें ढोला क्षेत्र तथा लौगजू के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर भेज सकते हैं ।

**श्री जगदेव सिंह सिद्धांती** : असैनिक प्रशासित नेफा क्षेत्र में क्या कुछ उन भारतीय सैनिकों का पता मिला है जिनको आक्रमण के समय कहा गया था कि वह गुम हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मालूम नहीं आप किस वक्त से हिसाब लगाते हैं । बहुतों का पता लगा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक सबों का पता नहीं लगा है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या मैं यह समझूं कि हमारा असैनिक प्रशासन पुनः स्थापित होने पर हम अपनी सैनिक पुलिस वहां भेज रहे हैं क्या सेना नहीं भेज रहे हैं जिससे असैनिक जनता की सुरक्षा हो सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि सैनिक पुलिस से उनका क्या तात्पर्य है ? सशस्त्र पुलिस एक चीज है । वह वहां पर है । सैनिक पुलिस सेना की होती है । जहां पर सेना जाती है वहीं पर सैनिक पुलिस जाती है । केवल सैनिक पुलिस वहीं पर नहीं जाती है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : राज्यों में सैनिक पुलिस दल होते हैं तथा असैनिक कठिनाई आने पर उनकी सहायता करते हैं । यह पुलिस का काम होता है तथा सेना का नहीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है । सैनिक पुलिस केवल सेना में शांति बनाती है । सशस्त्र पुलिस असैनिक प्रशासन में का भाग होता है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : तो हम सशस्त्र पुलिस वहां भेज रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां । सशस्त्र पुलिस वहां पर है ।

†**श्री रंगा** : कोलम्बो प्रस्ताव तो अब समाप्त प्रायः हैं । परन्तु प्रधान मंत्री के उत्तर से मालूम होता है कि कोलम्बो प्रस्तावों के कारण हमारे कार्यों में बाधा पहुंच रही है और इसलिये हमारी सेना खाली क्षेत्रों में नहीं जा सकती है ?

†**श्री त्यागी** : वह इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं ।

**श्री यशपाल सिंह** : जैसा दो बार आल इंडिया रेडियो से कहा गया कि अब भी चीनी सैनिक नेफा के बार्डर के उधर दिखाई देते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि आज उनकी क्या पोजीशन है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझ सकता कि माननीय सदस्य किस बार्डर की चर्चा करते हैं । बार्डर के कितनी दूर के ऊपर, बार्डर के एक मील इधर या दस मील उधर ;

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मेरी आपसे अपील है कि सीमा पर सैनिकों के आने-जाने की जानकारी के पूछने की आप अनुमति न दें ?

†**श्रीमती रेणुका राय** । भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि नेफा में जासूसों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे पास आयें और, उन्होंने बताया कि वहा पर एसा कार्य हो रहा है तथा उसका प्रमाण मौजूद है, मैं जानना चाहती हूं कि इन कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है । अगला प्रश्न ।

सैनिक स्कूल

*११४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री ब० कु० दास :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
**श्री हेम राज :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
**श्री हेडा :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री मुहम्मद इलियास :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान स्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुय सरकार कुछ और सैनिक स्कूल खोलने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी कोई योजना बना ली गई है ;

(ग) क्या उनकी स्थापना के स्थान और राज्यों का भी निश्चय कर लिया गया है और यदि हां, तो व कहां-कहां होंग ; और

(घ) इन सनिक स्कूलों में कितने छात्रों को दाखिल करने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल्ज सोसाइटी द्वारा चलाय जाते हैं, और इनका प्रवन्ध भी वही करती है । यह सोसाइटी सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत, एक स्वायत संस्था है । प्रतिरक्षा मंत्रालय तो केवल इनके विकास के कर्त्तव्य

---

†मूल अंग्रेजी में

निभाता है, और कुछ छात्रवृत्ति-वेतनों तथा स्कूलों के प्रधान-आचार्य, मुख्याध्यापक और रजिस्ट्रार के वेतन तथा भत्तों का खर्च बरदाश्त करता है ।

(ख) योजना सैनिक स्कूल्ज सोसाइटी के नियमों, विनियमों तथा साहचर्य संबंधी ज्ञापन-पत्र के अन्तर्गत है ।

(ग) पहले से चल रहे ११ स्कूलों के अतिरिक्त, मैसूर राज्य में बीजापुर तथा बिहार राज्य में तिलैया के स्थानों पर, दो और सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव सामने हैं। आसाम में भी एक स्कूल खोलने का सुझाव विचाराधीन है। अन्य सुझावों पर कार्यवाही तभी की जायेगी जब राज्य सरकारें जिन्हें इस निमित्त योजना के अधीन भूमि, इमारतें साजसामान तथा पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तियों जुटानी होती हैं, निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(घ) प्रत्येक सैनिक स्कूल लगभग १५०–२०० छात्रों से चालू होता है, और उसमें ५२५ छात्रों तक प्रसरण अपेक्षित है।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : इन दो सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त जोकि अभी खुलने जा रहे हैं जिनकी कि, स्वीकृति आपके विचाराधीन है,क्या देश के और भी भागों से इस प्रकार के आवेदनपत्र आये हैं जहां कि वे सैनिक स्कूल खोलना चाहते हैं, यदि हां, तो वे आवेदनपत्र किस स्थिति में हैं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : कई आवेदनपत्र हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार से और बिहार भी हैं।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि जो और सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में आप के पास आवेदनपत्र आये हैं, क्या उनमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता है जिस कारण कि आप उनको स्वीकृति नहीं दे रहे हैं या आप के पास धन का अभाव है जिस कारण कि आप उनको जोकि सैनिक स्कूल खोलने को तैयार हैं, स्वीकृति नहीं दे रहे हैं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो आवेदनपत्र आते हैं उनकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों को ही लेनी पड़ती है, इसलिये धन की कमी का कोई स्वाल पैदा नहीं होता है ।

**श्री जगदेव सिंह सिद्धांती** : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जो मिलेटरी के सर्वथा योग्य हैं और भरती होने के लायक हैं उनको भरती न करने के लिये यह कहा जाता है कि तुम बढ़िया इंगलिश नहीं बोलते ? क्या ऐसी बात है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो स्कूलों की बात कर रहे हैं।

**श्री यशपाल सिंह** : क्या लखनऊ के एक ट्रस्ट ने डिफेंस मिनिस्टरी को २५ लाख रुपये की जमीन सैनिक स्कूल खोलने के लिये औफर की है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इस बारे में मुझे कई लोग मिले थे ।

**श्री यशपाल सिंह** : उसका क्या परिणाम रहा ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : वह जमीन का सवाल तो राज्य सरकार और उन ट्रस्टियों के बीच का सवाल है। उसके बारे में सैंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री बेरवा कोटा** : इस समय देश में कितने सैनिक स्कूल चल रहे हैं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : ११ चल रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जब यह स्कूल भी खुल जायेंगे तब प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे और क्या इन स्कूलों में लड़कियों को भी भरती किया जायेगा ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : अधिकतम संख्या ५२५ हो सकती है परन्तु लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

†**श्री गु० सिं० मुसाफिर** : स्कूल खोलने के लिये जगह मुकर्रर करते वक्त किस बात का ख्याल रखा जाता है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं पर यह आधारित होता है। सामान्यतः हम राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर इस मामले पर विचार करते हैं।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

### विदेशी सैनिक सहायता

†*११५. **श्री हरि विष्णु कामत** :
**श्री श्रीनारायण दास** :
**श्री प्र० चं० बरुआ** :
**श्री यशपाल सिंह** :
**श्री बिशन चन्द्र सेठ** :
**श्री भक्त दर्शन** :
**श्री भागवत झा आजाद** :
**श्री विद्याचरण शुक्ल** :
**श्री बूटा सिंह** :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २६ अक्टूबर, १९६२ को राष्ट्रपति द्वारा आपात काल की घोषणा किये जाने के बाद से भारत को किन किन देशों ने सैनिक उपकरण और सामान दिये हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में किन आधार अथवा शर्तों पर---नगद भुगतान अथवा आस्थगित भुगतान अथवा उपहार स्वरूप---यह सामान दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड, रोडेशिया, इंग्लैंड, अमरीका, रूस और पश्चिम जर्मनी।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ८५२/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

## अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन

†*११६. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री बृजराज सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेडा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री हेम राज :
श्री मणियंगाडन :
श्री हरिविष्णु कामत :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री रामसेवक यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री प्र० के० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ४ फरवरी, १९६३ से मोशी (टंगानीका) में हो रही अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन की बैठक तथा विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों द्वारा भारत-चीन विवाद के बारे में व्यक्त विचारों की ओर गया है ;

(ख) क्या मोशी में हुये इस सम्मेलन में भारत का भी कोई प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित हुआ था ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल में कौन-कौन से सदस्य थे और वे किन-किन संस्थाओं के प्रतिनिधि थे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) इस सम्मेलन में भारत की ओर से ६ सदस्यों के एक अशासकीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया जिसका नेतृत्व दीवान चमन लाल, संसद सदस्य ने किया ।

(ग) प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

| | |
|---|---|
| १. दीवान चमन लाल, संसद्-सदस्य . | नेता |
| २. बख्शी अब्दुल रशीद . | जम्मू तथा काश्मीर नैशनल कांफ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और संसद्-सदस्य । |
| ३. डा० गोपाल सिंह, संसद-सदस्य . | लेखक और विद्वान; सदस्य, राज्य-सभा । |
| ४. श्री ए० एस० आर० चारी . . | वरिष्ठ एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट । |
| ५. श्री वी० आर० कृष्ण ऐय्यर . . | एडवोकेट, केरल राज्य के भूतपूर्व मंत्री । |
| ६. श्री रोमेश चन्द्र . . . | पत्रकार और जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय शांति परिषद् तथा अफ्रीकी एशियाई एकता की भारतीय एसोसियेशन की कार्य-पालिका समिति के सदस्य । |

**टिप्पण :**

भारत से जाने वाले इन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दो अन्य भारतीय सदस्यों को विदेश से इस प्रतिनिधिमंडल के साथ संलग्न कर दिया गया था :

| | |
|---|---|
| १. श्री कली मुल्लाह | काहरा में अफ्रीकी-एशियाई, एकता संघ के सचिवालय में भारतीय सदस्य । |
| २. श्री विश्वास . | अन्तर्राष्ट्रीय, शांति संस्था, वीआना, में सहयोजक और अखिल भारतीय शांति परिषद्, कलकत्ता, शाखा के सचिव । |

†मूल अंग्रेजी में

"नाइन आवर्स टु राम"

†*११७. { श्री सोनावने :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री विभूति मिश्र : }

**क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी जी पर बना चलचित्र "नाइन आवर्स टु राम" अब बन कर तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस चलचित्र के सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). "नाइन आवर्स टु राम" चलचित्र, जोकि गांधी जी की हत्या से संबंधित है, पूरा कर लिया गया है । सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भारत में इसके प्रदर्शन की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये ।

**नेफा में आदिम जाति के व्यक्तियों का पुनर्वास**

†*११८. { श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री गुलशन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रिशांग किशिंग : }

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में हाल के हुये चीनी आक्रमण में चीनी आक्रमणकारियों द्वारा कितने मोनपा तथा अन्य स्थानीय आदिम जाति के व्यक्ति (असैनिक) मारे गये, अपहृत किये गये, लूटे गये तथा पीड़ित किये गये ; और

(ख) नेफा के आदिम जाति के कितने व्यक्तियों को प्रतिकर दिया गया है तथा कितना प्रतिकर और अन्य प्रकार की सहायता उनके पुनर्वास के लिये दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) नेफा में चीनी आक्रमण के बाद सहायता और पुनर्वास उपायों पर ९,५४,००० रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं जिसमें भोजन सामग्री का वायुयानों द्वारा पहुंचाया जाना और उन व्यक्तियों को जिनकी सम्पत्ति चीनी ले गये थे फिर से बसाना सम्मिलित है।

## समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन

†*११९. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
**श्री बी० चं० शर्मा :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री भागवत झा आजाद :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २१ जनवरी १९६३ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों में विज्ञापन के स्थान को ४० प्रतिशत तक सीमित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और उस पर कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

## पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

†*१२०. **श्री हेम बरुआ :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री हेम राज :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री बेरवा कोटा :**
**श्री श्याम लाल सर्राफ :**
**श्री दाजी :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री भक्त दर्शन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूरोप में पाकिस्तान के विदेश सचिव द्वारा किये गये भारत-विरोधी प्रचार की ओर दिलाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जब भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं के निपटारे के लिये दोनों देशों में बातचीत हो रही है, तो इस समय इस बात के अनौचित्य की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस प्रश्न को उठाया है परन्तु औपचारिक रूप से नहीं ।

(ग) सरकार को कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।

**त्रिदलीय सम्मेलन**

†*१२१. **श्री काशीनाथ पांडे** :
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** :
**श्री अ० ना० विद्यालंकार** :
**श्री हिम्मतसिंहका** :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ नवम्बर, १९६२ को दिल्ली में हुये त्रिदलीय सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि छंटनी, पदच्युति तथा सेवामुक्ति के मामले न्याय निर्णयन की बजाय मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** (क) समझौता संकल्प[१] में यह उपबन्ध किया गया है कि वैयक्तिक श्रमिकों संबंधी सभी शिकायतें, जो आपस में तय न हों, मध्यस्थ निर्णय द्वारा निपटाई जायें ।

(ख) सभी संबंधित व्यक्तियों से समझौता संकल्प की सिफारिश को क्रियान्वित करने की प्रार्थना की गई है । केन्द्रीय औद्योगिक संबंध निकाय[२] के अधिकारियों को विशेष हिदायतें दी गई हैं कि वे दलों को न निपटाये जा सकने वाले झगड़े या संभव मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजने के लिये प्रभावित करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Truce Resolution.

[२]Central Industrial Relations Machinery.

### भारतीय प्रदेश में चीनियों का अवैध प्रवेश

†*१२२. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या २० जनवरी, १९६३ के बाद चीनियों द्वारा भारतीय प्रदेश में अवैध प्रवेश किए जाने अथवा गोली चलाये जाने की कोई घटना हुई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : २० जनवरी, १९६३ के बाद चीनियों के दावे के अनुसार तथाकथित, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पश्चिम में भारतीय प्रदेश में चीनियों द्वारा गोली चलाने अथवा अवैध प्रवेश किये जाने का कोई मामला नहीं हुआ है।

### भारतीय नौ सेना

*१२३. { श्री ओंकार सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान आपात के कारण भारतीय नौसेना को और सशक्त बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या नौ बेड़े को पनडुब्बियों से लैस करने के बारे में कोई कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). सभा में यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

### औद्योगिक श्रमिकों में तपेदिक तथा नेत्र रोग

†*१२४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन आने वाले औद्योगिक श्रमिकों में क्षय और नेत्र रोगों की वृद्धि हो रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Clinics.

(ख) क्षय तथा नेत्र रोगों के सभी मामलों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य चिकित्सालय स्थापित करने अथवा निःशुल्क एक्सरे और घरों पर इलाज करने की व्यवस्था की गयी है ; और

(घ) क्या चश्मे भी दिये जायेंगे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) उपस्थिति संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

(ख) योजना के अधीन तपेदिक और नेत्र रोग के विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं। औषधालयों तथा तालिका में रखे गये डाक्टरों के रुजालयों[1] में और घरों में जाकर चिकित्सा करने की सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है। जिन रोगियों को हस्पताल में चिकित्सा की आवश्यकता होती है उन्हें हस्पतालों में प्रविष्ट किया जाता है।

(ग) तपेदिक विशेषज्ञों की सलाह पर तपेदिक रोगियों का एक्स-रे परीक्षण और गृहोपचर्या निशुल्क किये जाते हैं। तपेदिक के हस्पताल और कक्ष भी स्थापित किये जा रहे हैं।

(घ) ऐसे बीमाशुदा व्यक्तियों को जो काम करते समय अवरक्त विकिरण[2] के सामने अपावरण[3] होने के कारण आंखों में मोतिया बिन्द से पीड़ित हों अथवा काम करते समय किसी चोट से जिनकी दृष्टि क्षीण हो गई हो, मुफ्त चश्मे दिये जाते हैं। दूसरों के लिये राज्य सरकारों ने स्वीकृत दृष्टि-परीक्षकों[4] द्वारा रियायती दरों या बिना लाभ-हानि आधार पर चश्मे दिये जाने का प्रबन्ध किया है।

## प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये संयंत्र

†*१२५. **श्री मुरारका :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये उधार पट्टा आधार पर कोई संयंत्र अथवा उपकरण मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी संयंत्रों का वर्तमान कारखानों में उपयोग होगा ;

(ग) क्या नये औद्योगिक एकक स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) क्या इन में से कुछ यंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र को भी दिये जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Clinies

[2]Infra red radiation

[3]Exposure

[4]Opticians

## भारतीय युद्ध बन्दी

*१२६. श्री रा० स० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरूग्रा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा ग्राजाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री गुलशन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री ग्रोंकार सिंह :
श्री गो० महन्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :
श्री बड़े :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम राज :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० के देव :
श्री बेरवा कोटा :
श्री महेश्वर नायक :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राज तक चीन से भारत में कितने भारतीय युद्ध बन्दी वापस ग्रा गये हैं ; ग्रौर कितने ग्रभी वापस ग्राने हैं ;

(ख) चीनी सैनिकों द्वारा लौटाये गये भारतीय युद्ध बन्दियों में से कितने बीमार हैं तथा कितने स्वस्थ हैं ; ग्रौर

(ग) शेष बन्दियों के कब तक वापस लौटाये जाने की ग्राशा है ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) उन भारतीय सेविवर्ग की संख्या, जो चीनियों ने अब तक लौटाये हैं, ७२६ है, उन १२ शवों को छोड़कर, जो उन द्वारा वापस किये गये हैं। नामावलियों के अनुसार, जो चीनियों से समय समय पर प्राप्त हुई है, अभी उनके पास ३२३७ कैदी हैं। इसके अतिरिक्त १० कैदियों के, चीनियों की कैद में मरने की रिपोर्ट है।

(ख) चीनियों द्वारा लोटाये जाने के समय, ७१४ व्यक्ति रूग्ण और घायल थे। तब से उनमें से २ मर चुके हैं, और शेष में से अधिकांश, अभी हस्पतालों में चिकित्साधीन हैं।

(ग) इस विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

**प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये रूसी सहायता**

†*१२७.
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री मा० ला० द्विवेदी :**
**श्रीमति सावित्री निगम :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री विश्वनाथ राय :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
**श्री सरजू पाण्डेय :**
**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
**श्री बाल कृष्ण वासनिक :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये मिग विमान के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने के अतिरिक्त अन्य सहायता भी देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसने किस प्रकार की प्रतिरक्षा सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार इस प्रकार की सभी सहायता लेने का है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राय चह्वाण)** : (क) से (ग) माननीय सदस्यों द्वारा मांगी गई जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## भारत में सार्वजनिक संचार माध्यम का विकास

†*१२८. { श्री रा० गि० दुबे :
श्री द्वा० ना तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सार्वजनिक संचार माध्यम के विकास के संबंध में डा० श्रम के नेतृत्व में फोर्ड फाउन्डेशन दल की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) भारत की वर्तमान अवस्था में उनको किस हद तक स्वीकार किया जा सकता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). फोर्ड फाउन्डेशन दल, जिसके नेता डा० विल्बर श्रम हैं, सार्वजनिक संचार के लिये केवल एक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था स्थापित करने की योजना बना रहा है। इससे भारत में सार्वजनिक संचार के माध्यम के विकास के बारे में सिफारिशें करना अपेक्षित नहीं है। इसके प्रस्ताव अभी मिलने वाले हैं।

## केन्द्रीय चाय मजूरी बोर्ड

†*१२९. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चाय मजूरी बोर्ड ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो बोर्ड में मामला किस स्थिति में है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) नहीं।

(ख) बोर्ड ने दक्षिण भारत, आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अन्तरिम मजूरी बढ़ा दिये जाने की सिफारिश की है। मुख्य विषयों पर अब पक्षों के विचार सुने जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## नई दिल्ली के चीनी दूतावास में नियुक्त भारतीय

†*१३०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के चीनी दूतावास में अभी भी कितने भारतीय नियुक्त हैं ; और

(ख) वह किन-किन पदों पर नियुक्त हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिह)** : (क) १४ (चौदह)

(ख) १ जनवरी, १९६३ को भारतीय कर्मचारियों की पद-सहित एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है।

विवरण

| क्रम संख्या | नाम | पद |
|---|---|---|
| १ | श्री राम नाथ शास्त्री | हिन्दी अनुवादक |
| २ | ,, पुरुषोत्तम प्रसाद | ,, |
| ३ | ,, रामेश्वर नाथ | क्लर्क |
| ४ | ,, जे० के० ग्रोवर | ,, |
| ५ | ,, मोहन लाल | ,, |
| ६ | ,, वाजित हुसैन | ड्राइवर |
| ७ | ,, काफिल अहमद | ,, |
| ८ | ,, सुन्दर लाल | धोबी |
| ९ | ,, फड़के चन्द | ,, |
| १० | ,, जगरप | माली |
| ११ | ,, रामसुर | ,, |
| १२ | ,, दुद्धानाथ | ,, |
| १३ | ,, मंगल | ,, |
| १४ | ,, शंकर | भंगी |

## पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय राष्ट्रजन

†*१३१. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर आफ पुलिस, श्री मदन बागची, तथा पश्चिम बंगाल नेशनल बालंटियर फोर्स के सैनिक, श्री षष्ठि चरण घोष, जिन्हें पूर्व पाकिस्तानी राइफलमैनों की सहायता से सशस्त्र पाकिस्तानियों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज थाने की सीमा से जुलाई १९६२ में अपहृत कर लिया था, कहां हैं, इसके बारे में सरकार के पास नवीनतम जानकारी क्या है ; और

(ख) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों से उनको रिहा कराने के बारे में कोई अनुरोध किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) सूचना है कि श्री मदन बागची और श्री षष्ठि चरण मंडल (घोष नहीं) अब पूर्व पाकिस्तान में राजशाही सेंट्रल जेल में हैं ।

(ख) जी हां ।

**मिग विमान तथा मिग विमान बनाने का कारखाना**

*१३२.
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री गो० महन्ती :
श्री बूट सिंह :
श्री हेडा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री कजरोलकर
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री बेरवा कोटा :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री जैना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी मिग विमान भारत आ चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या इन मिग विमानों को चलाने व इनकी मरम्मत आदि करने के लिये तथा भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये रूस से कुछ मैकेनिक तथा प्रशिक्षक भी भारत आये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) भारत में मिग विमान बनाने के कारखाने की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) से (ग). कुछ मिग विमान तथा तकनीकी कार्मिक भारत पहुंच चुके हैं। विमानों और कार्मिकों की पूरी संख्या तथा विस्तरण प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

(घ) निर्माण के निमित्त विस्तरण निर्धारित करने के लिये आयोजनदल बनाए जा रहे हैं। जभी रूसी विशेषज्ञों की मन्त्रणा का अन्तिम रूप ज्ञात हुआ, फैक्ट्रियों को स्थापित करने का काम शुरु कर दिया जाएगा ।

**काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग**

†१५१. { **श्री सुबोध हंसदा** :
**श्री स० चं० सामन्त** :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उन लोगों की संख्या जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम पंजीबद्ध करवाये ;

(ख) उनमें से शिक्षित, स्नातक और मैट्रिक कितने हैं ;

(ग) अब तक उनमें से कितनों को रोजगार मिला है ; और

(घ) उन्हें किस प्रकार के काम मिले हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क)

अनुसूचित जातियां . . १६,८०,८६७
अनुसूचित आदिम जातियां . . २,७६,१४३

(ख) जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ग) अनुसूचित जातियां . . . २,१६,७२१
अनुसूचित आदिम जातियां . . ३२,२८७

(घ) जिन व्यवसायों में रोजगार मिला था उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । उन संस्थापनों की श्रेणी के बारे में, जिनमें नौकरियां दी गई थीं, आँकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

| वर्ग | निम्नलिखित के अधीन १९५८—६२ में दी गई नौकरियों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | केन्द्रीय सरकार | राज्य सरकारें | अर्द्ध-सरकारी संस्थापन और स्थानीय निकाय | अन्य |
| अनुसूचित जातियां . | ६१,४०८ | १०१,९८१ | २५,७३९ | ३०,५९३ |
| अनुसूचित आदिम जातियां | ९,८१३ | ११,२९७ | ५,३७२ | ५,८०५ |

†मूल अंग्रेजी में

**बोमडीला (नेफा) में अस्पताल**

१५२. { **श्री रा० स० तिवारी :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफ़ा के बोमडीला अस्पताल में, जहां से सारा सामान चीनी आक्रमणकारी उठा ले गये थे, पुनः सामान पहुंचा दिया गया हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो वह कब तक भेज दिया जायेगा ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) कम्बल, लिनन, दवाइयां और डाक्टरी का अन्य सामान पूरी मात्रा में बोमडीला भेज दिया गया है जिससे कि वहां अस्पताल में फिर से सामान की पूर्ति हो जाये ।

(ख) आशा है कि यह सामान कुछ ही दिनों में बोमडीला पहुंच जाएगा ।

**औद्योगिक समितियों की बैठकें**

†१५३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के कारण सभी औद्योगिक समितियों की बैठकें बन्द कर दी गई हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की परिवेदनायें एकत्रित हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन उपायों के किये जाने की संभावना है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) हां । परन्तु वर्तमान आपात स्थिति की मांगों से सीधा सम्बन्ध रखने वाले काम या प्रयासों को तेज करने के हित में जहां कहीं आवश्यक हो बैठक बुलाई जा सकती है ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**न्याय निर्णयन के लिये औद्योगिक विवाद**

१५४. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस साल अब तक श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा कितने औद्योगिक विवाद न्याय निर्णयन के लिये भेजे गये हैं ; और

(ख) इन में से कितनों का निर्णय घोषित हो चुका है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** (क) २६

(ख) अभी कोई नहीं।

## विकलांग जवान

†१५५. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री बड़े :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री भागवत झा आजाद :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विकलांग जवानों की संख्या जिनकी निर्योग्यता २० प्रतिशत से अधिक है; और

(ख) विकलांग जवानों के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में खोले गये नये व्यावसायिक चिकित्सा एककों की संख्या क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** (क) चीनी आक्रमण के विरुद्ध लड़ते हुए ऐसे विकलांग जवानों की संख्या, जिनकी निर्योग्यता २० प्रतिशत से अधिक है, लगभग २०० होने की संभावना है। वास्तविक संख्या सभी मामलों में शल्य-चिकित्सा होने के बाद ज्ञात होगी।

(ख) सशस्त्र सेनाओं के पास पूना का कृत्रिम अंग केन्द्र ही एक मात्र व्यावसायिक चिकित्सा एकक है जिस के उप-केन्द्र देहली और लखनऊ के सैनिक अस्पतालों में है। कृत्रिम अंग केन्द्र, पूना की क्षमता को दुगना करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

अंगहीन भूतपूर्व सैनिकों के लिये व्यावसायिक / प्रविधिक प्रशिक्षण की सुविधायें कुछेक पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध हैं जैसे कि क्वीन मेरीज टैक्नीकल स्कूल, किरकी, देहरादून में स्थित अन्धे वयस्कों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र और हैदराबाद में बहरे वयस्कों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र।

और २०० अंगहीन भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिये क्वीन मेरीज टेक्नीकल स्कूल का विस्तार करने तथा अंगहीनों के लिये एक प्रशिक्षण-और-उत्पादन केन्द्र खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। बम्बई की शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिये फैलोशिप ने अपनी नव-निर्मित वर्कशापों में २०० अंगहीन भूतपूर्व सैनिक लेने का जो प्रस्ताव रखा था उसकी भी जांच की जा रही है।

## असैनिक रक्षा के लिये उपाय

†**१५६. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने हाल ही में लखनऊ में जो यह कहा बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में आग बुझाने के सामान और असैनिक रक्षा के उपायों पर, जैसे कि खंदके खोदना, बहुत सा रुपया व्यर्थ में खर्च किया गया था क्या यह सूचना ठीक है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने राज्य विधान मंडल में इसका जो खंडन किया है क्या उसकी ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ठीक स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) प्रधान मंत्री ने लखनऊ में जो कहा उसके बारे में सूचना ठीक नहीं थी । उन्होंने यह नहीं कहा था कि पश्चिम बंगाल में बहुत सा रुपया असैनिक रक्षा के उपायों पर व्यर्थ में खर्च किया जाता है । उन्होंने तो यह कहा था कि यदि पुरानी असैनिक रक्षा पुस्तिकाओं में दी गई सलाह का पालन किया गया तो उससे बहुत सा रुपया व्यर्थ जाएगा ।

(ख) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है वह ठीक है ।

(ग) भारत में संकटकाल के उत्पन्न होते ही राज्य सरकारों का ध्यान बहुत पहले बनाई गई असैनिक रक्षा पुस्तिकाओं की ओर दिलाया गया था । ये पुस्तिकायें मुख्यतः इंगलैण्ड में असैनिक रक्षा के अनुभव पर आधारित थीं जहां की परिस्थितियां सर्वथा भिन्न थीं । प्रधान मंत्री ने इसी की ओर ध्यान दिलाया था । वास्तव में पश्चिम बंगाल में इनके अनुसार कुछ भी नहीं किया गया था और इसलिये वहां वास्तव में अपव्यय होने का कोई प्रश्न नहीं उठा था ।

गृह-कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को असैनिक रक्षा उपायों के बारे में और सुझाव भेजे हैं जो भारत में होने वाली संभावनाओं के अधिक अनुकूल हैं । इन से व्यय बहुत कुछ कम हो जाएगा ।

**चीनी आक्रमण**

†१२७. **श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री स० चं० सामन्त :**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विरूद्ध चीनी आक्रमण के आरम्भ होने के शीघ्र बाद जिन देशों की सरकारों को इस विषय में सूचित किया गया था उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इस संबंध में जिन सरकारों को सूचित किया गया था क्या उन सब से उत्तर प्राप्त हुये थे ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक के उत्तर का सारांश क्या है ; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिनकी सरकारों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) :** (क) जिन देशों को इस बारे में लिखा गया था उनकी सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ८५३/६३ ]**

(ख) ११२ देशों को लिखा गया था जिनमें से ९३ ने उत्तर दिया है।

(ग) हमारे पत्र का उत्तर देने वाले देशों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८५३/६३]** प्रत्येक देश से मिले उत्तर का अलग

---

†मूल अंग्रेजी में

अलग सारांश देना संभव नहीं है । इन देशों के बहुत बड़े बहुमत ने भारत के प्रति सहानुभूति और समर्थन प्रकट किया है जबकि सभी ने हमारी सीमाओं पर होने वाली गम्भीर घटनाओं पर चिन्ता प्रकट की है ।

(घ) जिन देशों ने हमारे पत्र का उत्तर नहीं दिया है उनकी एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ८५३/६३]** ।

**सेना में रखे गये भूतपूर्व आई० एन० ए० कर्मचारी**

†१५८. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकटकाल की घोषणा के बाद सशस्त्र सेनाओं में लिये गये भूतपूर्व आई० एन० ए० के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) उन्हें किस हैसियत में रखा गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** (क) अतीत में भूतपूर्व आई० एन० ए० के कर्मचारियों की एक काफी बड़ी संख्या को सेना में भर्ती किया गया है परन्तु हाल ही में भर्ती होने वाले सेविवर्ग के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । भर्ती किये जा सकने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या अब बहुत कम होगी क्योंकि उनमें से अधिकतर पुनः नौकरी में आने/भर्ती होने की उच्चतम आयु सीमा को पार कर चुके होंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**राष्ट्रीय रक्षा कोष**

†१५९. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानने के लिये कि अंशदाता किस प्रकार के थे राष्ट्रीय रक्षा कोष में आने वाले अंशदानों का कोई विश्लेषण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या पता चला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख) ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया गया है और न ही अत्यधिक परिश्रम के बिना ऐसा करना संभव है । भारत के कोने कोने से लाखों लोगों ने इस कोष में अंशदान दिया है ।

**जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करना**

१६०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन राज्यों में जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कानून पास होकर लागू हो चुका है ; और

(ख) उपरोक्त कानून के अन्तर्गत अर्जित की गई फालतू जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में कानून पास किये गये हैं । भूतपूर्व पंजाब क्षेत्र में स्वामित्व के संबंध में कोई अधिकतम सीमा निश्चित

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है लेकिन राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भूस्वामियों के निजी काश्त पर निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर काश्तकारों को बसा सकती है ।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर तथा त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में अधिकतम सीमा कानून लागू कर दिया गया है।

केरल भूमि संबंधी अधिनियम, जिसमें भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में व्यवस्था है, लागू नहीं किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकांश भाग में अधिनियम को लागू न होने वाला करार कर दिया है। मैसूर और उड़ीसा में इस कानून को लागू करने से पहले उसमें संशोधन करने का विचार है । राजस्थान में भूमि की अधिकतम सीमा ३० स्टैन्डर्ड एकड़ निश्चित की है। एक स्टैन्डर्ड एकड़ का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें १० मन गेहूं या उसके बराबर मूल्य की अन्य उपज होती है । राज्य सरकार भूमि की विभिन्न किस्मों के रूप में स्टैन्डर्ड एकड़ का मूल्यांकन कर रही है। मूल्यांकन निर्धारित होने के बाद कानून लागू किया जायेगा ।

(ख) भूमि पर बढ़िया ढंग से काश्त करने के लिये कानून के अन्तर्गत तुलनात्मक आधार पर फालतू भूमि के नियतन को तरजीह देने की साधारणतः व्यवस्था होती है। आवश्यकतानुसार नियत भागियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी । कुछ मामलों में फालतू भूमि का प्रबन्ध सरकारी फार्म के रूप में करने की भी व्यवस्था है।

## जवानों की भर्ती

१६१. **श्री रामेश्वरानन्द :**
**श्री हेम राज :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री बेरवा कोटा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन द्वारा युद्ध-विराम की घोषणा के पश्चात् भारतीय सेना में राज्यवार कितने जवानों की भर्ती की गई है ; और

(ख) अभी कितने जवान सेना में और भर्ती करने की योजना है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** (क) और (ख). सूचना सभा में प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

## उत्पादन की गति

†१६२. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३ नवम्बर, १९६२ को नई दिल्ली में मालिकों और श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों द्वारा एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये जाने से सर्वोन्मुखी उत्पादन की क्या गति है ;

(ख) क्या उपर्युक्त समझौते से संबंधित पक्षों द्वारा इस समझौते का कठिनता से पालन किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) सामान्य रूप से, अनेक एककों से उत्पादन में वृद्धि होने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

(ख) लगता है कि सब मिला कर औद्योगिक समझौते पर प्रस्ताव को संबंधित पक्षों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

**भारत इलैक्ट्रानिक्स**

†**१६३. श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में 'प्रमापीकृत विद्युत् यंत्रों' के गुणात्मक और मात्रात्मक उत्पादन में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रतिरक्षा सेवाओं की मांगों को पूरा करने के साथ साथ क्या कथित यंत्र अब उद्योगों में प्रयोग करने के लिये उपलब्ध हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ८५४/६३**]

**आसाम में औद्योगिक एकक**

†**१६४.** { **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आसाम राज्य में कुछ औद्योगिक एकक स्थापित करने को आसाम सरकार की प्रार्थना पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**आयुध कारखानों की स्थापना**

†**१६५.** { **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
**श्री कोल्ला वेंकैया :**
**श्री शिवमूर्ति स्वामी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक आयुध कारखानों को स्थापित करने की योजना पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कारखानों को स्थापित करने के लिये स्थानों के संबंध में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों के क्या नाम हैं ; और

(घ) क्या इसके लिये किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** । (क) और अधिक आयुध कारखाने स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) और (ग) : अधिकारियों के एक दल ने उपयुक्त स्थानों का सर्वेक्षण कर लिया है तथा उनकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) परियोजनाओं की शीघ्र कार्यान्विति के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

**बी० बी० सी० सिंगापुर से आकाशवाणी के प्रसारण**

†१६६. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री हेम बरुआ :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० बी० सी० सिंगापुर से आकाशवाणी के प्रसारणों को पुनः प्रसारित करने की जो बातचीत चल रही थी वह समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) और (ख). इससे आगे कोई और प्रगति नहीं हुई है।

**जवान**

†१६७. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनियों के पाश्विक हमले के फलस्वरूप बोमडिला तथा सेला के बीच घिर गए जवानों में से बहुत सों को, जो कि बाद में धीरे धीरे सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे थे, पाला तथा शीत मार गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है ; और

(ग) उनमें से कितनों का उपचार हो चुका है तथा कितने अभी इनसे पीड़ित हैं ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही तथा यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**चलचित्र परामर्शदात्री समिति**

†१६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक चलचित्र परामर्शदात्री समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कार्य हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ)** : (क) जी, हां।

(ख) समिति का कार्य यह है कि वह सरकार को उन विषयों पर मन्त्रणा दे जिनका चलचित्र उद्योग तथा उसके भविष्य में विकास पर प्रभाव पड़े।

**शारीरिक रूप से असमर्थ सैनिक कर्मचारी**

†१६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से असमर्थ सैनिक कर्मचारियों के पुनर्वास तथा रोजगार के लिए कुछ प्रबन्ध किए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या।

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख) : विद्यमान पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों ; उदाहरणार्थ क्वीन मेरीज़ टैकनिकल स्कूल, किरकी, प्रौढ़ अंधों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून तथा प्रौढ़ बधिरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद ; में चिकित्सकों द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने के कारण सेना की सेवा से निकाले गये कर्मचारियों के लिए व्यवसायिक/प्राविधिक प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण समाप्त होने पर, विकलांग भूतपूर्व-सैनिकों को रोजगार दिलाने में बम्बई, दिल्ली, मद्रास और हैदराबाद में स्थित विशेष रोजगार दफ्तरों द्वारा सहायता की जाती है।

अधिक सुविधायें प्रदान करने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

**सीमावर्ती क्षेत्रों में नये रेडियो स्टेशन**

१७०. { **श्री भक्त दर्शन** :
**श्री भागवत झा आजाद** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोहिमा के अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों के अन्य किन-किन स्थानों पर आकाशवाणी के नये केन्द्र स्थापित किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : कोहिमा के अलावा और कोई नया रेडियो केन्द्र स्थापित नहीं किया है। कुछ वर्तमान केन्द्रों की शक्ति बढ़ा दी गई है या बढ़ाई जा रही है।

---

†**मूल अंग्रेजी म**

**केरल सरकार के लिए विशेष सहायता**

†१७१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने में राज्य पर लगी सीमाओं को ध्यान में रखकर केरल सरकार ने केन्द्र से किसी विशेष सहायता के लिए प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता किस रूप में मांगी गई है तथा किस सीमा तक ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरमन्)** : (क) से (ग). १९६३–६४ के लिए राज्य की वार्षिक योजना के प्रारूप में प्रस्तावित ३० करोड़ ८४ लाख रुपये के व्यय के विरुद्ध ३२ करोड़ ८० लाख रुपये के व्यय के लिए सहमति दे दी गई है।

**सैनिक कारखानों में उत्पादन**

१७२. { **श्री रा० स० तिवारी** :<br>**श्री यलमन्दा रेड्डी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि ब्रिटिश सहयोग से आवाडी में स्थापित टेंक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो टेंक कितने समय में बनने लगेंगे ; और

(ग) क्या बारूद तथा स्वचलित शस्त्रास्त्र भी इस कारखाने में बनेंगे ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं। कारखाना योजना के अनुसार स्थापित किया जा रहा है। तदपि, टैंकों के निर्माण को आरम्भ करने की तिथि को और निकट लाने के लिए, सुझाव विचाराधीन हैं।

(ख) निर्माण १९६६ में आरम्भ होने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

**सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का प्रतिरक्षा सेवाओं में उपयोग**

†१७३. { **श्री हेम बरुआ** :<br>**श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय के सीमावर्ती प्रदेशों से, विशेषतः उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रतिरक्षा सेवाओं में, लोगों को भरती करने के सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि कदम पहिले ही उठा लिए गए हैं, तो उनके प्रति लोगों का क्या प्रतिक्रिया रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण)** : (क) हिमालय के सीमावर्ती प्रदेशों से, विशेषत: उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों से, लोगों को भरती करने की दृष्टि से एक पृथक भरती का दफ्तर, जिसका मुख्यालय गोहाटी में है, तथा एक नया उप-भरती दफ्तर तेजपुर में स्थापित कर दिया गया है। अब इस क्षेत्र में पांच शाखा तथा उप-भरती दफ्तर होंगे, अर्थात तेजपुर, गोहाटी, शिलांग, जोरहाट तथा सिलचर में।

(ख) अब तक इस क्षेत्र में भरती के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया बहुत संतोषजनक रही है।

### लोहता में युद्ध सामग्री सम्भरण केन्द्र

१७४. **श्री बागड़ी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी जिले के अन्तर्गत लोहता में कोई युद्ध सामग्री सम्भरण केन्द्र (सप्लाई बेस) बनाने की योजना है ;

(ख) क्या सन् १९४२ में भी ऐसी योजना बनाई गई थी और उसके फलस्वरूप काफी किसान वहां से हटाये गये थे लेकिन वह योजना बाद में स्थगित कर दी गई थी ; और

(ग) क्या यह सम्भरण केन्द्र (सप्लाई बेस) लोहता के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जा सकता है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) तथा (ग). इस बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरे स्थान भी विचाराधीन हैं।

(ख) इस विषय में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

### लाहौल तथा स्पिती पर वृत्त-चित्र

†१७५. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौल तथा स्पिती पर वृत्त-चित्र तैयार कर लिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) लाहौल पर स्पिती पर एक रंगीन वृत्त-चित्र बन रहा है। चलचित्र के दो संस्करण होंगे—एक सिनेमास्कोप आकार का तथा दूसरा सामान्य आकार का।

(ख) अब तक इस पर २० हजार ६ सौ रुपये व्यय हो चुके हैं ; इसके अतिरिक्त २९ हजार ४०० रुपये और व्यय होने का अनुमान है।

### गोरखपुर श्रमिक संगठन

†१७६. **श्री काशी नाथ पाण्डे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि गोरखपुर श्रमिक संगठन २० वर्ष पूर्व बना था, अभी तक इसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख). गोरखपुर श्रमिक संगठन के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

## कपड़ा मिलों में श्वास रोगी

†१७८. श्री काशीनाथ पांडे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि कपड़ा मिलों में श्वास रोगियों की संख्या बढ़ रही है (व्यावसायिक रोगों की सूची में इस रोग के सम्मिलित न किये जाने के कारण) फिर भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराये हुये श्रमिकों का उचित उपचार नहीं हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह देखने के लिए कि बीमा कराये हुए श्वास रोगियों का उचित उपचार हो तथा यह रोग भी व्यावसायिक रोगों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरमन्) : (क) और (ख). कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन श्वास रोगियों का उचित उपचार किया जा रहा है। तदापि, श्वासरोग को व्यावसायिक रोगों की सूची में सम्मिलित करने का विचार नहीं है क्योंकि व्यावसायिक संकटों के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी यह रोग उत्पन्न हो सकता है।

## बीमा कराये हुए कर्मकारों के परिवार

†१७९. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराये हुए व्यक्तियों के परिवारों की चिकित्सा उसी स्तर पर नहीं की जाती जिस पर कि स्वयं उन बीमा कराए हुए व्यक्तियों की की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह देखने के लिए बीमा कराए हुए व्यक्तियों के परिवारों की भी उचित चिकित्सा की जाय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरमन्) : (क) और (ख). बीमा कराए हुए व्यक्तियों के परिवारों को, अस्पताल में भर्ती किए जाने के अतिरिक्त, स्वयं बीमा कराए हुए व्यक्तियों के समान ही चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार है तथा वही उन्हें दी भी जा रही है। पर्याप्त संख्या में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पताल निर्मित होने पर उनको अस्पतालों के भीतर चिकित्सा देने की भी आशा की जाती है। राज्य सरकारों के परामर्श से अस्पतालों के निर्माण के लिए एक देशव्यापी कार्यक्रम चालू कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**भविष्य निधि अंशदानों का जमा किया जाना**

†१८०. **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे नियोजकों[1] की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है जिन्होंने कि भविष्य निधि के लिए अपने कर्मचारियों से वसूल किए गए अंशदानों को तथा उस में के अपने भाग को सरकार के पास जमा नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, कुल कितना रुपया एसे नियोजकों के पास पड़ा है तथा इस प्रवृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरमन्)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ख) (१) ३० नवम्बर, १९६२ तक ३ करोड़ ८५ लाख रुपये

(२) निम्नलिखित वसूली कार्यवाहियां तथा अभियोग चला दिए गए हैं :—

**एक—वसूली कार्यवाहियां**

(क) ३१ दिसम्बर, १९६२ तक प्रारम्भ की गई वसूली कार्यवाहियों की संख्या १३,८८२

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६२ तक फैसला हो जाने वाली वसूली कार्यवाहियों की संख्या १०,२८८

**दो—अभियोग**

(क) ३१ दिसम्बर, १९६२ तक चलाये गए अभियोगों की संख्या ५,९४२

(ख) उन वादों की संख्या जिन में ३१ दिसम्बर, १९६२ तक दोषसिद्धि की जा चुकी है २५०९

**समाचार एजेंसियां**

१८१. **श्री बेरवा कोटा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी समाचार-एजेंसियों की संख्या और नाम क्या हैं, जो भारत के अनेक स्थानों से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को समाचार उपलब्ध करती हैं ;

(ख) इन में से कौन-कौन सी एजेंसियां अंग्रेजी के माध्यम से और कौन-कौन सी एजेंसियां संविधान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं के माध्यम से काम करती हैं; और

(ग) कितनी एजेंसियों से सरकार आकाशवाणी के लिए समाचार ख़रीदती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Employers.

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) :** (क) सरकार के पास उन्हीं समाचार एजेंसियों के बारे में जानकारी है जो, आई० टी० रूल्ज़[1] के अन्तर्गत रियायती दरों पर संचार सुविधाओं के लिए डाक और तार विभाग में पंजीकृत हैं। ऐसी समाचार एजेंसियों की एक सूची-संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ८५५/६३]।**

(ख) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज़ आफ़ इंडिया अंग्रेज़ी के माध्यम से काम करती हैं। हिन्दुस्थान सामाचार को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड हिन्दी और कुछ प्रादेशिक भाषाओं में समाचार उपलब्ध करती है। अन्य समाचार एजेंसियां किन-किन भाषाओं में समाचार उपलब्ध करती हैं, इसका कोई रिकार्ड नहीं है ।

(ग) एक (प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया)।

## नेफ़ा की वर्तमान जनसंख्या

†१८२. **श्री बैरवा कोटा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की जनगणना के अनुसार नेफ़ा की जनसंख्या कितनी है ;

(ख) क्या चीनी आक्रमण तथा उसके बाद की घटनाओं के कारण वहां की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा है: और

(ग) नेफ़ा की वर्तमान जन संख्या कितनी है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) १९६१ की जनगणना के अनुसार नेफ़ा की जनसख्या ३ लाख ३६ हज़ार ५५८ है।

(ख) चीनी आक्रमण काल में कुछ असैनिक व्यक्ति मारे गए थे। उनकी संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है । लगभग १०,५०० व्यक्तियों ने हमारे असैनिक प्रशासन के साथ साथ नेफ़ा का परित्याग किया। इन में से १,८३५ के अतिरिक्त सभी व्यक्ति घर वापिस लौट आये हैं। इन के भी शीघ्र ही लौट आने की सम्भावना है । उन निष्कान्ताओं की सहायता कार्यों के लिए जिन के खाद्यान्न तथा सम्पति चीनी ले गये थे ९ लाख ५४ हजार रुपये व्यय हो चुके हैं। चीन द्वारा अधिकार किए जाने के समय जो व्यक्ति पीछे रह गये थे उसमें से भी अधिकांश गांवों में वापस आगये हैं ।

(ग) इस प्रकार नेफ़ा की जनसंख्या में कोई जानने योग्य भारी परिवर्तन नहीं आ है ।

## सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान

†१८३. { **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बूटा सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सिनेमाघरों को प्रत्येक शो के बाद राष्ट्रीय गायन सुनाने के लिये कहा गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] I l ian Telegraph rules.

(ख) क्या जिस समय राष्ट्रीय गायन होता है उस समय उन्हें ऐसी स्लाइड दिखाने के लिये कहा गया है जिस में कि राष्ट्रीय ध्वज तथा गांधी जी दिखाये गए हों ।

(ग) क्या कुछ सिनेमाघरों के स्लाइड्स में राष्ट्रीय ध्वजों की बजाय कांग्रेसी झंडा दिखाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके पुनरावर्तन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## अमरीकी लड़ाकू विमान

†१८४. { **श्री बूटा सिंह** :
**श्री यशपाल सिंह** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अमरीकी प्रशासन को भारतीय वायु सेना के लिये लड़ाकू विमान देने के विषय में कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अमरीकी प्रशासन की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) ऐसे कितने हवाई जहाजों का आयात करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग). भारत सरकार ने अमरीकी प्रशासन से सैनिक सामग्री की सहायता देने के लिये प्रार्थना की है ; किन्तु पूछी गई बातों का सविस्तार उत्तर देना लोक हित में नहीं है ।

## बोमडीला के निकट जीप दुर्घटना

†१८५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ फरवरी, १९६३ को नेफा क्षेत्र में बोमडीला के निकट हुई जीप दुर्घटना में सेना के ३ कर्मचारी, जिनमें एक मेजर भी था, मारे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) दुर्घटना के कारणों की जांच एक सैनिक जांच न्यायालय द्वारा की जा रही है ।

## संविधान के अनुच्छेद ३१ (क) का संशोधन

+

†१८६. { **श्री अ० व० राघवन्** :
**श्री पोट्टेकाट्ट** :
**श्री नि० रं० लास्कर** :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा सुझाये गये भूमि सम्बन्धी सुधारों को लागू करने के

†मूल अंग्रेजी में ।

लिये संविधान के अनुच्छेद ३१ क में संशोधन करने के विषय में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) क्या किसी राज्य ने कोई अभ्यावेदन भेजे हैं और यदि हां, तो उनमें की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन को कब तक पुरःस्थापित किया जायेगा ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग) राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है। संविधान को संशोधित करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

### बेरोजगार स्नातक

†१८७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में १ जनवरी, १९६३ को चालू रजिस्टरों के अनुसार बेरोजगार स्नातकों की संख्या क्या थी ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** ६३,७८४ ।

### पंजाब में लोक नृत्यों पर वृत्त-चित्र

†१८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या पंजाब के लोक नृत्यों पर कोई वृत्त-चित्र तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख). पंजाब के लोकनृत्यों पर कोई पृथक वृत्त-चित्र तैयार नहीं किया गया है, किन्तु निम्नलिखित चलचित्रों में कुछ नृत्यों का समावेश कर लिया गया है :—

| क्रम संख्या | चल-चित्र का नाम | विषय | चलचित्र में दिये गये पंजाब के लोक नृत्य का नाम |
|---|---|---|---|
| जो पूरे हो चुके हैं : | | | |
| १. | धरती की झंकार . | भारत के लोक नृत्य | गिद्दा और भांगड़ा |
| २. | दी डांसिंग" फीट ("धरती की झंकार" का लघु संस्करण) | तदैव | भांगड़ा |
| ३. | कांगड़ा और कुल्लू | कांगड़ा और कुल्लू घाटी | स्थानीय निवासियों के नृत्य |
| जो बन रहे हैं : | | | |
| १. | पंजाब | पंजाब पर सांस्कृतिक चल-चित्र | भांगड़ा |
| २. | लाहौल और स्पिति | लाहौल और स्पिति पर सांस्कृतिक चल-चित्र | लामा और तलवार नृत्य |

†मूल अंग्रेजी में

**पंजाब में पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्ति**

†१८९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में रजिस्टर्ड (प्रवीण और अप्रवीण) व्यक्तियों की संख्या ३१ जनवरी, १९६३ को क्या थी ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** ९५,२६९ ।

**जावरा शुगर मिल्स**

१९०. **श्री बड़े :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जावरा शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड" नामक कोई चीनी का कारखाना जावरा नगर (मध्य प्रदेश) में स्थित है ;

(ख) क्या उक्त कारखाने के मजदूरों को गत वर्ष का बोनस अभी तक नहीं मिला ;

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त फैक्टरी में कोई अर्हताप्राप्त इंजीनियर नहीं है ?

**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्):** (क) से (घ). कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधीन है।

**श्रम निरीक्षकों को स्थायी बनाया जाना**

†१९१. **श्री काशीराम गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बाकी काम निरीक्षकों (केन्द्रीय) के स्थायीकरण के विषय को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) अभी नहीं।

(ख) प्राथमिक कदम उठाये गये हैं जैसे स्थायीकरण जोन में आने वाले श्रम निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाना और उनकी सेवा की अन्य बातें एकत्रित करना। कुछ ऐसे अर्ध-स्थायी श्रम निरीक्षक हैं जो अन्य पदों पर चले गये हैं और उनके मामलों पर उनके वर्तमान नियोजकों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। जब उनके मामले निबटा दिये जायेंगे तो इस विषय को विभागीय पदोन्नति समिति के परामर्श से अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ग) यथा सम्भव शीघ्र ।

**श्रम निरीक्षक**

†१९२. **श्री काशीराम गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ अगस्त, १९६२ के अतारांकित

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न संख्या १५१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम निरीक्षकों (केन्द्रीय) के वेतन पुनरीक्षित वेतन स्तर के अनुसार निर्धारित करने में उन की सेवा की अवधि को मान्यता देने के बारे में निर्णय कर लिया गया हैं ; और

(ख) यदि हां तो उस का व्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** (क) और (ख) यह विषय अभी विचाराधीन हैं ।

**ईसापुर राइफल फैक्टरी**

१९३. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**

**क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसापुर राइफल फैक्टरी में गत पांच वर्ष में प्रतिरक्षा उत्पादनों के अतिरिक्त कुछ अन्य सामान भी बनाये गये ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से अन्य सामान बनाये गये और वर्षवार वह कितनी संख्या में थे तथा उन से कितनी आय पृथक पृथक हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों में वहां राइफल उत्पादन कम कर दिया गया था और यदि हां, तो किस अनुपात से ; और

(घ) क्या अब भी प्रतिरक्षा उत्पादनों के अतिरिक्त कुछ सामान बनाया जा रहा है और यदि नहीं, तो कब से वह बन्द हुआ है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० ८५६/६३]**

(ग) फौजी कारखानों में सेवाओं के लिए फौजी सामान का निर्माण केवल उन की पक्की मांग पर किया जाता है । मांगों के अभाव के कारण फौजी कारखानों में राइफलों का निर्माण १९५५ से स्थगित कर दिया गया था । राइफलें बनाने का काम फिर से आरम्भ हो चुका है ।

(घ) आपात घोषणा के यकदम पश्चात से ईसापुर राइफल कारखाने में प्रतिरक्षा सामान के अतिरिक्त सामान का निर्माण बन्द कर दिया गया है । सब से अधिक प्राथमिकता अब सेवाओं की आवश्यकता-पूर्ति को दी जाती है ।

**कलिंग एयर लाइन्स**

†१९४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कलिंग एयर लाइन्स को नेफा क्षेत्र में सामान ले जाने की सेवा के लिये १९६० से अब तक कुल कितना रुपया दिया गया है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** कलिंग एयर लाइन्स को नेफा क्षेत्र में सामान ले जाने की सेवा के लिये १९६० से अब तक १,७८,३३,४१६ रुपये दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**गाजीपुर कालेज में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का एयर विंग**

**१९५. श्री सरजू पाण्डेय :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिग्री कालेज, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र मिला है कि वहां राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन० सी० सी०) के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये 'एयर विंग' की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) :** (क) जी हां ।

(ख) कालिज को सूचित कर दिया गया था कि गाजीपुर में किसी उड़ान-क्लब अथवा हवाई अड्डे के अभाव के कारण, वहां एयर विंग यूनिट चालू करना संभव नहीं था ।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

**मिलिटरी लाइन्स, सागर में पानी की टंकी का फट जाना**

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चहता हूं और मेरा निवेदन है कि वह इस बारे में वक्तव्य दें:—

> "१४ फरवरी, १९६३ को मध्य प्रदेश में सागर में मिलिटरी लाइन्स में एक पानी की टंकी फट जाने के समाचार के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप आठ सैनिक कर्मचारी मारे गये तथा अन्य कई घायल हुए ।"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** पानी की टंकी जो कि लगभग २० फुट लम्बी, ३ फुट चौड़ी ४ फुट ऊंची, ३ फुट ऊंचे प्लेटफार्म पर बनाई गई थी । इसे सागौर में सैनिकों के नहाने धोने के लिये बनाया गया था । इसकी स्वीकृति आपातकालीन कार्य के रूप में ३१–१२–६२ को दी गई थी । सागौर के एम० ई० एस० के विभागीय श्रम ने इसे १७ जनवरी, १९६३ को पूरा कर लिया था ।

१४ फरवरी, १९६३ को लगभग ५ बजे सायं सागर में सेना के इस्तेमाल के लिए संकट काल में प्रयोग के लिए बनायी गयी पानी की टंकी की दोनों दीवारें अचानक गिर गयी जब कि वहां पर रंगरूट अफसर स्नान कर रहे थे । इस दुर्घटना के फलस्वरूप हताहतों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (१) मृत्यु | आठ |
| (२) चिन्ताजनक रूप से घायल | चार |
| (३) गम्भीर रूप से घायल | चार |
| (४) सामान्य स्थिति | दो |

जिन परिस्थितियों में उपरोक्त रंगरूट अफसर मरे अथवा घायल हुए, उन परिस्थितियों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच न्यायालय का आदेश दे दिया गया है । पानी की टंकी के फट जाने के कारणों की जांच करने के लिए "हेड क्वार्टर्स एम० पी० सब एरिया" को भी एक 'तकनीकी' जांच

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालय आयोजित करने को कहा गय है। जांच पड़ताल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

पीड़ितों को अन्तरिम सहायता देदी गयी है।

**बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वहां के भारतीय बैंकों पर उस के प्रभाव**

†**श्री दामोदर टाँटिया** (सीकर) : मैं **वित्त** मंत्री का ध्यान निम्न लिखित लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वह अपना वक्तव्य दे :—

"बर्मा के बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वहां के भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव।"

†**प्रधान मंत्री, तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मेरे विचार में, पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में एक दो दिन में अपना वक्तव्य देंगे।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८७१/६३]**

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : मैं भारतीय नौसेना अधिनियम की धारा १८५ के अन्तर्गत, दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३२९ में प्रकाशित भारतीय रक्षित नौसेना और भारतीय रक्षित स्वयंसेवक नौसेना (संशोधन) विनियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखत हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७३२/६२]**

**त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार (संशोधन) नियम**

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**:मैं त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार अधिनियम १९६० की धारा १९८ के अन्तर्गत, दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३९ (३८) राजस्व/६१ की एक प्रति, जिसमें त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार (संशोधन) नियम १९६२ दिये हुए हैं, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ८५१/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

## कार्य मंत्रणा समिति

### तेरहवां प्रतिवदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो २२ फरवरी, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो २२ फरवरी, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

### राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा २० फरवरी, १९६३ को श्री रा० शि० पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत तथा डा० क० ला० राव द्वारा अनुमोदित निम्न प्रस्ताव पर विचार करेगी, अर्थात् :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ फरवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है ।' "

तथा २० फरवरी, १९६ को प्रस्तुत संशोधनों पर आगे विचार किया जायेगा ।

**श्री ब्रज राज सिंह** (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि चीन को हमने भाई बनाया और भाई भाई का नारा लगाया । चीन ने भी पंचशील के सिद्धान्तों को माना और उसके बाद भी हमला किया और एक बड़ा धोखा हमारी सरकार को हुआ । उस धोखे से सरकार को सबक लेना चाहिए था । कई बार कहा भी गया है कि हमें सोते हुए पकड़ा गया किन्तु अब हमारी आंखें खुल गई हैं । परन्तु देखने को यह मिला है कि हम एक नया भ्रम अपने मन में उत्पन्न कर रहे हैं, यह भ्रम कि शायद कम्युनिज्म में कोई दो गुट्ट बन गये हैं । एक गुट्ट चाहे भले ही हमारा विरोध करे और हम पर हमला करे परन्तु दसरा गुट्ट भी हमसे भाईचारा निभाने के लिए तैयार है । हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए कम्युनिस्ट भाई हमारे देश और उस नये गुट्ट के बीच में एक दलाली कर रहे हैं । एक भाईचारा और एक रिश्ता पैदा करने की बात कर रहे हैं । हमें देखना पड़ेगा कि जब हमें ने चीन को भाई बनाया और वहां से हमें धोखा मिला, उधर रूस बराबर कह रहा है कि हिन्दुस्तान हमारा दोस्त जरूर है परन्तु चीन हमारा भाई है, मौका आने पर हम भाई की मदद करेंगे । परन्तु फिर भी ऐसा नशा सा हमारे ऊपर तारो हो चुका है कि हम उसके मना करने के बावजूद भी इस बात की ज़िद में लगे हुए हैं कि हम उसको भाई बना कर ही छोड़ेंगे और हमारे देश के उन्हीं के पैदा किये हुए कम्युनिस्ट उस बीच में दलाली कर रहे हैं । हमारी सरकार उन्हें दलाली के पैसे भी देती है, कीमत भी दलाली की अच्छी देती है । उनको वह बतलाती है कि यह सेंट परसेंट नेशनलिस्ट्स हैं । मुझे समझ में नहीं आता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

कि इस प्रकार पहले एक गंट को भाई बना कर धोखा खाया, अब इस आशा पर कि उन दोनों गुटों में आपस में मतभेद हो गया है, दूसरे गुट की तरफ भाईचारे का हाथ बढ़ाय जा रहा है। ईश्वर जाने क्या होने वाला है, हमारे इस देश का यदि उस दूसरे भाई ने भी हमें वही चपत लगाई जो कि पहले भाई ने लगाई थी। इतना बड़ा इलाका तो एक भाई ले गया। ईश्वर जाने कि यह दूसरा भाई कितना बड़ा इलाका लेकर हमको चपत लगाने वाला है।

यह चाल चली जा रही है कम्यूनिस्टों के उन दलालों की तरफ़ से, जो कि आज भारतवर्ष में मोजूद हैं और हमारीं रूलिंग पार्टी के अन्दर भी जिनका प्रवेश हो चुका है।

**श्री त्यागी** (देहरादून) : नहीं।

**श्री बृजराज सिंह** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी दुनिया उनके बर्बरतापूर्ण ढंग को जान गयी है, उनके अमानुषिक तरीकों को जान गयी है, परन्तु यह दावा करते हुए भी कि हमारी आंखें खुल गयी हैं, हमारी सरकार को उनकी बर्बरता का ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। हज जाने वाले हर एक यात्री के प्रति कुछ श्रद्धा पैदा होती है, परन्तु जब नौ सौ चूहे खाने के बाद कोई बिल्ली हज करने के लिए चले तो एक सन्देह अवश्य उत्पन्न होता है। किन्तु हम देखते हैं कि हमारी सरकार के मन में कोई सन्देह उस बिल्ली के प्रति भी नहीं है, जो कि नौ सौ चूहे खाकर हज करने जा रही है। हमारी सरकार अभी भी यह आशा लगाये बैठी है कि जो भाई-चारा चीन से टूट गया है, वह रूस से स्थापित हो जायेगा।

अभी पिछले दिन कांग्रेस के हमारे एक साथी, श्री ब्रह्मप्रकाश ने एक आरोप लगाया। उनकी जानकारी के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस सा है। उन्होंने कहा कि कम्यूनिस्टों से टकर लेने, कम्यूनिस्टों का मुकाबला करने या वर्ल्ड कम्यूनिज्म का मुकाबला करने का नारा अब पुराना हो चुका है और अब इस नारे में कोई तथ्य नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि अब कम्युनिज्म से हमें कोई ख़तरा बाकी नहीं है, बल्कि उस से ज्यादा ख़तरा हमें जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी से है। हम उनकी विद्वत्ता की कहां तक कद्र करें? हमें तो अफ़सोस होता है।

आज मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं और इस हाउस को याद दिला दूं कि हमारी पार्टी कहीं बाहर से प्रेरणा लेने वाली पार्टी नहीं है। यह उस महापुरुष से प्रेरणा लेने वाली पार्टी है, जिस ने भारत की अखंडता के लिए हमारे बड़े से बड़े नेता से कंधा मिला कर एक आदर्श स्थापित किया, जिस ने काश्मीर के मसले पर अपनी जान की बाज़ी लगाई और अपने प्राणो की आहुति देकर भारत की अखंडता के सिद्धान्त को कायम किया। हम सदा उसी से प्रेरणा लेते रहे और लेते रहेंगे। भारत की अखंडता हमारा मुख्य उद्देश्य है।

परन्तु हमारे कुछ मित्रों को इस से सब्र नहीं होता। कांग्रेस को तो आज चाहिए हीरो-वरशिप। आज तो उस को उन लोगों से प्रसन्नता होती है, जो कि नेहरू जी के नाम पर दुआयें देते रहते हैं। वे कुछ भी करे। उन के कारनामों को देखने वाला कोई नहीं है। उन के लिए एक पास-वर्ड मौजूद है कि हम नेहरू सरकार के साथ हैं। उस पासवर्ड का इस्तेमाल कर चाहे वे मिनिस्टरों में फूट डालने की कोशिश करें, और मिनिस्टरों पर कीचड़ उछालने और उन को बदनाम करने की कोशिश करे, देश में फूट डालने का प्रयत्न करे, वह सब क्षम्य है।

**श्री त्यागी** : नेहरू का मतलब है कांग्रेस गवर्नमेंट।

**श्री ब्रजराज सिंह** : तो क्या यह समझा जाए कि जो बाकी के मिनिस्टर हैं, उन का मतलब कोई दूसरी सरकार है ?

श्री ब्रह्मप्रकाश ने यदि कोई तर्क शुद्ध बात कही तो केवल एक और वह यह कि नई दिल्ली में इमर्जेन्सी का कुछ असर नहीं हुआ। यह बात तो आपोजीशन ने भी चिल्ला-चिल्ला कर कही है। माननीय सदस्य ने भी कही, है, इस लिये हम उन को बधाई देते हैं। यह खुशी की बात है कि उन्होंने यह बात कहने की हिम्मत की ।। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इसकी ज़िम्मेदारी अपोजीशन पर है? क्या सरकार की अपनी कमियों के लिए आपोज़ीशन ज़िम्मेदार है? वास्तव में इस बात पर सरकार की गर्दन शर्म से झुक जानी चाहिए और उसको अपने गरेवान में मुंह डाल कर देखना चाहिये। अगर नई दिल्ली में इमर्जेन्सी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो यह जिम्मेदारी सरकाकार की है और उस को इस बारे में उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि कांग्रेस संगठन पर यह ज़िम्मेदारी है और उस ने इस ज़िम्मेदारी को कई दफ़ा निभाया भी है। मैं समझता हूं कि पिछले सुरक्षा मंत्री को अपने पद से हटाने का श्रेय कांग्रेस संगठन को है। उस ने यह अनुभव कर के कि उनकी जरूरत नहीं है हिम्मत कर के उन को हटा दिया। अगर आज नई दिल्ली में इमर्जेन्सी का कोई असर नहीं है, तो यह उस की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी सरकार पर प्रैशर डाले और उस को मजबूत करे कि वह ऐसे कदम उठाये, जिससे दुनिया और देश को मालूम हो कि इमर्जेन्सी का कुछ असर नई दिल्ली पर पड़ा है। सम्भव है कि अन्दरूनी तौर पर वह असर हो, लेकिन जनता पर उस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ईमानदार है, यही काफ़ी नहीं है। दुनिया को, भारतवर्ष को मालूम होना चाहिए कि वह ईमानदारी नहीं है। दुनिया को और इस देश को मालूम होना चाहिये कि इमर्जेन्सी के कारण नई दिल्ली पर और इस देश की शासन-व्यवस्था पर कुछ असर पड़ा है। मैं बार-बार कहूंगा कि इस की ज़िम्मेदारी कांग्रेस संगठन पर है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस संगठन अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वह अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेगा और अपने मिनिस्टरों को इस बात के लिए मजबूर करेगा कि वे अपनी आसाइश को कम करें।

अब मैं गोल्ड कंट्रोल के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है कि सरकार के बीच में रिफ्ट डाली जाये, सरकार के नाम पर तो दुआयें दी जायें और एक मिनिस्टर की किसी बात पर उसे कोसा जाए। मैं समझता हूं कि गोल्ड नियंत्रण एक आवश्यक कदम था। बाहर से तस्कर व्यापार चल रहा था और यहां की कीमतें बहुत ऊंची जा रही थीं और इस के लिये कोई नियंत्रण लाना बहुत आवश्यक था। खेद तो केवल इस बात पर है कि यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया। स्वर्ण का तस्कर व्यापार केवल इमर्जेन्सी के टाइम में तो नहीं शुरू हुआ। जिस प्रकार गवर्नमेंट सुरक्षा के मामले में सोती रही, उसी प्रकार वह स्वर्ण के तस्कर व्यापार के मामले में भी सोती रही और वह जागी उस वक्त, जब कि मार-मार कर जगाया गया। तब इमर्जेन्सी के टाइम पर स्वर्ण नियंत्रण लाया गया। इस को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। इमर्जेन्सी के टाइम पर स्वर्ण नियंत्रण करने का परिणाम यह हुआ कि देश तो पहले ही बेकारी के चंगुल में फंसा हुआ था, अब और बीस लाख आदमियों को बेकारी के चंगुल में डाल दिया गया। इस से गवर्नमेंट का कोई आराम होगा, यह मैं नहीं समझ पाता। इन बीस लाख आदमियों के बेकार हो जाने से देश में कितना दुःख और परेशानी होगी, मैं समझता हूं कि इस का अन्दाज आज सरकार अच्छी तरह लगा रही है। यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि उन लोगों को सर्विसिज़ में जगह दी जायगी। और सर्विसिज़ हैं कहां? सर्विस पाने के लिये लाखों करोड़ों आदमी

[श्री ब्रजराज सिंह]

पहले ही से बिलबिला रहे हैं। उन के साथ ही बीस लाख आदमियों की एक और लम्बी क्यू लगा दी गई है।। अगर सरकार की तरफ से इन लोगों को सर्विस के सम्बन्ध में प्रायर्टी दी जाती है तो इस का मतलब यह होगा कि आज तक जो लोग मर रहे हैं, उन का नम्बर इन बीस लाख लोगों के पीछे चला जाता है। सरकार को इस बारे में कोई तगड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे इस बेरोजगारी और भुखमरी से बचने का उपाय किया जा सके।

आज देश में एन० डी० एफ़०, नैशनल डिफ़ेंस फ़ंड, के लिए कलेक्शन किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में से आ रहा हूं। सब जगहों का तो मुझे पता नहीं, परन्तु उत्तर प्रदेश में जो नैशनल डिफ़ेंस फ़ंड कोई दान-वृत्ति वाली चीज़ नहीं रही। वहां पर अब रीयलाइज़ेशन किया जा रहा है। डेफ़िनिट्ली रीयलाइज़ेशन किया जा रहा है। वसूलयाबी हो रही है। मैं ने अपनी आंखों से बरेली के कलेक्टर का सर्कुलर-लैटर देखा है, जिस में लिखा है गया था कि "फ़लां फ़लां तारीख़ को हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री आ रहे हैं और उनको इतनी बड़ी थैली पेश करने का हम वादा कर चुके हैं। आप जा कर एक एक गांव को बेबाक कर लीजिए।" लफ्ज़ "बेबाक" इस्तेमाल किया गया है। अगर ज़रूरत हो, तो आप दफ्तर के, सरकार के काम छोड़ कर और बाहर रह कर वसूलयाबी करते रहें ताकि हमारे मुख्य मंत्री जो आ रहे हैं, उनको थैली भेंट करने में कोई कमी न हो जाए। यह कलैक्टर साहब की चिट्ठी है जो सर्क्युलेट की गई है, सारे तहसीलदारों में सारे एस०डी०ओज़० में, सारे ए० एस०डी० ओज़० में। इसको मैंने स्वयं देखा है। यदि सदन चाहेगा तो मैं इसे लाकर यहां टेबल पर भी रख दूंगा। इस वक्त मैं इसको ला नहीं सका हूं। हमारे प्रैज़ीडेंट साहब ने कहा कि लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, दी एक्चुअल वार खत्म हो चुकी है परन्तु खतरा बाकी है। लड़ाई खत्म हो चुकी है, नई दिल्ली पर कोई असर नहीं है, कांग्रेस के सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि काहे पर असर है? क्या एन० डी० एफ़० रीयलाइज़ेशन पर इसका असर बाकी रह जाएगा? क्या एन० डी० एफ़० की बैकिंग्ज़ के ऊपर कोई चादर डालनी है। इस तरह का नाजायज इस्तेमाल नहीं है होना चाहिये। जब सरकार को जरूरत हो तो जनता सीना तान कर आगे आ सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो त्याग की भावना जनता में जागृत हुई थी, इस एन० डी० एफ़० की रीयलाइज़ेशन से जो कि आज सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, उसको बड़ी ठेस ही नहीं लगी बल्कि वह सम्पूर्णतः समाप्त हो गई है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि मैं किस प्रकार उस भाषण के लिये जो कि प्रेजीडेंट साहब ने दिया है, धन्यवाद दे सकता हूं।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, इस सदन के दूसरे माननीय सदस्यों के साथ मैं भी आज राष्ट्रपति जी के भाषण का अनुमोदन करने के लिये खड़ी हुई हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि चन्द एक बातें राष्ट्रपति जी के भाषण में नहीं हैं। मैं समझती हूं कि सभी चीजों का जिक्र डिटेल में इस भाषण में नहीं हो सकता था और न ही सभी बातों का ज़िक्र करके कोई ज्यादा फायदा ही हो सकता था।

राष्ट्रपति जी ने कहा कि आज चीनी हमले की समस्या सब से बड़ी समस्या है और उसी को सामने रख कर हम को बाकी बातों पर विचार करना है। मैं राष्ट्रपति जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि हमारी सरकार तमाम चीजों का फैसला जहां तक हो सके, शान्ति से करना चाहती है।

बहुत सी बातें यहां पर कही गई हैं। यह भी कहा गया है कि हमारी सरकार डरती है और इंतजाम ठीक से नहीं करती है या जागृत नहीं है, या बार-बार धोखा खाकर सम्भलती नहीं है। जहां तक मेरी राय है, हम और सरकार और हमारे देश के लोगों ने बता दिया है कि हम जिस तरह से शान्ति के वक्त काम कर सकते हैं, उसी तरह अगर हमारे देश की आजादी को खतरा पैदा हो तो हम अपने देश को बचाने के लिये भी काम कर सकते हैं, पूरी परह से काम कर सकते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने उनको भाई कहा और उन्होंने हम को धोखा दिया। क्या इसका यह मतलब है कि हम दुनिया में लोगों को भाई समझना बन्द कर दें? अगर कोई आज भला आदमी है, अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है, अच्छे उसूलों पर चलना चाहता है, अच्छे काम करना चाहता है, तो दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो एंटीसोशल होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। धोखा भी देते हैं, खराब बातें भी करते हैं लेकिन उन का भी मुकाबला किया जा स कता है। पर यह नहीं हो सकता है कि हम भी खराब हो जायें, हम लोग भी बिगड़ जायें और हम सभी को शक और शुबाह की निगाह से देखना शुरू कर दें और अपने चरित्र से, अपने उसूलों से गिर जायें। इस तरह की बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अगर हमने धोखा खाया धोखा खाया है तो सम्भलना हम लोगों का फर्ज है। हम सम्भले हैं, हमारी जनता सम्भली है। हमारी सरकार भी सम्भली है और जो-जो जरूरी चीजें करनी हैं, उनको कर रही हैं।

यहां डिफेंस में बहुत सा सामान बनने लगा है, बहुत सी चीजें बनने लगी हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती। मैं समझती हूं सरकार उनका जिक्र करेगी। इस सम्बन्ध में मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं कि आज जब शान्ति और अमन है तो हम लोगों को जो बोर्डर के एरियाज हैं, उनकी तरक्की पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिये। बोर्डर एरियाज में मैं उस एरिया का खास तौर पर जिक्र करना चाहती हूं जो कि नेपाल तक है। यह हमारा सौभाग्य है और यह अच्छी बात भी है कि नेपाल से हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। ईश्वर क रे, वे सम्बन्ध बने रहें और कभी लड़ाई और झगड़ा उधर न हो। पर जरूरी नहीं है कि उन सड़कों पर, उन इलाकों की तरक्की पर ध्यान उसी वक्त दिया जाए जब किसी तरह दोनों के ताल्लुकात खराब हो जायें। जब ताल्लुकात अच्छे हों, तब भी उन इलाकों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये और उनको विकसित किया जाना चाहिये। जो इलाके नेपाल बोर्डर से लगे हुये हैं, वहां पर अभी तक सड़कों की हालत खराब है, कोई मीन्ज आफ कम्युनिकेशन नहीं हैं, ट्रांस्पोर्ट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। मैं सरकार से दरखवास्त करती हूं कि उन चीजों का वह अच्छी तरह से खयाल रखे।

हमारे राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा है कि आर्थिक और औद्योगिक विकास भी हमारी डिफेंस के लिये बहुत आवश्यक है। मैं समझती हूं कि इमरजेंसी आने के बाद भी सरकार के उन महकमों ने जो कि हमारे कारखाने बनवाते हैं, जो उनको लोन देते हैं, जो उनकी तरक्की करते हैं, कोई तेजी नहीं दिखाई है। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि १९६२ के पहले नौ महीने में साढ़े सात परसेंट इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ी है। लेकिन इमरजेंसी के बाद क्या नतीजे निकले हैं, कितनी तेजी आई है इसका जिक्र नहीं किया है। मैं तो अभी भी देखती हूं कि जो उद्योग धंधे शुरू करना चाहते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाना चाहते हैं, उनको कर्जे मिलने में, उनको पैसा मिलने में, उनको मदद मिलने में उतनी ही देरी होती है, जितनी पहले हुआ करती थी। यही बात बिजली पर लागू होती है। बहुत सी स्टेटों में अभी भी बिजली और पावर देने का जो काम है, वह प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में है। यह काम प्राइवेट हाथों में होने से न कारखानों के लिये बिजली मिलती है और न कोई मदद होती है। मैं प्रार्थना करती हूं कि इस तरह की चीजों को जल्दी से जल्दी आप अपने हाथों में ले लें, स्टेटें अपने हाथों में लेलें, ताकि जो आवश्यक चीजें

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जिनकी हमें लड़ाई में आवश्यकता है, उनके उत्पादन में तेजी लाई जा सके, उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके, उनके उन्पादन में मदद पहुंचाई जा सके।

राष्ट्रपति जी ने कहा है कि एमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद मालिकों और मजदूरों की मीटिंग हुई थी और वहां पर इस बात का फैसला हुआ कि श्रमिकगण जब तक इमरजेंसी है, तब तक अधिक से अधिक पैदा करने की कोशिश करें और डिसप्यूट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स जो हैं, वे कम खड़े हों। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि इसका लाभ मालिक उठा रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा फैसला था जो कि श्रम मंत्री नन्दा जी ने करवाया था। लेकिन इसका फ़ायदा मालिक ज्यादा से ज्यादा उठा रहे हैं, पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा उठा रहे हैं और कई जगहों पर जो यूनियंज़ में काम करने वाले हैं, उनको निकालने, उनको सताने, उनको हटाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। वे समझते हैं कि अगर श्रमिकगण इसका मुकाबला करेंगे तो कहा जाएगा कि श्रमिक इसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वह इस तरफ तवज्जह दें। मैं चाहती हूं कि वह बतायें कि इस इमरजेंसी में कौन से कदम उठाये गये हैं जिन से मजदूर वर्ग अपनी शिकायतें दूर करवा सकते हैं, अपनी तकलीफें दूर करवा सकते हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करवा सकते हैं।

इसी सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि श्रमिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैदावार बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि जिस तरह से देश के दूसरे पूंजीपति और मालिक इस एमरजेंसी से फायदा उठा रहे हैं, उसी तरह से हमारे यहां भी एक बिल लाने की कोशिश की जा रही है जिस में यह व्यवस्था है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो अपने आपको डिफेंड करने का मौका दिया जाता रहा है, एक सैक्शन का एमेंडमेंट करके, यह मौका उन से छीन लिया जाए, यह जो उनका अधिकार है, यह उन से वापिस ले लिया जाए। मैं दरख्वास्त करूंगी अपने श्रम मंत्री जी से तथा दूसरों से भी कि सरकारी कर्मचारियों ने जितना अच्छा आचरण इस वक्त किया है, जितना अच्छा परिचय दिया है, उसको देखते हुये ऐसे वक्त पर इस तरह का एमेंडमेंट ला कर, उनको चोट पहुंचाना बहुत नामुनासिब है। उन्होंने हमको बहुत ज्यादा पैसा ही नहीं दिया बल्कि यह भी कहा है कि हमें छुट्टी नहीं चाहिये, कुछ नहीं चाहिये, हम चौबीस घंटे काम करने के लिये तैयार हैं। जब वे इतना कोओप्रेशन दे रहे हैं तब इस प्रकार का एमेंडमेंट ऐसे मौके पर नहीं लाया जाना चाहिये। मैं आशा करती हूं कि इस पर विचार किया जाएगा।

यह हमारी समाजवादी सरकार है, इसको मैं मानती हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं। मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर पढ़ी है कि हमारे एल० आई० सी० के लोग बर्मा में एक मुकदमा लड़ रहे हैं और इस आधार पर लड़ रहे हैं कि बर्मा के जो एम्प्लायीज़ हैं, उनको दूसरों के मुकाबले में वहां पर कम पैसा देते हैं, जितने पैसे एल० आई० सी० के हिन्दुस्तानी कर्मचारियों को देते हैं, बर्मा के लोगों को उससे कम मिलते हैं। यहां पर रोज इस बात की चर्चा होती है कि दूसरे देशों की हमारे साथ हमदर्दी होनी चहिये और खास तौर पर आज के वक्त पर तो होनी ही चाहिये। ऐसी सूरत में चाहे हमारे बैंक हों या दूसरे महकमे, दूसरे देशों के लोगों को, दूसरे देशों के नागरिकों को वे एक्सप्लायट करने की कोशिश करें तो वह अच्छा नहीं है। मैं चाहती हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी पालिसी स्पष्ट कर।

हमारे राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा किया जो उन देशों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस इमरजेंसी में हमारी मदद की है। जिन राष्ट्रों का इस भाषण में ज़िक्र नहीं है और जिन्होंने हमारी मदद की

है, उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूं। हमारे देश पर आक्रमण हुआ। चीनी बढ़ते चले आ रहे थे, उस समय खास कर दो देशों का, जिन को उन्होंने धन्यवाद दिया, अर्थात यू० एस० ए० और ग्रेट ब्रिटेन, हमारे देश का बच्चा-बच्चा आभारी है। ऐसा कौन होगा जो एहसान नहीं मानेगा, जो कृतज्ञ नहीं होगा ? हमारे देश के करोड़ों लोग कृतज्ञ हैं उन देशों के जिन्होंने हमारे देश की मदद की थी। परन्तु एक चीज मैं कहना चाहती हूं। मैं इस सभा के माननीय सदस्य श्री रंगा से प्रार्थना करना चाहती हूं कि जिस तरह से वह बाहर की मदद की मांग करते हैं और साथ ही जो हमारे देश की समाजवादी प्लेन है, जो प्लैन समाजवाद पर बेस्ड है, उसका विरोध करते हैं, उस से हमारे देश में बड़ी चिन्ता हो जाती है। बाहर की सारी मदद चाहिये, हर एक को चाहिये। पर क्यों मदद चाहिये ? इस लिये कि इस देश के करोड़ों गरीब लोग इस बात के इन्तजार में हैं कि हमारे देश की आजादी बनी रहेतो किसी दिन हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। अगर बाहर से मदद मांगने वाले लोग रंगा जी जैसे हों और साथ में वह कहें कि सरकार को अपनी समाजवादी प्लैन तोड़ देनी चाहिये, बदल देनी चाहिये और समाजवाद यहां नहीं लाना चाहिये, तो देश के गरीब आदमियों को और जो हमें मदद बाहर से मिलती है उसके बारे में दिल में सन्देह होने लगता है, शुबहा होने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि हमारी समाजवादी प्लैन हट जाय और और अमरीका और इंग्लैंड से मदद आये, कहीं इन में कोई सम्बन्ध तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रंगा साहब की जमात इस बात का फायदा उठाना चाहती हो . . . . . . है ?

**डा० मा० श्री० अणे :** (नागपुर) : आप जो मदद ले रहे हैं उस का मतलब क्या होता है ?

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : हमारे दिल में शुबहा होने लगता है, हम सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रंगा साहब, स्वतन्त्र पार्टी और जन संघ के लोग इमर्जेन्सी का फायदा उठा कर अपना काम सीधा करना चाहते हैं और अपनी-अपनी पार्टी का, जो कि समाजवाद के खिलाफ हैं, उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं और इस के लिये अमरीका का नाम लेते हैं। या तो वह फायदा उठा रहे हैं या हो सकता है कि बाहर वालों के कहने से ऐसा कह रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी मदद की है उन से हमें रोज-रोज मदद चाहिये, लेकिन उन के प्रति रंगा साहब हमारे दिल में सन्देह पैदा करते हैं। मैं रंगा साहब से प्रार्थना करूंगी कि वह ऐसा न करें। मैं तो अपने अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के लोगों से भी प्रार्थना करूंगी कि अगर रंगा साहब दोस्ती में ऐसा करते हैं तो वे नादान दोस्त हैं, और उन का साथ उन लोगों को छोड़ देना चाहिये। और अगर रंगा साहब कोई ऐजन्ट हैं तो उस एजेन्ट को उन लोगों को डिसमिस कर देना चाहिये क्योंकि इस वक्त देश का बच्चा-बच्चा अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन का आभारी है। लेकिन जब रंगा साहब उस के साथ यह जोड़ देते हैं कि सामाजवादी प्लैन को तोड़ दिया जाय, उस समय देश के लोग उन देशों को कुछ शुबह। की नज़र से देखते हैं।

दूसरा जो ऐतराज मुझे है वह यह कि रंगा साहब ने औरतों के काज को बहुत ऐडवोकेट किया और कहा कि उन के जेवर ले लिये गये जिस से कि देश की स्त्रियां बहुत दु:खी हैं, परेशान हैं, डर गई हैं। हिन्दुस्तान की स्त्री क्या चाहती है ? हिन्दुस्तान की स्त्री चाहती है कि उस के बच्चे को अच्छा खाना मिले, अच्छा पढ़ने को मिले, उस के

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

बच्चे की सेहत अच्छी हो और उस का बच्चा जब बड़ा हो जाय तो उस को रोजगार मिले। आज हिन्दुस्तान की स्त्री हिन्दुस्तान की गरीब जनता की मां, आज़ादी क्यों चाहती है? इस लिये कि उन के बच्चों की तरक्की हो। आज समाजवाद चला जाय, हिन्दुस्तान की स्त्री इस को नहीं चाहती। अगर रंगा साहब ऐसा समझते हैं कि हिन्दुस्तान की स्त्री को सोना चाहिये, तो हिन्दुस्तान की स्त्री ऐसी नहीं है। वह सोना ले कर क्या करेगी? हिन्दुस्तान की स्त्री सोना तो क्या सभी कुछ दे सकती है अपने देश के और अपने बच्चों की तरक्की के लिये। हिन्दुस्तान की स्त्री, भारतीय नारी आज बच्चे दे रही है, कुर्बानी के लिये भाई दे रही है, पति दे रही है जो कि सीमा पर जा कर लड़ने को तैयार हैं, तब स्त्री के केस को ऐडवोकेट करना कि हिन्दुस्तान की स्त्री को सोना चाहिये, यह स्त्री का बड़ा अपमान करना है, जो कि रंगा साहब ने किया। हिन्दुस्तान की स्त्री को समाजवादी प्लैन चाहिये, हिन्दुस्तान की स्त्री को देश की रक्षा चाहिये। मैं उन भाइयों से कहूंगी जिन का केस ऐडवोकेट करते हुए यहां कहा गया है कि सुनारों के पास आज काम नहीं है, भारत में, रंगा साहब से कहूंगी कि हिन्दुस्तान की स्त्री नहीं चाहती कि वह सोने की बात कह कर हिन्दुस्तान की स्त्री ो बेवकूफ बनायें। आज हिन्दुस्तान की स्त्री सोने के जेवर पहन कर बेवकूफ नहीं बनाना चाहती। मैं कहूंगी कि सुनार भाई कारखाने बनाये, जिन में देश के बच्चों को काम मिले, सुनार भाई आज बम और गोले बनायें जिस से कि हमारे देश की रक्षा हो और आज़ादी बनी रहे।

(अन्तर्बाधाएं)

**अध्यक्ष महोदय**: आप तो यहीं कारखाने बनाने लगीं।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी**: इस तरह से भारतीय नारी का नाम ले कर अगर यहां रंगा साहब पूंजीपतियों, मुट्ठी भर लोगों के केस को, जिन के हाथों में सोना है, राजाओं और महारानियों के केस को ऐडवोकेट करते हैं, तो उस को हम बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। इस लिये मैं कहना चाहती हूं कि बाहर से ऐड लेने के बहाने हमारी प्लैन को कटवाने की बात जो यहां होती है उस को हमें रोकना चाहिये।

हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि "आज अपने सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना, विचार, इजहार, विश्वास, निष्ठा और पूजा की आजादी, दर्जे की बराबरी" यह सब करना हमारी सरकार का काम रहा है। आज हमारे सामने सवाल उठा कि इमर्जेन्सी रहे या नहीं रहे। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि अगर इमर्जेन्सी का इस्तेमाल नहीं करना है वह क्यों रहे। इमजन्सी रहनी चाहिये। पर उस का कहां इस्तेमाल हुआ है? सरे आम कहा जाता है कि सरकार को पैसा मत दो, उस पर हमारा विश्वास नहीं है, सोना मत दो, सरकार पर विश्वास नहीं है। सरे आम कहा जाता है कि इस सरकार में समझ नहीं, अक्ल नहीं, वह सम्भाल नहीं सकती है। इतना ही नहीं, भाई भाई में, बिरादरी बिरादरी में, जाति जाति में आज भी ज़हर अथवा विष फैलाया जाता है। लेकिन सरकार अपनी इमजन्सी की पावर्स को इस्तेमाल नहीं करती है। आज जो नई और सब से खराब बात हम ने देखी, और जिस की हमें सरकार से शिकायत करनी है वह यह है कि जब कि हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि हम यहां पर नागरिक नागरिक को बराबर समझते हैं, हमारे देश में जो राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो हमारी आज़ादी का

दिन मनाया गया, उस में उस जमात को जगह दी गई जो कि देश के तमाम नागरिकों को नागरिक मानने के लिये तैयार नहीं है, जो जमात देश के झंडे को अपना झंडा मानने के लिये तैयार नहीं हैं, जो जमात अपने देश के तमाम लोगों को एक बराबर मानने के लिये तैयार नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को हमारे यहां उस सड़क पर मार्च करवाया गया जिस सड़क पर गांधी जी की अर्थी को हम ने निकाला था।

**श्री बड़े** (खारगोन) : उस वक्त हमारे हाथ में नैशनल फ्लैग था। राष्ट्रीय झंडा उन लोगों के हाथ में था और आर० एम० एस० को कोरपोरेशन ने बुलाया था। क्या हमको चलने का अधिकार भी नहीं है। २६ जनवरी को। हम भी नागरिक हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके। अब वह बैठ जायें।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि आज इमर्जेन्सी के वक्त खास कर हमारे देश के लिये, तमाम नागरिकों को....

**श्री रामेश्वरानन्द** : वह कह रहीं हैं कम्यूनिस्टों से प्रेम करो, औरों से मत करो क्योंकि उन के पति देव कम्यूनिस्ट हैं।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : अगर हमारी सरकार इमर्जेन्सी की पावर्स को इस्तेमाल नहीं करती है तो इमर्जेन्सी को हटा दिया जाय, और अगर वह इमर्जेन्सी की पावर्स को इस्तेमाल करती है तो हमारे यहां इमर्जेन्सी रहनी चाहिये और कारखानों के बाहर और भीतर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम कर के देश की रक्षा के लिये तैयार रहना चाहिये।

**श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** (छपरा) : अध्यक्ष महोदया मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। कब्ल इस के कि मैं राष्ट्रपति महोदय के विचारों के ऊपर अपना मत प्रकट करूं, मैं उस दिन जो राष्ट्रपति के प्रति अशोभनीय घटना घटित हुई उस के सम्बन्ध में अपनी क्षमा याचना करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

आज लगभग बारह वर्षों से देश के राष्ट्रपति हिन्दी भाषा भाषी पूज्य राजेन्द्र बाबू थे। मेरा ऐसा इम्प्रेशन था कि बारह वर्षों तक राजेन्द्र बाबू पहले हिन्दी में और उस के बाद अंग्रेज़ी में अपना अभिभाषण दिया करते थे। लेकिन एक हिन्दी भाषा भाषी और हिन्दी हिमायती ने, जिन्हें किसी से भी कम हिन्दी से प्रेम नहीं है, बतलाया कि राजेन्द्र बाबू भी जब पूर्ण स्वस्थ थे तो हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ते थे। पहले वह अंग्रेज़ी में अपना अभिभाषण पढ़ते थे और बाद में हिन्दी में पढ़ते थे।

इसके अलावा मैं उन भाइयों के प्रति भी क्षमा याचना करना चाहता हूं जोकि हिन्दी भाषा भाषी नहीं हैं। इस से उन भाइयों के मन में यह आशंका उत्पन्न हो सकती है कि हिन्दी भाषी भाषा ज़ोर जबरदस्ती कर के हिन्दी को उन के ऊपर लादना चाहते हैं। इसलिए एक हिन्दी भाषा भाषी होने के नाते मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह भावना जिसके वशीभूत होकर राष्ट्रपति के संसद् के सम्मुख अभिभाषण के समय इस किस्म का प्रदर्शन किया गया, वह उन की अपनी व्यक्तिगत भावना हो सकती है या उनकी पार्टी की हो सकती है जिस जमात से कि वे आते हैं। पर उस से हिन्दी भाषा भाषियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। हिन्दी भाषा भाषियों का उन के प्रति भी उतना ही आदर है जितना कि

[श्री राम शेखर प्रसाद सिंह]

उनका जो इस देश में हिन्दी नहीं जानते हैं ? इस देश में अभी भी एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहां कि लोगों को हिन्दी की जानकारी नहीं है और विशेष प्रयास करने पर भी हिन्दी को सीखने में उन को कठिनाई होती है। जब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था और जब मैं अपने प्रदेश में था तो मेरा भी यह विचार था कि हिन्दी की उन लोगों के प्रति अश्रद्धा है और वे हिन्दी की जानकारी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन यहां आने पर मुझे यह चीज़ समझ में आ गई कि वाक्ई हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने में उनको कठिनाई का अनुभव होता है और प्रयास करने पर भी वे उसे जल्दी नहीं सीख सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी हिन्दी के प्रति अश्रद्धा है या वह हिन्दी सीखना नहीं चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर जो अशोभनीय कांड यहां घटित हुआ उस के लिए मैं समस्त हिन्दी भाषा भाषियों की ओर से उन से क्षमा याचना करना चाहता हूं और राष्ट्रपति महोदय से भी क्षमा चाहता हूं जो कि उनके प्रति ऐसा अशोभनीय प्रदर्शन हुआ।

आज देश में संसदीय पद्धति के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और आदर का भाव है और सभी लोग संसद् के सदस्यों को आदर की दृष्टि से देखा करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे जैसा कि अभाग्यवश उस दिन किया गया तो देशवासियों के दिलों में संसदीय पद्धति के प्रति अनादर पैदा होगा और ऐसी बात पैदा हो जायगी जिससे कि देश का कल्याण नहीं होगा और कोई दूसरी ही व्यवस्था उत्पन्न करनी पड़ेगी।

गत सोमवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति महोदय ने जो भाषण दिया उस के तीन अंग हैं, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति, आन्तरिक व्यवस्था एवं भारत चीन सीमा विवाद। तीनों पर उन्होंने प्रकाश डाला अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में उन्होंने संतोष जाहिर किया है। इस में हम लोग उन से सहमत है हमारे निकटवर्ती राज्य नैपाल और पाकिस्तान के साथ अपनी मौजूदा समस्याओं को सुलझाने और उनके साथ अपने सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए हमारी सरकार सचेष्ट है और चिंतित भी है। अभी कुछ ही दिनों बाद हमारे आदरणीय नेता और गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री नैपाल जाने वाले हैं और मेरा अपना विश्वास है कि नैपाल से हमारी मित्रता पुनः वैसी ही कायम हो जायगी जैसी कि पहले थी।

एक दूसरे मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने पिछले दिनों पाकिस्तान से मौजूदा समस्याओं को सुलझा ने और उससे अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कई बार प्रयास किया है और कई मीटिंगें इस सम्बन्ध में हो चुकी हैं। मेरी ऐसी आशा और विश्वास है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारा मुख्य समस्याओं पर समझौता हो जायगा और अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे और दोमों पड़ौसी देशों में मैत्रीभाव कायम हो जायेगा।

जहां तक दूसरे देशों का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि विदेशी नीति हमारी अच्छी रही है। विदेशों में जो हमारे राजदूत नियुक्त हैं वे काबिल और सुयोग्य हैं लेकिन काबि-लियत के साथ उन के चुनाव में कुछ देश भक्ति का भी खयाल रहना चाहिए। प्राग के पास हमारे देश का नक्शा नहीं था और जिस नक्शे को डांगे साहब को देना पड़ा जिससे कि उनकी जानकारी हुई। इससे मालूम होता है कि जो हमारे राजदूत विदेशों में रहते हैं वे सुयोग्य रहते हुए भी कहीं कहीं उन में देश की चिन्ता की कमी और देशभक्ति की कमी

रहती है । इसलिए मेरा सरकार को नम्र सुझाव है कि इनकी बहाली के वक्त देशभक्ति को प्रथम स्थान देना चाहिए और बाद में योग्यता और अन्य चीजों का ध्यान होना चाहिए। ऐसा करने से हमारे देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा ऊंची उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

अध्यक्षम होदय, आन्तरिक व्यवस्था के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने संतोष जाहिर किया है। कृषि और उद्योग के मामले में देश की काफी प्रगति हुई है । लेकिन कुछ दिन पहले कलकत्ते की एक सभा में हमारे माननीय योजना मंत्री ने कृषि या उद्योग के मामले में पूरा संतोष जाहिर नहीं किया। उन के इस विचार से हम भी सहमत हैं और इस दृष्टि से सरकार को ज्यादा चेष्टा दिखाने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को उन कामों के लिए जवाबदेह बनाने की जरूरत है जिनको कि इन कामों की जानकारी के साथ साथ उनमें श्रद्धा भी हो । अभी देखा जाता है कि योजनाएं बना दी जाती हैं और ऐसे लोगों को जिनकी इन योजनाओं में श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है उनको उनके वास्ते जवाबदेह बना दिया जाता है । फलस्वरूप योजना में सफलता नहीं होती है और योजना में कमी होती । इसलिए यह आवश्यक है कि जिस योजना के लिए जो व्यक्ति लगाया जाय । और जवाबदेह बनाया जाय उसकी उस में श्रद्धा हो। जिस योजना में आदमी रक्खा जाय और जवाबदेह बनाया जाय उस में उस योजना के प्रति आस्था और विश्वास रहना जरूरी है और केवल उन्हीं लोगों को लिया जाय।

राष्ट्रपति ने जिस वीरता और संकल्प के साथ इस संकटकालीन घड़ी में देशवासियों का आवाहन किया है उस का सारे देश में स्वागत हुआ है । वह हमारे देश में आदर के सूचक बन गये हैं। वह एक महान् दार्शनिक हैं। शब्दों का समुद्र उन के समक्ष मौजूद है और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि प्रशासन के काम में केवल राजनीतिक व्यक्ति ही दक्ष और कुशल नहीं हो सकता है बल्कि दार्शनिक और विद्वान लोग भी इस काम को सुचारु रीति से कर सकते हैं। जिनका किसी पार्टी विशेष या दल से सम्बन्ध नहीं होता है वह देश की भावनाओं का विशेष वीरता और विशेष संकल्प के साथ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं बनिस्बत उन व्यक्तियों के जिनका कि किसी पार्टी या दल से सम्बन्ध रहता है। उनकी भावनाओं का देश ने स्वागत किया है और आज राष्ट्रपति के रूप में सारे देश की भावनाओं के प्रतीक बन कर हमारे सामने मौजूद हैं।

भारत चीन विवाद के सम्बन्ध में उन्होंने विशेष ध्यान दिया है । उन्होंने कहा है कि देश में शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हुए भी हम किसी भी तरीके से प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और देश की रक्षा में किसी बात की कमी नहीं करेंगे और इस काम को पूरा करने के लिए हमारी सरकार सचेष्ट है । इसी अभिप्राय: से यह संकटकालीन स्थिति जो हमारे देश में कायम है उस को जारी रक्खा जा रहा है । इस दृष्टि से हमारे देश के नागरिकों ने जो सहयोग दिया है वह निश्चय ही प्रशंसा की बात है । एक स्वर से देहात से ले कर शहरों तक के लोगों ने इस में एकता की भावना दिखलाई है और एक आवाज से जिस तरीके से चीनी आक्रमण का विरोध किया है और उसके विरुद्ध प्रदर्शन किया है वह सचमुच ही हमारे देश के लिए एक गौरव की वस्तु है ।

यह बात सही नहीं है जैसा कि कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि जोर जबरदस्ती से चन्दा वसूल किया जाता है । लोगों ने बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से चंदा दिया है क्योंकि लोगों के हृदय में देशभक्ति की एक ज्वाला है जो कि इसके लिए उनको प्रेरित करती है ।

[श्री राम शेखर प्रसाद सिंह]

देशवासी हर प्रकार से देश की रक्षा के लिए तैयार हैं और वे उसके लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। लेकिन उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कि इसके विरुद्ध शिकायत की, उनकी भावनाओं से इतना मैं जरूर सहमत हूं कि चंदा वसूली का काम जिस पवित्र भावना से होना चाहिए उस भावना से न हो कर एक प्रचार का दृष्टिकोण उसमें रक्खा गया है क्योंकि अगर एक बार एक ब्लाक में चंदा ५००० के करीब वसूल हुआ तो फिर वही ५००० की रकम ५ मंत्री उस ब्लाक में गये तो ५ बार उसका प्रचार किया गया। जिस पवित्र भावना से लोगों ने सरकार का साथ दिया और पूरी सहायता की, जिन लोगों पर यह रुपया वसूल करने की जवाबदेही थी, उन लोगों ने उस पवित्र भावना से काम नहीं लिया। यह एक दुखद बात है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इस में कोई सन्देह नहीं कि खर्च में कमी करने की बहुत आवश्यकता है। आज कांफरेंसिज होती हैं और इसके साथ ही हवाई जहाज, स्टाफ कार और टेलीफोन आदि के इस्तेमाल का प्रश्न सामने आता है। यह कहा जा सकता है कि चालीस पचास हजार या दो चार लाख रुपए की बचत से क्या हो सकता है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के खर्च से लोगों की अन्तरात्मा और भावनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लोग महसूस करते हैं कि एक तरफ तो ये लोग दो दो पैसे के लिए भिखारी बने हुए हैं और दूसरी तरफ ये हवाई जहाजों का इतना इस्तेमाल करते हैं--जहां बड़ी आसानी से रेल के द्वारा जा सकते हैं, वहां पर ये हवाई जहाज से जाते हैं। लोगों पर इस का बहुत बुरा असर पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यद्यपि पहले पटना से सरकारी काफिला बड़ी आसानी से एक प्लेन में दिल्ली पहुंच जाता था, लेकिन इमर्जेन्सी के इस जमाने में इस काम के लिए दो हवाई जहाज इस्तेमाल किये जाते हैं। आज सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आवश्यक खर्च है, वह जरूर किया जाये, लेकिन जो अनावश्यक खर्च है, जिस में किसी तरीके से कमी की जा सकती है, उस को कम करने का प्रयास किया जाये।

आज सारा देश वार मूड में है। आज देश के एक एक नागरिक के दिल में युद्ध-भावना जाग्रत है। सभी लोग इस बात को जानने के लिए चिन्तित हैं कि लड़ाई के लिए सरकार की तैयारी क्या है। अगर आज कोई भी आदमी चाइनीज के प्रति कोई रोष प्रदर्शन करता है और इस संकट कालीन स्थिति के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता जाहिर करता है, तो, क्या आप जानते हैं कि उस के लिए क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि यह व्यक्ति जवाहरलाल जी के खिलाफ है। मालूम होता है कि आज चाइना के सब से ज्यादा दोस्त जवाहरलाल जी हैं। कौन लोग ऐसा कहते हैं? ऐसी बातें वे लोग कहते हैं, जिन्होंने कभी भी पंडित जी का साथ नहीं दिया। १९४२ की क्रांति के जमाने में, जब कि हम लोग जेलों के सीखचों में बन्द थे, ये लोग कहा करते थे कि हम ट्रेटर्ज टु दि कंट्री हैं, उस वक्त लड़ा जाने वाला युद्ध पीपल्ज वार है और उस में सहायता न देने के कारण जवाहरलाल जी बुरे हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं कि उस समय "भारत छोड़ो" का नारा लगा कर कितने ही नौजवान फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, लेकिन इस प्रकार की बातें कहने वाले लोग आज जवाहरलाल जी के सब से नजदीक और हमारे माननीय नेता, श्री त्यागी, उन से दूर चले गए कहे जाते हैं।

**श्री त्यागी** : मैं प्रोटेस्ट करता हूं। मैं उन ,से दूर नहीं हूं।

**श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : उन के बारे में ऐसा कहा जाता है। मैं ने यह नहीं कहा कि वह दूर हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो श्री त्यागी की मदद कर रहे हैं।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : माननीय सदस्य का इशारा किस तरफ है ?

**अध्यक्ष महोदय** : उन का इशारा आप की तरफ भी हो सकता है। मेरा इशारा शर्मा जी की तरफ है।

**श्री दी० चं० शर्मा** : शुक्रिया।

**श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिला कर हर एक लड़ाई में पंडित जी का साथ दिया, वे कभी भी उन से दूर नहीं हो सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में जवाहरलाल जी जितने मजबूत हैं, उतने मजबूत वह जिन्दगी में कभी भी नहीं थे। आज ४४ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जवाहरलाल जी हैं और हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा उन के साथ है। सिर्फ वही लोग उन के साथ नहीं हैं, जो कहते हैं कि उन के हाथ मजबूत करने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल जी कभी भी कमजोर नहीं रहे हैं और न हैं।

देश में एक ऐसी एम्बीशस पार्टी है, जो कि इस संबंध में बात चलने पर कहती है कि आल्टरनेटिव लीडरशिप होनी चाहिए। अगर इस बारे में उन से बात करें, तो वे भी स्वीकार करेंगे कि पंडित जी इंडिस्पेन्सेबल हैं। पंडित जी केवल जवाहरलाल ही नहीं हैं, बल्कि वह हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की युद्ध करने वाली मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। जिन लोगों ने कुछ दिन पहले कोलम्बो प्रस्तावों को बुरा बताया था, उन को भी स्वीकार करना पड़ा कि प्रधान मंत्री ने उन को मान कर अच्छा किया।

**श्री रामेश्वरानन्द** (करनाल) : नहीं, नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या स्वामी जी की तकरीर साथ साथ चलती रहेगी ?

**श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : हमारे प्रधान मंत्री हमारे देश की चीन का मुकाबला करने की भावनाओं का प्रतीक हैं। जो लोग चाहते हैं कि चाइनीज को किसी भी तरीके से इस देश से निकाला जाए, उन को मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करें, उस में किसी तरीके से बाधा डालना देश को कमजोर करना है। जो लोग उन की पापुलेरिटी से लाभ उठा कर खुद पापुलर बनना चाहते हैं, केवल वही कहा करते हैं कि पंडित जी कमजोर हैं, उन को मजबूत बनाना चाहिए। उन को कमजोर कहने की बात गलत है।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय को उन के भाषण के लिए धन्यवाद देता हूं।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (अम्बुल पुझा) : पाकिस्तान और चीन के बीच जो करार हुआ है, उसको लेकर माननीय सदस्यों में काफी परेशानी है। मेरा निवेदन है कि यद्यपि भारत की यह हार्दिक इच्छा है कि दोनों देशों के बीच शांति और मैत्री हो। परन्तु पाकिस्तान जरूरत से तनिक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासुदेवन नायर]

अधिक ही चतुर नीति अपना रहा है । स्पष्ट ही है कि यह नीति मित्रता के राह में बाधक सिद्ध होगी । भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता वार्ता चल रही है जम्मू तथा काश्मीर का मामला मुख्य है । पाकिस्तान इसके सम्बन्ध में चीन के साथ कोई समझौता करना चाहता है । किसी भी दृष्टि से पाकिस्तान को ऐसा करने का ,अधिकार नहीं है । भारत इस प्रकार के समझौते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा । यह तो पूर्ण रूप से अवैध बात होगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं काश्मीर तथा अन्य मामलों पर भारत की जो बातचीत हो रही है उसका पूरा विवरण संसद के समक्ष आना चाहिये । पता चला है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के विभाजन के बारे में कोई योजनायें बनाई जा रही है । इस सम्बन्ध में फैले हुये आतंक को दूर किया जाना चाहिये । क्या इसके लिये पश्चिमी शक्तियां कुछ दबाव डाल रही हैं । मेरे विचार में इन सब बातों का एक ही हल है कि हम अपने साधनों का विकास करें, प्रतिरक्षा को मजबूत करें । इस के साथ शांति पूर्ण ढंग से मामलों को सुलझाने के लिये भी तैयार रहें । हमें इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिये कि अन्य देशों की ओर न देखना पड़े । हमें अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी होगी । भय को दूर कर अपने पर भरोसा करना चाहिये ।

हमने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, इसके लिये विश्व भर में भारत की सराहना की गई है । चीन को सारे संसार से पृथक् कर दिया गया है । मेरा विचार है कि इन प्रस्तावों के लिये कोलम्बो राष्ट्रों को दोष देना अनुचित है । इस बारे में हमें दृढ़ नीति अपनानी चाहिये । यह हर्ष की बात है कि हम अपनी नीति पर दृढ़ हैं । हम अपने सम्मान और गौरव का ध्यान रखते हुए सीमा समस्या का हल तलाश करने में किसी भी अवसर का स्वागत करेंगे । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने वर्तमान आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने में भी कुछ गलत बातें की हैं । यह बातें राष्ट्रीय रक्षा कोष में धन संग्रह करने तथा "होमगार्डों" में स्वयंसेवकों इत्यादि को भर्ती करते समय भी की गई है । पता चला है कि केरल में कांग्रेस दल द्वारा दी गई सूचियों के आधार पर भर्ती की गई है । यह तो बहुत ही आपत्तिजनक बात हैं । यदि सचमुच ऐसा किया गया है तो इस बात की जांच की जानी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत के साम्यवादी दल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लेने का कोई औचित्य नहीं है । साम्यवादी दल ने वर्तमान आपातकाल के दौरान सरकार को पूर्ण रूप से समर्थन देने का प्रस्ताव पास किया है । हमें बाहर से सहायता लेने के बजाय अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये ।

†**श्री गजराज सिंह राव** (गुड़गांव) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का प्रायः प्रयोग होता रहा है । तटस्थता का शब्द उसमें से एक है । तटस्थता का कई एक क्षेत्रों में यह मतलब लिया जा रहा है कि हम सभी मामलों में विश्व से तटस्थ रहते हैं । इसका यह मतलब नहीं है । इसका अभिप्राय: तो यह है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी एक विचारधारा से बंधे हुए नहीं है । दूसरा शब्द आपात है इन के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस समय आपात को समाप्त कर देने, अथवा तटस्थता की नीति को छोड़ देने से देश को कुछ लाभ नहीं पहुंच सकता । इसके विपरीत इसकी कुछ हानि होने की ही सम्भावना है । सरकार को जागरूक हो कर कार्य करना है । उन लोगों के विरुद्ध

†मूल अंग्रेजी में

आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये जो कि चीन के लिये कार्य कर रहे थे और अब हमारे प्रतिरक्षा प्रयत्नों में बाधा पहुंचा रहे हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि आपातकालीन स्थिति कायम रहनी चाहिये।

यह कहना गलत है कि राष्ट्र रक्षा कोष के लिये जोर जबरदस्ती से काम लिया गया है। इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि हमारी जनता के निर्धन वर्गों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में सब से अधिक धन दिया है। धनियों, व्यापारियों और पूंजीपतियों ने तो इस दिशा में अपना कर्त्तव्य निभाया ही नहीं।

परिस्थितियां कुछ भी हों हमने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करके देश के गौरब को बढ़ाया ही है। हम उन मित्र देशों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपातकालीन अवस्था में हमारी सहायता की है। अमरीका तथा ब्रिटेन इनमें प्रमुख हैं। हमें इस पर भी आत्मसन्तोष है कि भारतीय सिपाहियों ने लद्दाख में अपने बलिदान द्वारा वीरता का परिचय दिया है। हमारी सेनाओं ने बड़े साहस के साथ युद्ध किया है। मेरा कहना है कि राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख करना चाहिये था। इन सैनिकों का उत्साह बहुत बढ़ा चढ़ा है। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि यह उत्साह बना रहे। किसी भी हालत में यह उत्साह ढीला नहीं पड़ना चाहिये। इसके अतिरिक्त इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि इन सैनिकों के परिवारों को उचित सहायता उपलब्ध होती रहे, और उनका बोझ हलका होता रहे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा प्रयत्नों को उन विकास खंडों को नहीं सौंप देना चाहिये जो कि भारी षड़यन्त्रों का केन्द्र बन गये हैं।

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धारवाड़—उत्तर) : मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिये दिये जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। उनके भाषण से उनका महान व्यक्तित्व और देश का गौरव स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने देश को उत्थान के लिये आह्वाहन किया :—

उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत

मैं इसमें ब्राह्मण ग्रन्थों से २ पंक्तियां और कहना चाहती हूं :

आस्ते भग आसीनस्य उर्ध्वस्तिठरति तिष्टतः।
श्येते निपद्यमानस्य चराति चरतो भग : ॥

राष्ट्रपति जी ने विभिन्न प्रकार के देश में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया है। उन सभी विषयों पर प्रकाश डाला है जो कि देश के समक्ष है। देश के ७० प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। अतः कृषि के प्रोत्साहन की ओर विशेष ध्यान देना ही होगा।

यह अत्यन्त खेद का विषय है कि उपलब्ध सिंचाई के साधनों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया गया, और विभिन्न स्वीकृत योजनाओं को भी कार्यान्वित नहीं किया गया। इन मामलों की जांच करनी चाहिये। यह कहना उचित नहीं है कि कृषक द्वारा स्वयं इन साधनों से लाभ उठाना चाहिये। मेरा कहना यह है कि प्रशासकों को कृषकों के लिये इन सुविधाओं का पूर्ण ज्ञान भी उपलब्ध करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सरोजिनी महषी]

हमें यह बताया जाता है कि मध्य-कालीन अथवा दीर्घ-कालीन ऋणों के रूप में कई करोड़ रुपया उपलब्ध किया गया है; परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि इतना धन देने के बावजूद भी उत्पादन हमारी आशाओं के अनुसार क्यों नहीं बढ़ा है ? कृषि उत्पादन में ६ प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ौत्री की हमें आशा थी, परन्तु १० वर्ष में केवल ३.८ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है ।

धन उपलब्ध कर के सिंचाई सुविधायें बढ़ाने के साथ साथ, भूमि की चकबन्दी, खाद का उचित वितरण विद्युत का सम्भरण, उन्नत बीजों का उचित सम्भरण, आदि बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये, क्योंकि इन सब बातों का कृषि विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

राष्ट्रपति द्वारा औद्योगिक विकास की भी चर्चा की गई है, परन्तु जहां हम ९ प्रतिशत के बढ़ जाने की आशा रखते थे वहां गत वर्ष औद्योगिक उत्पादन केवल ६ प्रतिशत ही बढ़ा है । इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में नियोजन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है । योजना आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र में किये गये कार्यों की जांच करने का जो निश्चय किया गया है वह प्रशंसात्मक है । इस जांच से मालूम हो जायगा कि उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार क्यों नहीं बढ़ पाया ।

देश की प्रयोगशालाओं में भी पूर्वधारणाओं के अनुसार कार्य नहीं हुआ है, अतः इन के कार्यों की जांच के लिए वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय ने विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं प्राप्त करने का निश्चय किया है, । क्या हमारे देशी विशेषज्ञ इस जांच-कार्य के लिए कार्यक्षम नहीं हैं ? यदि नहीं, तो अब तक कार्य किस प्रकार हो रहा था ? यह बातें हमारे लिये शोचनीय हैं ।

मैं यह जानना चाहती हूं कि सेवानिवृत्ति की आयु ५५ से बढ़ा कर ५८ करने का कारण क्या टेकनिकल क्षेत्र में सेवा करने वालों की कमी है ? यदि ऐसा है, तो सरकार देश में अधिक टेकनिकल संस्थायें स्थापित करने तथा टेकनिकल शिक्षा के विस्तार के लिये किस प्रकार प्रयास कर रही है ? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अधिक ध्यान दिया है, परन्तु इस के बावजूद भी हम देखते हैं कि तृतीय योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष तक की आयु श्रेणी में केवल ६० प्रतिशत बालक ही प्राईमरी स्कूलों में जा सकेंगे । इस से सिद्ध होता है कि इस क्षेत्र में भी हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो सके ।

विश्वविद्यालयों में भी कई प्रकार की अनियमिततायें देखने में आई हैं । यद्यपि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय हैं, फिर भी सरकार का कर्तव्य है कि वह समय समय पर उन के नियमित रूप से काम करने की जांच करती रहे । एक उदाहरण हमारे समक्ष गौहाटी विश्वविद्यालय का है । पार्वत समिति द्वारा उस विश्वविद्यालय के कार्यों में पाई जाने वाली अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है । विश्वविद्यालय सहायता आयोग की ओर से काफी धन इस विश्वविद्यालय को सहायता के रूप में दिया गया, अतः इस के कार्यों का निरीक्षण करना आवश्यक था । पार्वत समिति भी शिक्षकों के शोर मचाने पर नियुक्त की गई । यह खेदजनक बात है । ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिये हमें प्रयत्न करने चाहिएं ।

प्रशासनिक कार्यों में भी अकुशलता पाई जाती है । जहां हम यह चाहते हैं कि लोकतंत्रात्मक स्थापनाओं में हर स्तर पर जनता भाग ले, वहां प्रशासनिक मशीनरी में से भ्रष्टाचार दूर करने, और इसे अधिक कार्यक्षम बनाने की चेष्टा भी होनी चाहिए ।

आय-कर की २५३ करोड़ बकाया राशि की चर्चा समाचारपत्रों ने की है । कितने खेद का विषय है कि एक ओर तो हम जनता तथा श्रमिकों से राष्ट्रीय रक्षा कोष में उदारता से धन देने की अपीलें करते हैं, और दूसरी ओर प्रशासन की अकार्यकुशलता के कारण इतनी बड़ी रकम

हम वसूल नहीं कर सकते। लोक लेखा समिति द्वारा प्रशासन की उन गतिविधियों की त्रुटियों की ओर संकेत किया गया है, जिन के कारण कि यह स्थिति उत्पन्न हुई है । इस के साथ साथ कर-अपवंचन के कारण भी बहुत सी रकमें प्राप्त नहीं हो सकीं। सरकार को इन सब अनियमितताओं की ओर ध्यान देना चाहिए ।

इतिहास इस बात की गवाही देता है कि हमारे देश को सदैव एकता न होने के कारण मुंह की खानी पड़ी। परन्तु आज जिस प्रकार इतिहास से शिक्षा प्राप्त कर, जनता ने एकता की भावना का प्रदर्शन किया है, वह उत्साहवर्धक है। सोने के रुप में हमारे देशवासियों द्वारा, विशेषकर स्त्रियों द्वारा, बहुत दान दिया गया है । यह बात जनता के उत्साह तथा बलिदान की भावना की द्योतक है।

विरोधी पक्षों द्वारा जिस भावना का प्रदर्शन किया जाता है, वह खेदजनक है। विरोधी दलों का कर्त्तव्य होता है कि उन मामलों में जिन में सरकार किसी प्रकार ठीक ढंग से न सोचे वह सरकार का ध्यान आकर्षित कर सहायक सिद्ध हों, परन्तु होता यह है कि हर विषय में विरोध की नीति अपनाई जाती है। भाषा के सम्बन्ध में भी जिस प्रकार विरोधी पक्षों ने प्रतिक्रिया दिखायी हैं, वह निन्दा योग्य है। हिन्दी में भी जानती हूं, और चाहती हूं कि इस का विकास हो, परन्तु इस आधार पर सभा के आचरण नियमों का उल्लंघन करना सर्वथा अनुचित है। हमें सदस्य होने के नाते अपना सम्मान भी बनाये रखना है ।

कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी विरोधी पक्षों द्वारा उचित नीति नहीं अपनाई गई। हमें आज स्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हो कर देखना है। क्यूबा के मामले में रूस द्वारा एक नीति अपनाये जाने पर पूर्व और पश्चिम के परस्पर सम्बन्धों में परिवर्तन आ चुका है । हमें अपनी चीन अथवा पाकिस्तान सम्बन्धी नीति को इसी प्रसंग में देख कर निर्धारित है करना।

हमें अपने देश का सम्मान बनाये रखना है और हर तरह से इसकी अखण्डता को कायम रखना है ।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर): राष्ट्रपति द्वारा अपने भाषण में कहा गया है कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, विश्वशांति की महत्ता पर बल देते हुए, दिलचस्पी ली, और कि सरकार ने आशा की थी कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्वक रहेगा ; अतः कि जो भी समस्यायें उत्पन्न होंगी उन को शांतिपूर्वक ढंगों से सुलझाया जायगा ; मेरा निवेदन है कि यह सब बातें भ्रम मात्र थीं। वास्तव में, हमारी सरकार आत्मतुष्टि की भावना से मीठी नींद सो रही थी, और जब चीन और पाकिस्तान में कुछ और घटनायें हुईं, जब हमारे सीमावर्ती क्षत्रों में हल चल हुई, तो हमारी सरकार आश्चर्य चकित रह गई ।

हम ने चीन की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, परन्तु चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियों का उल्लंघन कर, बरबरतापूर्ण हम पर आक्रमण किया। ऐसे आक्रमण का अन्य उदाहरण हमें प्रथम अथवा द्वितीय महायुद्ध में भी नहीं मिलता । इस आक्रमण से चंगीज़खां, नादरशाह, आदि के इतिहास को फिर से जीवित कर दिया । मुझे हर्ष हुआ कि राष्ट्रपति ने इस आक्रमण को विश्वासघात का नाम दिया। निसंदेह हमारा सर्वप्रथम यह कर्त्तव्य है कि अपनी एक एक इंच भूमि को आक्रमणकर्त्ताओं के पंजे से छुड़ायें। यही हमारे लिये सम्मानजनक भी है अतः इस संबंध में जो भी पग उठायें गये हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन, और राष्ट्रीय रक्षा कोष

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री अणे]

का चालू किया जाना, आदि, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमें अपनी रक्षा की आवश्यकताओं को सम्मुख रख कर ही अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना, तथा आयुद्ध कारखानों में उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए ।

चीनी सेना का पीछे हटना एक धोखा है। शांति उसी दिन स्थापित होगी जब चीन हमारी भूमि से पीछे हट जायेगा।

अभिभाषण में कहा गया है कि चीन का सामना करने के लिये हमें काफी समय की आवश्यकता है और इस उद्देश्य से यह आवश्यक है कि भारतीय सेना आधुनिक आयुधों से लैस हो । परन्तु चीन अपने एकपक्षीय युद्ध-विराम के पश्चात् भी लद्दाख और मध्य क्षेत्र के कुछ भागों में हमारी भूमि पर रहेगा । मैं यह चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जाये कि किसी आकस्मिक आक्रमण का सामना करने के लिये हम तैयार हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ गोपनीय बांत सरकार द्वारा बताई जायें, परन्तु मोटे तौर पर ऐसा आश्वासन देना भी आवश्यक है ताकि जनता में आत्म-विश्वास बढ़े ।

अभिभाषण में देश की रक्षा के लिये सरकार की कटिबद्धता की चर्चा तो की गई है, परन्तु इन शब्दों का, कि "वह तब तक दम न लेंगे जब तक कि चीनी भारतीय राज्य-क्षेत्र से निकाल न दिये जायं।"[१] विशेष वर्णन नहीं है। इन शब्दों के समावेश से हर प्रकार की संदिग्धता दूर हो सकती थी । देश की अखंडता तथा सुरक्षा मुख्य लक्ष्य होने चाहिएं, नीतियां तो केवल साधन मात्र ही होती हैं। यदि तटस्थता की नीति के साथ ही हमें, चीन के आकस्मिक आक्रमण पर, विदेशों से सहायता मिल सकती है, तो इस नीति से भी मुझे कोई मत भेद नहीं है ।

कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में हम कोलम्बो शक्तियों के शांति के प्रयासों की सराहना करते हैं, परन्तु उन्होंने चीन के भारत पर आक्रमण वाली मूल बात पर अपने विचार व्यक्त नहीं किये, हालां कि उन के ऐसा करने का चीन पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता था। इसके बावजूद भी हम ने कोलम्बो प्रस्तावों को, उन के स्पष्टीकरणों सहित, स्वीकार कर लिया है । मैं अब कोलम्बों शक्तियों को स्मरण कराना चाहता हूं कि उन्हें सच्चाई और मित्रता के नाते निर्भीक हो कर अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिए ।

इस के साथ साथ हमें अपनी सैनिक शक्ति के बढ़ाने पर बराबर बल देते रहना चाहिए, और तैयारी हो जाने पर चीन को चेतावनी दी जानी चाहिए कि वह आक्रमण द्वारा हथियाये गये क्षेत्रों को खाली कर दे। यदि वह ऐसा करने के लिये तैयार न हो, तो हमें उन्हें बलपूर्वक अपने राज्य क्षेत्र से खदेड़ देना चाहिये । इसी प्रकार हम जनता के जोश तथा बलिदानों का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे । मुझे आशा है कि सरकार ऐसा करने में ढील नहीं दिखायेगी । ऐसे पग उठाये जाने से ही देश का सम्मान सुरक्षित रह सकता है ।

राष्ट्रपति के अभि भाषण में हमारे जवानों द्वारा दिये गये बलिदानों का वर्णन न पा कर मुझे खेद हुआ है । उन बीर जवानों के प्रति हमारा कर्त्तव्य तभी पूरा होगा जब हम शत्रु को अपनी भूमि से हट जाने पर मजबूर कर देंगे ।

इन शब्दों के साथ में श्री पाण्डेय के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

**डा० महादेव प्रसाद** (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के समक्ष माननीय सदस्य, श्री पाण्डेय, द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद-प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

हमारे मनीषी राष्ट्रपति ने यह उचित ही किया कि उन्होंने अपने भाषण के आरम्भ में समाजवादी व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया । समाजवादी व्यवस्था केवल एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि वह जीवन को एक नई दिशा देने का सिद्धान्त है । आज की दुनिया की बहुत सी दुरवस्था तब तक समाप्त नहीं हो सकती, जब तक कि सब देशों में समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती । माननीय सदस्य श्री रंगा ने यह चिन्ता प्रकट की है कि हमारी योजनाओं से, समाजवादी योजनाओं से, देश का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है, वह नष्ट हो रहा है । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि श्री रंगा की चिन्ता का विषय क्या है । क्या श्री रंगा उस सामाजिक ढांचे के नष्ट होने से चिन्तित हैं , जिस में एक इन्सान दूसरे इन्सान से नीचे है ? क्या श्री रंगा की चिन्ता का यह विषय है कि वह आर्थिक ढांचा नष्ट हो रहा है, जिस में मुट्ठी भर आदमी मौज उड़ाते हों और अनगिनत लोग हैवान की ज़िन्दगी गुज़ार रहे हों ?

जहां तक समाजवादी व्यवस्था का प्रश्न है, उस के प्रति हमारे देश की आस्था बहुत पहले से चली आ रही है । सच तो यह है कि हमारे राष्ट्रनायक, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, १९३६ से ही जब कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का सभापतित्व स्वीकार किया, हमारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित करते चले आ रहे हैं और इस सिद्धान्त की घोषणा और इस का समर्थन देश में सैकड़ों नहीं हजारों मंचों से बराबर होता चला आ रहा है । तब से ले कर अब तक, जब कि हम स्वतन्त्र हुये और हम को अपने देश को एक निश्चित दिशा में ले जाने का अवसर मिला, हमारे प्रधान मंत्री हमारे देश का नेतृत्व उस दिशा में सफलतापूर्वक करते चले आ रहे हैं ।

स्वतन्त्र पार्टी की सदस्या, महारानी गायत्री देवी, ने नेतृत्व में परिवर्तन की बात कही है । मैं आप के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेतृत्व में परिवर्तन तो तब हो गया, जब कि दुनिया में फ़्रांसीसी राज्य-क्रान्ति हुई । वह ज़माना लद गया, जब कि लोग गाया करते थे "यशस्वी रहें हे प्रभो,हे मुरारे, चिरंजीव रानी व राजा हमारे ।।" यह जनयुग है, जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में देश का नेतृत्व है । जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में नेतृत्व इतिहास के विकास के क्रम के परिणामस्वरूप आया है और इतिहास के विकास के क्रम को पलटना अब राजाओं और रानियों के वश में नहीं है ।

श्री जवाहरलाल के नेतृत्व में देश ने कुछ बुनियादी सिद्धान्तों में अपनी आस्था प्रकट की । उनके उदात्त नेतृत्व में हमारे देश ने इस सदन में और इस सदन के बाहर कुछ मूल्यों में अपनी मान्यता प्रकट की । वे मूल्य और वे सिद्धान्त भारतवर्ष की विशेषता रहे हैं और उन्हीं मूल्यों और सिद्धान्तों की भूमिका पर खड़े हो कर हमारे देश के अंग्रेज़ों ने विश्व को अपने चरित्र की शिक्षा दी ।

एतद्देशस्य प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना :
स्वं स्वं चरित्रम् शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा : ।

राष्ट्रपति जी ने कृपा कर किया कि हमारा ध्यान अपने भाषण में इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि जहां एक ओर हमारा यह उद्देश्य और लक्ष्य है कि अपने देश में हम सब के लिये सुख और समृद्धि प्राप्त करने की दिशा में योजनायें बना कर आगे बढ़ें, वहां यह भी आवश्यक है कि हम दुनिया में शान्ति-स्थापना की चेष्टा भी करें । इस ओर हम बराबर प्रयत्न करते आए हैं । ये

[डा० महादेव प्रसाद सिंह]

हमारे सिद्धान्त, हमारे मूल्य और हमारी आस्थायें हैं। ऐसा नहीं कि इन सिद्धान्तों, मूल्यों और आस्थाओं पर हमले नहीं हुए। हमले हुए। बाहर से और भीतर से भी हमले हुए लेकिन २० अक्तूबर, १९६२ को एक बहुत बड़ा हमला इन सिद्धान्तों और मूल्यों पर हुआ हमारे पड़ौसी देश चीन के द्वारा। यह सही है कि इस हमले के परिणामस्वरूप चीन की फौजों ने हमारे देश के एक काफ़ी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने कब्जा तो किया, लेकिन उस समय देश एक व्यक्ति की तरह एक साथ उठ खड़ा हुआ। हम में जो अभूतपूर्व एकता आई, उसके परिणामस्वरूप चीन को पीछे हटना पड़ा और वह पीछे हटा। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है, यह हमला केवल ज़मीन के एक टुकड़े पर ही नहीं हुआ, बल्कि हमारे बुनियादी सिद्धान्तों पर हुआ। अगर चीन हमारे बुनियादी सिद्धान्तों पर हमला करे, अगर चीन की यह कोशिश हो कि हम अपने सिद्धान्तों को त्याग दें, तो हम को कोई ताज्जुव या आश्चर्य नहीं होता है। किन्तु हमारे देश के लोग ही उन आस्थाओं और उन मूल्यों को ठुकराने की बात करें, उन नीतियों को छोड़ने की बात करें, तो ताजज्जुब होता है।

हमारे मित्र, श्री बृजराज सिंह, ने सैनिक गठनों से अलग रहने की हमारी नीति के विषय में कुछ कहा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतने वर्षों के बाद भी उनको यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सैनिक गठबन्धनों से अलग रहने की नीति का अभिप्राय क्या है। उस नीति का मतलब यह नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर, उचित होने पर, हम अमरीका से सहायता नहीं लेंगे, आवश्यक होने पर हम रूस से सहायता नहीं लेंगे, या दुनिया के किसी और मुल्क से सहायता नहीं लेंगे। हमने इन मुल्कों से सहायता ली। सच तो यह है कि आज दुनिया में कोई भी मुल्क अकेले, बिना किसी की सहायता या सहयोग लिए चल ही नहीं सकता है। इस सिलसिले में मैं आपकी आज्ञा से यहां पर प्रधान मंत्री के उस भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं, जो उन्होंने इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड एफ़ेयर्ज़ के सामने अपनी इस सैनिक गठबंधनों से अलग रहने की नीति की व्याख्या करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था :

> "हमारी गुटों से अलग रहने की नीति का यह अर्थ नहीं है कि हम किन्हीं देशों से अन्य देशों की अपेक्षा अधिक घनिष्ट सम्बन्ध नहीं रख सकते। इसका अर्थ केवल यह है कि हम राजनयिक दृष्टि से किसी एक गुट के साथ लग कर अपनीभविष्य की विदेशी गतिविधियों में उससे प्रभावित नहीं होना चाहते।"

श्रीमन्, श्री बृजराज सिंह जी ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। मैं आपकी आज्ञा से उनका ध्यान श्यामाप्रसाद मुखर्जी के ही एक वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ३ जून, १९४८ को डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने एक वक्तव्य में रूस को निमंत्रण दिया था कि भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में और सुदूरपूर्व के देशों में भी, उनकी आर्थिक स्थिति को वह उन्नत करे। आज अगर हम इस से कोई सहायता की बात करते हैं, या रूस से सहायता की आशा रखते हैं तो क्या कोई गलत काम कर रहे हैं?

मैं, जहां तक चीन के साथ हमारी नीति का सम्बन्ध है, इस सदन का और आपका ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली तो सिद्धान्त की बात है और दूसरी तथ्य की बात। सिद्धान्त का जहां तक प्रश्न है, विचारने की बात यह है कि दो राष्ट्रों में जब झगड़ा हो तो वह झगड़ा या तो युद्ध से तय हो सकता है या फिर समझौता करके, बातचीत के द्वारा तय हो सकता है। युद्ध

का रास्ता सर्वनाश का रास्ता है। इस सिलसिले में मैं महाभारत की एक कथा का उल्लेख करना चाहता हूं। महाभारत के विषय में स्वतन्त्र पार्टी के नेताओं की और जनसंघ की प्रायः मान्यता है। राजाजी का कहना है कि महाभारत की कथायें ऐसी हैं जिन को पढ़ कर, जिन से नसीहत ले कर आदमी अच्छा आदमी हो सकता है, विचारक अच्छा विचारक हो सकता है। एक अवसर ऐसा उपस्थित हुआ महाभारत के समय में कि जब पाण्डव लोग इकट्ठे थे यह विचारने के लिये कि दुर्योधन तथा अन्य कौरवों से, जिन्होंने उनके साथ बराबर विश्वासघात किया था, जिन्होंने उनको काफी सताया था और जिनकी बातों पर विश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, उनसे लड़ाई की जाये या नहीं। आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण पाण्डवों के सलाहकार थे। वह वहां पर मौजूद थे। उन से राय ली गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो एक बार फिर जा करके दुर्योधन से शान्ति की बात, सुलह की बात करना चाहता हूं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने इसके जवाब में कहा कि आपका वहां जाना बिल्कुल बेकार है और आप वहां जायें, इसका मैं समर्थक नहीं हूं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही, वह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा :

जानाम्येतां महाराज धार्तराष्ट्रस्य पापताम् ।

अवाच्यास्तु भविष्यामः सर्वलोके महीक्षिताम् ।।

हे महाराज मैं जानता हूं कि धतराष्ट्र कौरव किस प्रकार के पापी हैं। उनके पापों को मैं जानता हूं। वे किस प्रकार से अपने वायदे से मुकर सकते हैं, इसको भी मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं यह चाहता हूं कि संसार के राजाओं के सामने हम निर्दोष सिद्ध हो जायं और सब को यह ज्ञात हो जाए कि हमने शान्ति को कायम रखने के लिये अपनी तरफ से हद से बाहर जा करके कोशिश की है।

दूसरी बात इस संदर्भ में जो विचारने की है वह भौगोलिक स्थिति की है। एक बात स्मरण रखी जानी चाहिय कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और यह जरूर है कि हम को उसकी तकलीफ है लेकिन श्रीमन्, चीन के विषय में हम कोई भी नीति निर्धारित करने जायें, पाकिस्तान के विषय में हम कोई भी नीति निर्धारित करने जायें, तो यह बात हम को ध्यान में रखनी होगी कि वे दोनों हमारे पड़ोसी थे, आज भी हमारे पड़ोसी हैं और आगे भी हमारे पड़ोसी रहने वाले हैं।

राष्ट्रपति का मैं बड़ा अनगृहीत हूं कि उन्होंने नेपाल से हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का उल्लेख किया है। मेरा अपना क्षेत्र नेपाल की सीमा पर पड़ता है। हम जानते हैं कि नेपाल के और हमारे कितने घनिष्ट संबंध हैं। सच तो यह है कि नेपाल और भारत के बीच की सीमा कोई सीमा ही नहीं है। वह तो मानने की सीमा है। हजारों लोग हमारे अपने क्षेत्र से नेपाल में काम करने जाते हैं, नेपाल के बहुत से लोग हमारे क्षेत्र में काम करने आते हैं। बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे और नेपाल के संबंध घनिष्ट रहे। थोड़ी बहुत जो कमी इधर किसी कारण से आ गई थी, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे स्वराष्ट्र मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री जी की यात्रा के फलस्वरूप वह दूर हो जाएगी और हमारे सम्बन्ध और भी घनिष्टपा तम हो जायेंगे और जहां कहीं भी शिकन आ गए हैं, , वे दूर हो जाये, । इतना होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल की सीमा पर जो हमारा क्षेत्र है, उस में सैनिक दृष्टि से हम को तैयारी मजबूत करने की जरूरत है। यदि सम्भव हो तो नेपाल और भारत सहयोग करके, दोनों की संयुक्त: अगर वहां पर तैयारी हो सके, तो बड़ा ही उत्तम होगा।

[श्री महादेव प्रसाद सिंह]

मैं आप के ध्यान में एक और बात बताना चाहता हूं । सीमा क्षेत्रों में यातायात की स्थिति अत्यन्त दयनीय है और उसको उन्नत करने की ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये । एक उदाहरण में अपने क्षेत्र का देना चाहता हूं । सड़कों की बात को जाने दीजिये, रेलों की स्थिति क्या है, क्या इसको आप देखिये । नौतनवा सीमा से चार मील की दूरी पर स्थित है । वहां पर आनन्द नगर से एन० ई० रेलवे की लाइन जाती है । वह लाइन १८८९ ईस्वी में बिछाई गई थी। उस वक्त जब वह बिछाई गई थी वह ४१ पांउड की थी। इस वक्त शायद ३० या ३२ पाउंड की होगी । १३ मील फी घंटा की रफतार से उस पर आजकल गाड़ियां चलती हैं । अजीब बात है कि अगर सीमा पर साधारण गाड़ियों की यह हालत रहेगी तो फिर किस तरह से युद्ध के लिए तथा दूसरी किसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सचमुच में हम तैयार हो सकेंगे । मेरा निवेदन है कि सीमा पर स्थित जो भी क्षेत्र है उन में जल्दी से जल्दी बड़ी लाइन बिछाई जानी चाहिये और उनको अच्छी से अच्छी स्थिति में रखने की भी कोशिश की जानी चाहिये ।

नेपाल से घनिष्ट संबंध की मैं इसलिए भी लालसा करता हूं कि अभी पिछले साल हमारे जो क्षे थे, देवरिया और गोरखपुर के जो उत्तरी क्षे थे बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हो गए थे और वे इस लिये हो गये थे कि हम गंडक योजना को पूरी नहीं कर पा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि हमारे शास्त्री जी जब नेपाल जा रहे हैं तो गंडक योजना को पूरा करने की दिशा में भी वहां बातचीत करें ताकि अगली बरसात में हम बाढ़ से अपने उन क्षेत्रों को बचा सकें ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में योजनाबद्ध कार्य करने की ओर भी संकेत किया है। यह दूसरी बात है कि हमारे कुछ भाई उसके खिलाफ हैं। योजना के फलस्वरूप देश एक कदम से दूसरे कदम पर जब आया तो प्रायः आगे बढ़ा, हमारी स्थिति अच्छी हुई । यह ठीक है । लेकिन हम जहां तक देश को ले जाना चाहते हैं, वहां तक नहीं ले जा पाये हैं, वहां तक देश को नहीं पहुंचा पाये हैं । एक बात इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं । योजनाओं से राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ी है, लेकिन गरीबों की सम्पत्ति उतनी नहीं बढ़ पाई है जितनी बढ़नी चाहिये थी। इसका कारण यह है कि हमारी जो योजना है वह खर्च करने की योजना है । केन्द्र के द्वारा और राज्यों के द्वारा कुल रकमें हम खर्च करते हैं और लोग अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उस रुपये से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इन रुपयों से फायदा जिन के पास रुपया हैं, जिन के पास शक्ति है, जिनके पास साधन हैं वे ज्यादा उठा पाये हैं और जो गरीब हैं, वे नहीं उठा पाये हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि तकावी के, अनुदान के, कर्ज के नियमों आदि में बुनियादी तौर पर परिवर्तन होना चाहिये जिस से गरीब भी इससे लाभ उठा सकें ।

आपात् स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । यह भी कहा गया है कि जबर्दस्ती चन्दे इकट्ठे किये जा रहे हैं । यह बात हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने तथा स्वतंत्र दल के भाइयों ने भी कही है। जहां तक मेरी वाकफियत है मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। किस तरह से इस तरह के आरोप लगा दिये जाते हैं, पता नहीं । एक तरफ कहा जाता है कि सुरक्षा कोष में सहायता देने के लिये सभी लोग उठ खड़े हुए हैं, स्वेच्छा से चन्दे दे रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है जबर्दस्ती वसूली की जा रही है, इन दोनों बातों की संगति नहीं बैठती है। जब लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं तो जबर्दस्ती करने का प्रश्न कहां

उपस्थित होता है। इस प्रकार की बातें कर के हमारे देश की ताकत को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, यह उनके ही सोचने की बात है। एक कम्युनिस्ट भाई से मैं बात कर रहा था और मैं ने उनसे पूछा कि उनको यह सूचना कहां से मिली तो उन्होंने कहा कि पेकिंग रेडियो से इसका प्रसारण हुआ है। पेकिंग रेडियो की बात के ऊपर विश्वास कर के इस तरह के आरोप लगाये जाय और जो कुछ यहां कहा जाता है, उस पर विश्वास न किया जाए, यह कहां तक सही है, यह मैं उन से पूछना चाहूंगा।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपातकाल के होते हुए भी, हम को समाजवादी ढांचे को अधिक से अधिक मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं।

**१४-३०**

**श्री वाल्मीकी** (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार प्रकट करने के लिये मैं भी खड़ा हुआ हूं।

उस दिन जब राष्ट्रपति महोदय ने अपना अभिभाषण प्रारम्भ किया तो एक अशोभनीय घटना घटित हुई थी, हिन्दी के विषय में, और वह हमारे अपने साथियों के द्वारा हुई थी। उसकी जांच के लिये जो जांच समिति बनी है, हमारा उस में विश्वास है। हम यह अवश्य देखते हैं कि इस सदन की, दूसरे सदन की और संसद् की प्रशंसा और संसद की सम्माननीय पद्धति को ध्यान में रखते हुए ऐसी घटना फिर घटित नहीं होगी। इस प्रकार की घटना से हिन्दी का कार्य आगे बढ़ता भी नहीं। वैसे तो हिन्दी अपना स्थान प्राप्त कर रही है लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दी को जिस प्रकार का प्रोत्साहन और स्थान प्राप्त होना चाहिये, सरकारी तौर पर वह प्रयत्न कुछ ढीलेपन से ही चल रहा है। उधर कुछ तेजी आनी ही चाहिये और हिन्दी को अपना उचित स्थान प्राप्त करने का अवसर जल्दी से जल्दी मिलना चाहिये, राष्ट्र भाषा के रूप में। हिन्दी वह स्थान है धीरे धीरे प्राप्त कर रही है। जिन राज्यों के भाई हिन्दी नहीं जानते हैं, मैं उन राज्यों में भी गया हूं। वहां भी मैं ने देखा है कि हिन्दी अपना स्थान प्राप्त कर रही है। जिस तरह से हिन्दी वहां बढ़ रही वह सराहनीय कार्य है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी के कार्य को ले कर चलना है। हमें उस में किसी प्रकार की जिद की बात नहीं लानी है। अब हिन्दी का काम किसी भी प्रकार से रुकने वाला नहीं है क्योंकि हिन्दी भाषा भाषी लोगों की संख्या इस देश में बहुत ही ज्यादा है। इसलिये मैं इस बात को यहां सदन में रखना चाहता हूं।

हमारे राष्ट्रपति महोदय ने चीन के हमले की विभीषिका और विकट समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है सारे देश के अन्दर संकटकालीन स्थिति है और आज भी है। यद्यपि चीन के अपने तरीके से विराम सन्धि के कारण हट जाने से हमें थोड़ी सी शांति सी प्रतीत होती है, फिर भी हमारे सीमावर्ती इलाकों पर से अभी भी चीन की निगाह कोई हटी नहीं है। और चीनी अजगर आज भी फुंकारता हुआ नजर आता है। चीन के जो अपने विस्तारवादी प्रयत्न हैं व शान्त नहीं है। चीन के इस हमले का खतरा केवल इस देश का ही नहीं है, केवल एशिया को ही नहीं हैं, सारे संसार का है। चीन के इस भर्त्सनापूर्ण हमले की निन्दा सारे संसार ने की है, और हम विशेष कर उन संसार के राष्ट्रों के प्रति जिन्होंने इस संकट

[श्री बाल्मीकी]

कालीन समय में हमारी सहायता की है, आभार प्रकट करते हैं। यह बात अवश्य है कि मैं सरकार का ध्यान विशेष कर इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि यकीनी तौर से एक प्रकार की ढील, शिथिलता और क्लीवता बरती गई है और देश में एक प्रकार की कमजोरी रही। लेकिन वह उस वक्त रही। यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि हमारे देश के फौजी जवानों ने आज एक शौर्यू और बलशाली वीरता का परिचय दिया है। जिस प्रकार से कोई प्रबन्ध न होते हुये उन्होंने चीनी अजगर के दांत खट्टे किये हैं और अनेक चीनियों को पछाड़ कर लोथों पर लोथें बिछाई हैं, उसके लिये उन के कार्य की चारों ओर प्रशंसा की जाती है। यहां यह बात जरूरी है और देश चाहता है, देश की इच्छा है, यहां के जन-जन की इच्छा है कि हमारे फौजी प्रयत्न फौजी तैयारियों के प्रयत्न तेजी से बढ़ने चाहियें और इस तरह से बढ़ने चाहियें कि देश में आशा का संचार हो। देश चाहता है कि उन में किसी प्रकार की ढील न बरती जाय।

हम जानते हैं कि हमारे देश की रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि है। देश की रक्षा के लिये जो भी बलिदान किया जाय वह थोड़ा है। तन का, मन का और धन का जो भी बलिदान किया जाय वह थोड़ा है। सारे देश ने इस संकट काल में जिस एकता का परिचय दिया है वह एक सराहनीय कार्य है। आज सारा देश एक है, अनेक मत मतान्तरों का यह देश, अनेक देवों को पूजने वाला यह देश, अनेक बातों के यहां रहते हुये इस में हर प्रकार के भेद विभेद नजर आते हैं, लेकिन आज संकट के समय में वे सारे भेद विभेद विलीन हो गये हैं और सारा देश दृढ़ता के साथ, वीरता के साथ, शक्ति के साथ और धैर्य के साथ खड़ा हो गया है। अन्त में संसार में कौमें ही जीतती हैं जो धैर्य रखती हैं, जिनमें साहस होता है, जिन में मनोबल होता है।

त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले,
धैर्यात् कदाचित् गतिमाप्नुयात्च,
यथा समुद्रेऽपि च पोत भंगे,
सांयान्त्रिको वाञ्छति ततुर्मेव।

हमारे इस कठिन काल में धैर्य की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक यात्री समुद्र में जहाज के टूट जाने पर लकड़ी के सहारे को भी सहायक समझता है, उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि देश के लिये धैर्य की बहुत आवश्यकता है। लेकिन धैर्य कोई शिक्षा नहीं, धैर्य कोई विश्वास नहीं, धैर्य मनुष्य का अपना कर्तव्य है। लेकिन जहां तक सरकार का और शासन प्रबन्ध का सम्बन्ध है, शासन को धैर्य रख कर भी तीव्रता के साथ तेजी के साथ फौजी तैयारियों को जारी रखना चाहिये।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो हमारे लड़ाई का सामान तैयार करने वाले कारखाने हैं, जो आर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं, उन में दिन रात बल लगा कर तेजी के साथ सामान तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार से जो मजदूर भी प्रयत्न कर रहे हैं मैं उन के प्रयत्न की भी सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आशा है कि जो भी अस्त्रशस्त्र हैं, आधुनिक अस्त्रशस्त्र हैं, और आधुनिक पद्धिति से चलाये जाते हैं, उन के निर्माण के सारे प्रयत्न चलते रहेंगे। वे यहां भी तैयार किये जायेंगे और अगर नहीं तो जहां से भी वे उपलब्ध हो सकेंगे वहां से प्राप्त किये जायेंगे। इस बात की बहुत आवश्यकता है क्योंकि हमारी जो तैयारी है वह एक विशेष प्रकार की तैयारी होनी चाहिये। आज भारत की प्रभु सत्ता को जो, एक प्रकार की चुनौती है उसे हमने स्वीकार किया है। हम ने चीन को ललकार दी है यह चुनौती स्वीकार करके कि हम अपनी इस पवित्र धरती से चीनी दरिन्दों के पैरों को उखाड़ कर फेंकेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार से यहां बर्दाश्त

नहीं करेंगे। हमारा वह संकल्प ज्यों का त्यों खड़ा है और हम को इस संकल्प में किसी प्रकार की ढील नहीं लानी है क्योंकि उस संकल्प में सारे देश का सहयोग है।

सी प्रकार से मैं चाहता हूं कि नेवी, अर्थात् हमारे पानी के बल में भी पूरी शक्ति होनी चाहियें और उस में तेजी से, तीव्रता से ृद्धि आनी चाहिये। यही नहीं, हमारा वायु बल, हमारी वायु सेना भी ृढ़तर होनी चाहिये। उस में मजबूती होनी चाहिये। जिस प्रकार से भी हो सके यह सारे प्रयत्न हम को सभी ओर से करने हैं और भली प्रकार से करने हैं। इस प्रकार से आप को अपनी सारी सेना में मजबूती लानी है तभी हम चीनी हमले का डटकर मुकाबला कर सकते हैं।

यह बात ठीक है कि हमारे यहां ऐसी स्थिति में एक बलशाली सेना की आवश्यकता है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि जहां तक हमारी सेना का सम्बन्ध है, वह सारे संसार में प्रसिद्ध रही है। यदि हम इसी प्रकार तैयार रहें और इसी तेजी से चलते रहें और हर प्रकार के आधुनिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते रहें, तो इस प्रकार का कार्य विशेष रूप से सराहनीय होगा। हमारी जो फौज है वह सारे संसार में स्थान रखती रही है और आगे भी रखती रहेगी, इस प्रकार का मेरा विश्वास है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रयत्न किसी प्रकार से भी ढीले नहीं पड़ेंगे।

यह मेरी समझ में भी आता है, कि रक्षा और रक्षा की तैयारियों में खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़े। अगर आवश्यक हो तो हमें अपने प्रयत्नों में तेजी लाने के लिये अपने खर्च में बचत का प्रयत्न करना चाहिये। जब हम इस बचत की ओर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि इस ओर बहुत कम प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार के प्रयत्न भी ढीले रहे हैं और नहीं के बराबर हैं क्योंकि जो शासन तथा सरकारी कार्यालयों में साज सज्जा की बात है, जो शौकीनी की बात है वह ज्यों की त्यों नजर आती है, और जहां तक संकटकालीन स्थिति का सम्बन्ध है, उसके होते हुए भी कोई उसका रूप देश में हमें नजर नहीं आता है। मैं समझता हूं कि हमें अपनी बचत में तेजी लानी चाहिये। जहां तक फजूल खर्ची को रोकने की बात है, मैं समझता हूं कि उधर भी कम ध्यान दिया गया है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं कि फिजूलखर्ची को रोकने के लिये, लालफीताशाही को रोकने के लिए अफसरशाही को रोकने के लिये जिस प्रकार की ताकत के साथ प्रयत्न करने चाहिये वे नहीं किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सारे संसार से एक-एक पैसा जहां ले रहे हैं वहां अपने यहां भी बचत करके इस तरह के प्रयत्न करने चाहिये और सरकारी फुजूलखर्ची को यकीनी तौर पर रोकना चाहिये। यदि इस ओर ध्यान दिया जाय तो अधिक नहीं तो कम से कम सात आठ करोड़ रुपये बचाये जा सकते हैं, जो कि देश के इस संकट काल में हमारे देश के काम आ सकते हैं। अगर आप इस ओर ध्यान देंगे तो इसका प्रभाव हमारी योजनाओं पर पड़ेगा।

पहली और दूसरी योजनाओं में देश में ही श्रम की आदत पैदा हुई है और विश्वास पैदा हुआ है, विचारों में दृढ़ता आई है। लेकिन जहां तक हमारी तीसरी योजना का सम्बन्ध है, मैं इस ओर आपका ध्यान आर्का त करना चाहता हूं कि उसके लक्ष्यों को किसी भी प्रकार से गिरने नहीं देना है। हालांकि तीसरी योजना के लक्ष्यों में कटौती की गई है लेकिन उस कटौती का प्रभाव केवल जन-कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता है, हरिजनों या दूसरे कुछ वर्गों पर पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तीसरी योजना के तथ्यों को सामने रख कर, चीनी आक्रमण की विभीषिका को सामने रख कर तीसरी योजना के लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जाय। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि तीसरी योजना एक प्रभावशाली योजना है जो इस ओर हमारा ध्यान आर्कषित करती है।

[श्री बाल्मीकी]

लड़ाई केवल फौजी मैदानों में ही नहीं लड़ी जाती, केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि पर्वतों पर भी लड़ी जाती है। चूंकि यह लड़ाई पर्वतों पर लड़ी जा रही है इसलिये इस तरह का प्रशिक्षण सैनिकों को देने की आवश्यकता है कि वे उस पहाड़ी स्थिति में अच्छी तरह से दुश्मन से लड़ सके। केवल इस शिकायत से काम नहीं चलेगा कि वहां पर कुछ ऊंचाइयां थीं, कुछ नीचाइयां थीं या कुछ गहरी खाइयां थीं। अभी भी चीनी आक्रमणकारी हमारी भूमि पर मौजूद है इस तथ्य को हमें भुलाना नहीं होगा। हमारे ऊपर यह छलपूर्ण और बर्बरतापूर्ण आक्रमण उस चीन द्वारा किया गया जो कि हमारा अपना मित्र रहा है, जिसके सम्बन्ध विगत में हमारे साथ मैत्रीपूर्ण रहे हैं। इसी चीन को हमने संसार की पंचायत में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया है। इतना होते हुए भी उसने हमारे साथ यह धोखे से भरा और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। आज यह बात नहीं है कि हम आज की स्थिति के प्रति जागरूक नहीं हैं बल्कि उनके इस धोखे में हमें झकझोर दिया जाय। मैं नहीं समझता कि हिन्दी, चीनी भाई-भाई तथ्य को देश ने समझ लिया है। हम देशवासियों को इस तथ्य को समझना है और यह ध्यान में रखना है कि उसने कैसा छलपूर्ण व्यवहार उस देश के साथ किया है जिसके कि साथ मिल कर हिन्दी, चीनी भाई-भाई का नारा लगाया था। जो ग़लती और गफ़लत भूतकाल में हमसे हो गई है उसको दुबारा नहीं करना है। अपने युद्ध प्रयत्नों में हमें किसी तरह की भी ढील नहीं करनी है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को भी हमें ध्यान में रख कर उनके लिए प्रयत्न करना है और देश की कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में भी उन्नति करनी है। आज की लड़ाई युद्ध क्षेत्र में ही नहीं अपितु कल, कारखानों और खेतों में भी लड़ी जाती है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारी सरकार उधर सजग है और उसके लिए सक्रिय प्रयत्न हो रहे हैं। कारखानों के उत्पादन में वद्धि हुई है। खेती के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है लेकिन अभी मैं अपने इलाके में या आसपास में घमा हूं और मैं देखता हूं कि इस साल की फ़सल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार का ध्यान उस ओर जायेगा। सरकार को चीनी हमले का सामना करने के सवाल को सब से पहले प्राथमिकता देनी चाहिये। लेकिन उसके अलावा दूसरे प्रश्न भी देश के सामने हैं जैसे कि देश की कृषि और औद्योगिक उत्पादन की क्षमता बढ़ाना। यह सन्तोष का विषय है कि इधर प्रयत्न हो रहा है। मेरा निवेदन है कि यह प्रयत्न रुकना नहीं चाहिये।

आज देश के सामने जो संकटपूर्ण स्थिति है उसमें यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने युद्ध प्रयत्नों में किसी तरह की ढील न आने दें। आपात स्थिति कायम रहनी चाहिए क्योंकि यह सारे देश को तैयार करने का सवाल है। लेकिन जैसा कि कुछ भाइयों ने शिकायत भी की है कि संकटकालीन स्थिति के दौरान मिली इमरजेंसी पावर्स का दुरुपयोग हो रहा है, वह दुरुपयोग उनका नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जहां सरकार इस बात का ध्यान रक्खे और रक्खा भी जा रहा है कि इमरजेंसी पावर्स का सही इस्तेमाल हो, इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि देश में जो भी ऐसे देशद्रोही और देश के खिलाफ तत्व मौजूद हैं सरकार उनको उभरने न दे और उनको सख्ती से दबाये। ऐसे देश और समाज विरोधी तत्वों को जो कि देश को हानि पहुंचाने वाले हैं उनको दबाना और उभरने न देना देशहित में है और ऐसा करके ही सरकार देश की सुरक्षा सुदृढ़ कर सकती है।

हमारे देश में समाजवाद और प्रजातांत्रिक व्यवस्था चल रही है और उनके अन्दर मनुष्य का भाग्य खुल रहा है, नये भाग्य का उदय हो रहा है। भारत रक्षा कोष और अन्य युद्ध प्रयत्नों में मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि धनी वर्ग ने अपना पार्ट अदा नहीं किया है। उनका उसमें सहयोग

न के बराबर रहा है। इसके विपरीत इस देश की आम जनता ने किसानों और मजदूरों तथा दलितों ने दिल खोल कर अपना सहयोग प्रदान किया है।

जहां हमें यह देख कर प्रसन्नता होती है कि देश के अन्दर लोकतंत्री और समाजवादी परम्परा जागृत हो रही है वहां यह देख कर बिल को एक ठेस सी लग ी है कि अभी भी देश के अन्दर हजारों और लाखों निर्धन आदमी दलितों की शक्ल में, मामूली किसानों की शक्ल में, मजदूरों की शक्ल में, और सर्वहाराओं की शक्ल में मौजूद हैं। मैं सारे देश में घूमा हूं और उनकी स्थिति देखी है। आज भी उनको कोई आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। वह न्याय उन्हें मिलना चाहिये। सरकार ऐसा प्रयत्न करेगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

**श्री बाल्मीकी** : आपने सबको इतना-इतना समय दिया है। मुझे तो अभी दस मिनट भी नहीं हुए हैं। मुझे कुछ और अधिक समय दिया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बस एक ो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

**श्री बाल्मीकी** : मैंने खेती के उत्पादन में वृद्धि करने और उसके लिए किसानों को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए सुझाव दिया है। दूसरा निवेदन यह है कि हमें उद्योगीकरण में भी प्रगति करनी है। हमें देश में अपने उद्योगों को इस तरह से ालना है जिससे देश में रक्षा सम्बन्धी तथा जवानों के उपयोग का सामान ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके और इसके लिए हमें जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए और इस प्रकार का सामान उनके अन्दर भी बनाना चाहिए। उनको इसके लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और हर प्रकार से धन की सहायता करनी है।

अन्त में मैं अधिक न कहते हुए किसानों की हालत की तरफ सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। आज की स्थिति में किसान को सारी जरूरी कर्ज तकावी आदि की सहुलियतें पूरी तरीके से मिलनी चाहिएं। हमें यह नहीं भूलना है कि हमारी जो अर्थ नीति है वह किसान के ऊपर निर्भर है। ग्रामीण जीवन तथा किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि वहां स्वस्थता, एकता और मजबूती लाने के लिए वहां के जीवन में भारी परिवर्तन किये जायें और उनको ऊपर उठाया जाये। सरकार को इस दिशा में विशेष रूप से सक्रिय और ठोस कदम उठाना चाहिए। तभी विकास के प्रयत्न सफलीभूत हो सकते हैं।

†**श्री य० ना० सिंह** (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से असन्तोष प्रकट करना चाहता हूं।

अभिभाषण में औद्योगिक उत्पादन, ग्राम सुधार, आदि, विषयों की चर्चा तो की गई है, परन्तु चीन के आक्रमण तथा संसद की उस प्रतिज्ञा का उल्लेख नहीं है जिसके अनुसार सरकार को शत्रु को अपने राज्य-क्षे से खदेड़ने के लिए कहा गया था। इस समय जब कि हमारी स्वतन्त्रता खतरे में है, अन्य बातों का उल्लेख करना सर्वथा अनुचित है। सरकार द्वारा उस मुख्य विषय की अवहेलना की गई है। यह केवल हमारे देश की विशेषता है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय की अवहेलना करते पर भी सरकार कायम रह सकती है। अभिभाषण में शांतिपूर्ण उपायों का उल्लेख किया गया है। इस से जाहिर है कि सरकार चीनी आक्रमण की समस्या को महत्वहीन समझती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री या० ना० सिंह]

देश के राज्य क्षे की रक्षा करना सरकार का सर्वोत्तम कर्तव्य है। हमारे इतिहास की परम्परायें इस बात की गवाही देती हैं। परन्तु आज के प्रशासक अप ी ग ी को बनाये रखने की चिन्ता में हैं।

चीन के प्रति समर्पण की भावना का प्रदर्शन करके हमारी सरकार देश के लिये हितों की अवहेलना कर रही हैं। शान्तिपूर्वक ंग से शत्रु को अपने राज्य-क्षेत्र से खदेड़ने की बात करना देश के लिए और जनता के लिए अपमानजनक बात है।

धान मंत्री ारा ५ दिसम्बर, १९६१, को यह विचार व्यक्त किया गया था कि वह युद्ध सम्बन्धी बातों से घृणा करते हैं, परन्तु युद्ध से घबराने का अर्थ गुलामी को स्वीकार करना है। देश के लिये यह विचारणीय बात है कि वह स्वतन्त्रता चाहते है अथवा शान्ति और पराधीनता। हमारे प्रधान मंत्री यदि युद्ध से भयभीत हैं तो उन्हें सच्चे मित्रों और देशभक्तों से पहामर्श करना चाहिए।

**श्री शिवनारायण** (बांसी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है।

हमारा यह देश बड़ा गौरवशाली है कि ऐसे राष पति जी हमारे बीच में हैं, जो कि फिलासफ़ी के बड़े विद्वान, राजनीति के प्रकांड पंडित और गु जन रहे हैं। उन्होंने यह सदुपदेश देकर कि "उठो, जागो, जाग्रत रहो, सोओो नहीं," देश को जगाया है और संकेत दिया है। उन्होंने हमें कहीं विचलित नहीं किया है। हम सब को इस बड़े भारी विद्वान, राजनीतिज्ञ और फिलासफ़र के इस उपदेश से प्रेरणा और प्रकाश लेना चाहिए।

जहां तक कोलम्बो प्रस्तावों का सम्बन्ध है,उनको इस सदन और इस पार्लियामेंट ने माना है और इस प्रकार हमने अपने देश की नान-एलाइनमेंट पालिसी को एक सनद दे दी है। कोलम्बो प्रस्तावों को बनाने वाले पांच देश नान-एलाइन्ड इंट्रीज़ हैं और उन प्रस्तावों को मान कर हमने अपनी पालिसी को एक सही सर्टिफिकेट दिलाया हैं। यद्यपि चीन ने दुनिया भर में किताबें आदि बांट कर और कुप्रचार करके हमको बदनाम कर रखा है कि हिन्दुस्ा ने उस पर एटैक किया है लेकिन कोलम्बो प्रस्तावों को मान कर हमने यह सिद्ध कर दिया कि हम सही रास्ते पर हैं और चीन ग़लत रास्ते पर है।

श्रीमन्, दुनिया में अच्छा से अच्छे युद्ध भी ख़राब से ख़राब पीस से अच्छा नहीं होता है। किसी भी युद्ध के बाद अन्त में टेबल के गिर्द बैठ कर शान्ति और सुलह के लिए बातचीत करनी पड़ती है। आपको याद होगा कि पहली बड़ी लड़ाई के बाद वारसाई में जर्मनी के साथ सुलहनामा हुआ। फिर उस वारसाई सुलहनामे का रिजल्ट दूसरा बड़ा युद्ध हुआ।

**श्री रामसेवक याव** (बाराबंकी) : यहां तो पहले ही सुलह है।

**श्री शिव नारायण** : माननीय सदस्य श्री यादव, बहुत परेशान हैं। मैं अभी उनको बताऊंगा कि वह क्या हैं और क्या कर रहे हैं।

मुझे इस बात की खुशी है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि चीन ने हमको अच्छा सबक दिया, उसने हम को सचेत कर दिया और जाग्रत किया।

**श्री राम सेवक यादव** : इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है ?

**श्री शिव नारायण** : बेशर्मी माननीय सदस्य को होगी ।

श्रीमन्, मुझे एक कहावत याद आती है : "तमीज़े न वाशद, कमन्दे हवा, उलटने की रोटी, उलट दी तवा ।" हमारे मित्र मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन यह हालत उनकी है ।

मैं कहना चाहता हूं कि दुश्मन ने हम पर हमला नहीं किया है, दोस्त ने हम पर हमला किया है। चीन ने दुनिया के सामने यह एक नई मिसाल पेश की है। हिस्ट्री में ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि दोस्त ने हमला किया हो, दुश्मन ने नहीं। चीन के इस हमले को हम फ़ेस कर रहे हैं, लेकिन पंचशील पर आधारित जो पीसफुल पालिसी हमने अख्तियार की थी, उस पर हम टिके हुए हैं। हमारे प्रधान मंत्री उस पर स्थिर हैं। हमारे कुछ मित्र इतना शोर-गुल करते हैं, लेकिन वह शान्ति और गम्भीरता के साथ इस समस्या का सामना कर रहे हैं ।

मैं बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल क्या हैं। जवाहरलाल वह हस्ती है, जिसने हिन्दुस्तान के अप्स एंड डाउन्ज़, सुख और दुख दोनों के दिन देखे हैं। वह अंग्रेज से लड़े हैं। १९४२ की मूवमेंट के बाद जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने नहीं कहा कि हम १९४२ की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। वह हिन्दुस्तान का शेर जवाहरलाल नेहरू था, जिसने पंजाब में कहा कि १९४२ के रेवोल्यूशन का जिम्मेदार मैं हूं। उसके बाद अंग्रेज का मुंह बन्द हो गया। आज उसी जवाहरलाल के पीछे हिन्दुस्तान खड़ा है। वह कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है, कोई कमजोर लीडर नहीं है। उनमें बड़ा तपोबल है। वह उन्नीस बरस जेल रह चुके हैं। श्री यादव का तो शायद उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा यह कीमत है जवाहरलाल की और इसीलिए आज सारी कौम उनके पीछे खड़ी है ।

हमने कोलम्बो प्रस्तावों को माना है और ग़लत नहीं माना है । नान-एलाइनमेंट पालिसी और कोलम्बो प्रस्ताव दोनों एक दूसरे के समर्थक हैं। हमने उन प्रस्तावों को माना और इस प्रकार दुनिया के सामने नान-एलाइनमेंट पालिसी की फिर पुष्टि की। हमारी इस नीति का ही फल है कि आज दुनिया के सत्तर मुल्क हमारे पीछे खड़े हैं। हम कम जोर नहीं हैं। अमरीका, रशा, ब्रिटेन, फ्रांस, कोई भी देश हमारी मदद करे, तो हम उसको वैलकम करते हैं। मैं फ्रांस को बधाई देना चाहता हूं कि उसने स्वयं अपनी इच्छा से अपने अधीनस्थ भारतीय क्षेत्रों को स्वतंत्र किया और इस बारे में एक सुलहनामा किया । यह उस देश का बड़प्पन है ।

तुलसीदास जी ने कहा है, "जेन मित्र दुख होहिं दुखारी, तिनहिं विलोकत पातक भारी ।" चीन ने इस नीति के विरुद्ध काम किया है और इसलिये उसका नाम दुनिया के सभ्य देशों से मिट गया है। उसकी बदनामी हुई है। आज कम्यूनिस्ट वर्ल्ड में चीन की क्या पोज़ीशन है ? स्वयं कम्यूनिस्टों ने उसको कन्डेम किया है। मैं राजनीति का छोटा सा तिनका हूं। "जाकी धन धरती हरी, ताहि न लीजो संग, जो संग राखत बने, तो करि राख अपंग ।" हम ढोल नहीं पीटते हैं कि हम यह हैं और वह हैं। हम खरगोश की चाल नहीं चरल रहेहैं, हम कछुए की चाल चल रहे हैं हम उतावले नहीं हैं। हम शान्ति के साथ अपनी गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे पहले थे, वैसे ही अब हैं। वह सदा एक से हैं।

**श्री राम सेवक यादव** : जैसे सूखे सावन, वैसे हरे भादों ।

**श्री शिवनारायण** : सूरज के विद्यमान रहते हुए भी जिसको दिन में न दिखाई दे, तो यह उसका दोष है, मेरा दोष नहीं है । हमारी गाड़ी तो आगे चलती जायेगी ।

[श्री शिव नारायण]

गवर्नमेंट ने जो गोल्ड कंट्रोल पालिसी को लांच किया है, मैं उसके सिलसिले में फ़िनांस मिनिस्टर का दिल खोल कर बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने देश में ओपनली एलान किया कि जिसके पास सोना है, चाहे वह फ़ेयर मीन्ज़ से प्राप्त किया गया हो और चाहे फ़ाउल मीन्ज़ से, वह उसको जमा करके गोल्ड बांड्ज़ ले ले, वर्ना बाद में हम उस को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या यह कोई गुनाह है? मेरे लायक दोस्त, श्री रंगा, इस वक्त बैठे नहीं हैं। उन्होंने औरतों की बड़ी वकालत की। मैंने उस दिन व्हिप साहब से कहा था कि उनके बाद किसी लेडी मेम्बर को बुलवा दिया जाये, लेकिन इन्तजाम दूसरा था। हम सब जानते हैं कि हमारी मां बहनों ने दिल खोल कर अपने सुहाग के ज़वरात दिये और सोना-चांदी दिया। भारतीय नारियों के त्याग की गाथायें हमारे इतिहास के एक एक पन्ने पर लिखी हुई हैं। झांसी की रानी और दुर्गावती आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज भी वे ललनायें हमारे बीच में मौजूद हैं, जो अपने बेटे को तिलक लगाकर रण-क्षेत्र में भेज देती हैं।

इसके बाद श्री रंगा ने पचास लाख सुनारों की भी बड़ी वकालत की। जिन लोगों के घरों में ब्लैक मार्केटिंग का सोना होता है और चोरी से सोना गलाया जाता है, श्री रंगा ने उनकी वकालत की। इससे मुझे दुख हुआ। इस मुल्क में हमने ज़मींदारी का एबालिशन किया। "गरीबों को मिले रोटी, तो मेरी जान सस्ती है", हम ने यह नारा लगाया था। कांग्रेस वाले आज भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। जनसंघ के एक मेम्बर ने भी आज उनकी तारीफ की है। हम में यह हिम्मत है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टरों से लड़ते-झगड़ते हैं, लेकिन हम सौ और पांच आपस में होते हुए भी दूसरों के लिए १०५ हैं।

इस पवित्र सदन में १४ नवम्बर को हमने युनैनिमसली एक संकल्प पास किया था कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन मुझे दुख है कि आज जब कि मुल्क के सामने इतनी बड़ी प्राबलम है जब कि मुल्क पर विदेशी एटैक हुआ है, हमारे कुछ मित्र बाहर बड़ी बड़ी गालियां सुनाते हैं। हमारे देश में चार बड़ी हस्तियां हैं, जिनके नाम में नहीं लेना चाहता। कांग्रेस की बदौलत वे मिनिस्टर रहे गवर्नर रहे, गवर्नर-जेनरल रहे, क्या क्या नहीं रहे? वही लोग आज कांग्रेस के विरोध और इस देश के बड़े बड़े लीडरों के विरोध में काम करते हैं। कल तक वे मिनिस्टर थे, लेकिन चूंकि आज हम उनको नहीं रख पा रहे हैं, इस लिए हम बुरे हो गए। यह कितने अफसोस की बात है। मुझे क्षमा किया जाए, लेकिन हमारे यहां गांवों में एक कहावत मशहूर है कि जब कोई बुजुर्ग सत्तर बरस से ऊपर हो जाता है तो सठिया जाता है। मियां जब बूढ़ा हो जाता है वह होशियार हो जाता है। यह है नमूना हमारे देश की चार बड़ी हस्तियों का। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन जब वे इस तरह का व्यवहार करते हैं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। इस तरह का जो व्यवहार करता है, उससे बड़ा ट्रेटर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। बगावत का बिगुल बजाते हुए वे देश में घूमते फिरते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राणा प्रताप को जब जरूरत पड़ी तो भामा शाह ने खजाने खोल दिये थे। आज मैं पूछना चाहता हूं रंगा साहब से कि वे क्या कर रहे हैं। मुझे दुख है कि गायत्री देवी जी यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने ललकार कर कहा कि दस परसेंट और चौदह परसेंट प्रिवी पर्स का उन्होंने दान में दे दिया। ऐसा करके आपने बड़ी कृपा की है। इस आपत् काल में मैं तो कहूंगा कि आपने राजपूती शान को बट्टा लगाया है। राम राम। वह जब बोल रही थीं तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब वह यहां पर बैठी हुई थीं उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी तेजपुर गई हुई थीं। प्रो० रंगा भी उस वक्त यहां पर बैठे हुए थे। आज भी वह देश के कोने कोने में दौड़ फिर रही हैं और लोगों को तैयार कर रही हैं। उस बेचारी का नाम लिया जाए और उसको क्रिटिसाइज

साइज़ किया जाए, यह कहां का न्याय है। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मां बेटी दोनों जेल गए हैं। बाप जेल गया है। सारा खानदान तबाह हुआ है। आज भी वह देश के कोने-कोने में मारी-मारी फिर रही हैं और देश को तैयार कर रही हैं। जान उन्होंने अपनी हथेली पर रखी हुई थी जब वह तेजपुर गई थीं। वह नेफा गई थी। वहां पर कोई भी बम गिर सकता था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। उनमें देश की श्रद्धा है, उन पर देश का विश्वास है।

रंगा साहब कहते हैं कि वह कम्युनिस्टों के विरोधी हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मैं उनसे भी ज्यादा कम्यूनिस्टों का विरोधी हूं। मैं सांपनाथ और नागनाथ में कोई अन्तर नहीं जानता हूं। हम भी कम्युनिस्टों में विश्वास नहीं करते हैं। हम तो यह कहते हैं कि हर एक को बैन करो। उनके लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी के आठ सौ आदमी जेल में हैं मैं तो कहता हूं कि टेलीफान कर दो चीन को, टेलीफोन कर दो रशिया को कि यह इंडियन गवर्नमेंट में ही दम है, यह नेहरू गवर्नमेंट में ही दम है जो आप सबको जेल से बाहर रखे हुए हैं, उनको बाहर रखे हुए है जिन्होंने राज की बातों को कनवे किया है। इससे बड़ा आदर्श, इससे बड़ा नमूना आपको दूसरा नहीं मिल सकता है। यह हमारे देश का ही आदर्श रहा है और इसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। आज भी हम आपको सीने पर रखे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि एमरजेंसी पावर्ज़ का इस्तेमाल नहीं कि या गया है। मैं अगर एमर-जेंसी इंचार्ज डिफेंस मिनिस्टर होता तो रंगा जी को भी जेल में डाल देत हमने इन एमरजेंसी पावर्ज़ का इस्तेमाल ही कहां किया है? हमने तो बड़ी-बड़ी लीनियंसी बरती हैं। आपके इस व्यवहार पर आपको बड़ी आसानी से अन्दर किया जा सकता था।

पाकिस्तान के सिलसिले में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। उसके साथ हमारे भाईचारे के सम्बन्ध होने चाहियें। हमने बांट कर पाकिस्तान दिया है। हम भाई भाई रहे हैं आज भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ उनका प्रेम हो जाए, आज भी हम चाहते हैं कि हमारा मेल मिलाप हो जाए। अगर ऐसा हो सका और माननीय स्वर्ण सिंह जी अपने मिशन में कामयाब हो सके तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। अगर वार्ता में सफलता मिलती है, तो उनका नाम रोशन हो जाएगा। जो नीति हम पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपनाये हुए हैं, वह सही है। लेकिन हमको टीज़ किया जा रहा है। आज भुट्टो साहब पेकिंग गये हुए हैं। वहां पर वह बातचीत करेंगे। क्या हिन्दुस्तान को उन्होंने कमजोर समझ रखा है? हमारे चार हजार जवान मारे गये हैं लद्दाख और नेफा में। लेकिन हमने किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा है। हमने सीने पर गोलियां खाई हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी पीठ में कोई दूसरा छुरा घोपे। जो हमारे जवान मरे हैं वे बहादुरी दिखाते हुए मरे हैं। यह भारतीय इतिहास है और इसी का पालन उन्होंने किया है, इसी परम्परा का पालन उन्होंने किया है। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीर अभिमन्युओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चीन की गोलियां खाकर उन्होंने अपनी जान गवांई है, देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है।

अब मैं एग्रिकल्चर के सिलसिले में तथा कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं। दोनों मिनिस्टर यहां मौजूद हैं। मेरी उनसे शिकायत है। जो खाद पहुंचता है, जो फर्टि-लाइजर आप देते हैं, वह समय पर नहीं मिलता है, आपके अधिकारी बड़ा रोड़ अटकाते हैं रास्ते में। किसान आपसे सन्तुष्ट हैं आपकी चीज़ पहुंचती है। लेकिन समय से नहीं पहुंचती है। समय पर चीज देने का आप प्रबन्ध करें। कम्यूनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब से मैं कहता हूं कि जो जीपें हैं, उनको आप विदड्रा कर लें। हम से मिलिट्री के लोगों ने इसकी शिकायत की है, दूसरों ने शिकायत की है कि उनका मिसयूज हो रहा है। आप देखिये कि कांग्रेस वालों में ही दम है कि गवर्नमेंट की शिकायत गवर्नमेंट के सामने कर रहे हैं। आप भी इसको कान खोल कर सुन लीजिये हम पिछवाड़े

[श्री शिव नारायण]

से चोट नहीं करते हैं, सामने से करते हैं। इस चीज़ को आपको मोबिलाइज़ करना चाहिये। एन० सी० सी० की जो ट्रेनिंग हो रही है, उसमें डिसिप्लिन आना चाहिये।

यहां पर शिकायत की जाती है कि चन्दे जबर्दस्ती वसूल किये जाते हैं। मैं अधिकारियों के साथ गांव गांव घूमा हूं। पैसा लोग दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। किसी अधिकारी ने उनके डंडा नहीं मारा है और न ही उनको किसी ने डंडा मारा है।

**श्री रामसेवक यादव** : अधिकारियों ने मारा है।

**श्री शिव नारायण**: कहीं पर कोई ज्यादती नहीं हुई है। आप बाराबंकी ज़िले से आते हैं जहां पर एनार्की है, जहां पर हुल्लड़बाज़ी है। लेकिन वहां भी आज लोग दे रहे हैं और खुशी से दे रहे हैं। किसी अधिकारी के वहां पर गोली नहीं मारी गई है। हां मेरे एक साथी को वहां गोली मार दी गई थी पहले और मैं जानता हूं कि आप उस जिले से आते हैं। वहां पर अधिकारी आज पैसे पा रहे हैं और किसी के गोली नहीं मारी गई है।

हमारे रंगा साहब ने कहा कि इन एमरजैंसी पावर्ज़ को विदड्रा कर लो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम को इनको विदड्रा किए ही हुए हैं, इनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल करते तो आपकी बोल बन्द हो जाती। आप परेशान हो जाते। अंग्रेज़ों के ज़माने में एमरजैंसी पावर्ज़ का नक्शा आपने देखा था। जब दूसरी वर्ल्ड वार हो रही थी या जब १९४२ की मूवमेंट चली थी उस वक्त जो पावर्ज़ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली थीं, उनका नंगा इस्तेमाल होते हुए आपने देखा ही था। क्या उसको आप भूल गये हैं ? लेकिन हमारे यादव जी उस वक्त १८ साल के रहे होंगे और कालेज में पढ़ते रहे होंगे।

मान्यवर मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देश में ऐसी एकता आज तक कभी नहीं देखी गई है जैसी कि इस चीनी हमले के वक्त देखी गई है। हमारे रंगा साहब बड़े विद्वान हैं। उनसे मैं कहता हूं कि वह कृपा करके हिन्दुस्तान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जा कर देखें कि किस तरह से सारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। हमें चाहिये कि हम पहले चीन से निबट लें और बाद में हम आपस में निबटते रहेंगे। आज हमें अपने सारे मतभेद भुला देने चाहियें। हमारी एकता कायम रहनी चाहिये। मैं चार बड़ी हस्तियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं जो ग़लत प्रचार कर रही हैं। मैं भगवान से इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूं कि वह उनको सद्‌बुद्धि दे।

इन शब्दों के साथ श्री आर० एस० पांडेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें जो यह सन्देश दिया है "जागो, उठो" यह कितना सुन्दर है। इसका हमें पालन करना चाहिये।

†**श्रीमती अकम्मा देवी** (नीलगिरि) : कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों के बावजूद, हमने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित कर लिया है और अब तीसरी योजना को कर रहे हैं। निस्संदेह हमने देश का आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से निर्माण करने में बहुत प्रगति की है।

हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सैनिक बलों और आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं। श्रमिकों ने दिन रात काम किया है और राष्ट्रीय

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रतिरक्षा कोष में धन भी दिया है। इस के लिए वे बधाई के पात्र हैं। आयुध कारखानों में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पुराने संयंत्र बदले जायें और उन की जगह नए लगाये जायें।

राष्ट्रपति के साथ, मैं भी उन मित्र देशों के प्रति, विशेष कर अमेरिका और ब्रिटेन के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं, जिन्हों ने चीनियों के हमले के समय हमारी हार्दिक सहायता की। उन श्रमिकों के लिए जो दूर दूर से आते हैं, आवास की सुविधाएं देनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकार आयुध कारखानों की आवश्यकताओं को सब से अधिक प्राथमिकता दे। हमारे श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए अमेरिका या जर्मनी से विशेषज्ञ बुलाये जायें।

मुझे यह कहने में हर्ष होता है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में लोगों ने स्वेच्छा से चन्दा दिया है। यह कहना गलत है, जैसाकि विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने कहा है कि जबरदस्ती से काम लिया गया है।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

भारतीय महिलायें सोना और आभूषण अपनी इच्छा से दे रही हैं और जवानों की देखभाल के लिए अपनी सेवायें डाक्टरों और नर्सों के रूप में पेश कर रही हैं। बहुत सी ग्रामीण महिलाओं ने राइफल प्रशिक्षण के लिए अपने नाम दिये हैं।

योजनाओं के अन्तर्गत कृषि में सुधार करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो पग उठाये गये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। पानी की कमी के कारण हज़ारों एकड़ भूमि में कृषि नहीं की जा सकती। सरकार ऐसे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का उचित प्रबन्ध करे।

मद्य निषेध को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस का नैतिक स्तर ऊंचा किया जाये और उन्हें अधिक अच्छे वेतन दिये जायें, ताकि वे भ्रष्ट आचरण को न अपनायें।

†**श्री स्वेल** (आसाम—स्वायत्त शासी जिले): अभिभाषण की ३० कंडिकाओं में से लगभग ११ आपात काल के बारे में हैं। यह कहा जा सकता है कि आपात इस समय का सब से अधिक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए अभिभाषण में इस पर जोर दिया ही जाना चाहिए। किन्तु आपात की उद्घोषणा के बाद सरकार को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उन का कुछ हद तक दुरुपयोग किया गया है और इस सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये हैं, वह पूर्णतया निराधार नहीं हैं।

समाजवादी दल के सदस्य श्री कृष्ण पटनायक की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि इस समय सरकार की आलोचना करना बहुत खतरनाक है भारत की प्रतिरक्षा नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिस से आपात काल में ली गई शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

आपात काल के दौरान कोई भी उपचुनाव उचित ढंग से नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं, तो भारत के सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए चुनावों की अवधि के लिए सरकार को आपात हटा देना चाहिए, ताकि विरोधी पक्ष खुले तौर पर आलोचना कर सकें।

मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या उन की वर्तमान स्वर्ण नीति देश के हित में है। स्वर्ण नियंत्रण आदेश को सफलता नहीं मिली है क्योंकि देश में अनुमानित कुल ४००० करोड़ रुपये के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वेल]

मूल्य के सोने में से सरकार को केवल ५ करोड़ रुपये का गैर-ज़ेवराती सोना प्राप्त हुआ है। लाखों सुनारे और उनके आश्रित भूखों मर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को ५ करोड़ का सोना प्राप्त हुआ है, वह ५ करोड़ लोगों के कष्टों का उचित प्रतिकर है। स्वर्ण आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है जिस से पाकिस्तान में सोने को चोरी से ले जाये जाने को रोका जा सके। वहां पर सोने का मूल्य ६२.१५ रुपये प्रति तोला सरकारी मल्य के मुकाबले में १६० रुपये प्रति तोला है। इसलिए सोने के मुनाफ़ाखोरों को सोना जमा करने और उसे देश से बाहर भेजने से कैसे रोका जा सकता है।

अभिभाषण में आदिमजाति लोगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं। उत्तर-पूर्वी सीमान्त पर रहने वाली आदिमजातियों के लोग हमारी सीमा के प्राकृतिक प्रहरी हैं। यदि उन का आर्थिक विकास किया जाना है तो उन्हें देश के समान नागरिक मानना चाहिए और उन्हें उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। इस का एकमात्र हल यह है कि उन्हें अपना पूरा दर्जा दिया जाये।

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

†**डा० कोलाको** (गोआ दमन और दीव) : क्या यह सत्य नहीं है कि हम आत्म-संतुष्टि की भावना में डूब रहे हैं और आपातकाल के महत्व को पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं। क्या देश में हम ने बेरोजगारी की बड़ी समस्या की ओर से आंखें नहीं मूंद ली हैं, जिस के कारण स्वर्ण नियंत्रण आदेश और भी कठिनाई पैदा कर रहा है। क्या भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलता और कुंबापरस्ती दूर करने की ओर उचित ध्यान दिया गया है। इन को सख़्ती से हटाया जाना चाहिए और प्रशासकीय मशीनरी में ऊंचे नैतिक स्तर स्थापित किये जाने चाहियें।

भारत में आने के बाद गोआ, दमन और दीव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। गोआ, इस समय भारत के नकशे में एक काला धब्बा है। वहां बेरोजगारी फैली हुई है। पुराने लेटिन कानूनों के कारण और नये भारतीय कानूनों के कारण वहां पर भ्रम फैला हुआ है। अतिरिक्त प्रशासकों की उपस्थिति से सेवाओं को चलाने में बाधा पड़ती है और गोआनी कर्मचारियों पर विश्वास नहीं किया जाता। संकुचित वाणिज्यिक नीति जनसाधारण के लिए अत्यधिक हानिकर है और कुछ वस्तुओं के मूल्य असाधारण हद तक बढ़ गये हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों के भावी राजनीतिक दर्जे के बारे में सदन में जो विधेयक आने वाला है, मैं उस का स्वागत करता हूं। यदि इस में कुछ परिवर्तन किये जायें, तो इस से हमारी उन्नति का रास्ता खुल जायेगा। मेरा निवेदन है कि गोआ को संघ राज्य क्षेत्र रखने की बजाये, यदि भारतीय संघ का एक पूरा राज्य बनाया जाये, तो इस से हमारे उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। गोआ, दमन और दीव में कोंकणी भाषा को विकसित होने दिया जाये।

**श्री मौर्य** (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राष्ट्रपति जी के ३,००० शब्दों के सुन्दर और उच्च कोटि के भाषण को पढ़ने का मुझे मौका मिला। मैंने उसे बड़े गौर से पढ़ा। उस में मुझे बहुत सी विद्वत्तापूर्ण बातें देखने को मिलीं। इस के लिए मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं।

परन्तु आश्चर्य और खेद इस बात का है कि लाखों प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की आर्थिक समस्या, लगभग, २० करोड़ भूमिहीन मजदूरों की भयंकर दुर्दशा, २ करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, ७

---

†मूल अंग्रेजी में

करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट्स, १६ करोड़ बैकवर्ड क्लासेज, अर्थात् २५ करोड़ शोषित, पीड़ित, कठोर कर्मा, सर्वहारा समाज की आर्थिक तथा सामाजिक दुःखदायी समस्या के सम्बन्ध में एक शब्द भी आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। इस से आगे बढ़ कर जब मैं ने देखा कि भारत में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और संकटकाल में इमर्जेन्सी के दुरुपयोग तथा भारतीय सेनाओं की भारी पराजय के उपरान्त सरकार को चेतावनी के रूप में एक शब्द को भी आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्थान नहीं दिया गया है इन बातों को देख कर मेरे मन को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची ।

शिक्षा : सब से पहले मैं शिक्षा को लेना चाहता हूं जिस के विषय में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा है । हमारा संविधान है, हम संविधान को अपनी सब से ऊंची धार्मिक पुस्तक मान कर चल रहे हैं । उसी के आर्टिकल ४५ में, जोकि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक है, लिखा है :

> "राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ।"

आज संविधान को लागू हुए लगभग १३ वर्ष हो चले हैं । दस वर्ष की बात कही गई थी । कहा गया था कि दस वर्ष में इस भारत वर्ष में १४ वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा होगी । यह तो हमारे संविधान की पवित्र धारा ४५ कहती है । इसी तरह के सब १४ डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं । परन्तु आज मुझे खेद होता है कि संविधान की एक पवित्र धारा भी आज तक लागू नहीं हुई है । अभी भी राष्ट्र में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा १४ वर्ष तक के बालकों को नहीं दी जाती । इस से आगे बढ़ कर मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा को देने वाले जो अध्यापक हैं, अगर उन की दुःखदायी स्थिति और उन की दुर्दशा को देखा जाय, जोकि इस राष्ट्र के निर्माता हैं, जो इस राष्ट्र के भावी नेताओं के भाग्य विधाता हैं, जिन के ऊपर एक तरह से यह राष्ट्र आधारित है, कि वह ६० और ६५ रु० में किस प्रकार से अपना गुजारा करते हैं, तो और भी दुःख होगा । दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले मेहतर को भी ८० रु० मिलते हैं । खेद इस बात का है कि राष्ट्र के निर्माता, यहां के बालकों के आदर्श के रचयिता को ६० या ६५ रु० मासिक मिलते हैं । इस के बारे में भी कोई विशेष संकेत आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है ।

खेती के बारे में स्वयं राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैरा ४ में जोर दिया है, इस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं । वे कहते हैं "कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत आवश्यक अंग है ।"

यही नहीं आगे बढ़ कर उन्हों ने पैरा १५ में कहा है : 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कृषि का ठोस आधार चाहिए । अगर राष्ट्रपति जी की इन भावनाओं को देखा जाय, और खेती के लिए राष्ट्र में जो तैयारी है उस को देखा जाय तो वह एक दूसरे से बहुत अलग अलग नजर आती हैं । प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में खेती के लिए कितना धन रक्खा गया था और अन्य कार्यों के लिए कितना धन रक्खा गया था ? तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। उस के दौरान में जो भारत में ७५ फी सदी लोग खेती से ताल्लुक रखते हैं, उन के लिए कितना रुपया खर्च किया जा रहा है ? खेती के लिए कितना खर्च होगा । इस से पता चलेगा कि हमारी योजनायें उस भावना के ऊपर आधारित नहीं हैं जोकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैरा ४ और १५ में इस राष्ट्र के सामने, और संसार के सामने, रक्खी हैं । यही नहीं है बल्कि यहां पर भूमिधरी

[मौर्य]

आन्दोलन चला था, लोग भूमिधर बने । किसान भूमि के मालिक बने । उन्हों ने दस गुना दिया । किसी ने अपने बैलों को बेच कर, किसी ने अपनी स्त्री के जेवरों को बेच कर और किसी ने अपनी जमीन को बेच कर या मकान गिरवीं रख कर दसगुना दिया । उस के बाद आज चकबंदी की बीमारी उनके पीछे लगी है । यहां बहुत से आदरणीय सदस्य बैठे हैं, चाहे े कांग्रेस के हों या विरोधी दलों के, वे स्वयम् जानते हैं कि किस प्रकार चकबन्दी में भ्रष्टाचार का बोल बाला है, किस प्रकार से गरीब किसान का शोषण हो रहा है । चकबन्दी के बाद े कुछ आशा करते थे । उसके बाद कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया । लेकिन मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग में यहां के २० करोड़ लैंडलेस लेबर के लिए, २० करोड़ खेतिहर मजदूर के लिए कोई जगह नहीं है । जिन २० करोड़ मजदूरों ने जन्म जन्मान्तर से खेत जोता है, बोया है, पानी लगाया है, नराया और गहाया है, लेकिन खाया नहीं है, उन २० करोड़ मजदूरों के लिए जोकि भूमिहीन हैं उन के लिये कोई भी प्रोग्राम कोआपरेटिव फार्मिंग के पास नहीं है । इस कारण हम कहते हैं कि जो हल चलाने वाले शोषित समाज के किसान और मजदूर हैं और जो रात दिन पसीना बहा कर काम करते हैं उनको उनकी कमाई का अंश नहीं मिलता है और इसलिए ऐसी जमीन जहां कि वह हल चलाते हैं उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । इस भावना के ऊपर हमारे राष्ट्रपति जी की भावनाएं आधारित हैं । हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यह जरूरी है कि अनएकोनामिक होल्डिंग्स का सरकार राष्ट्रीयकरण करे । हम शोषितों के बाजुओं में इतनी ताकत है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर इतना अनाज पैदा करके दिखा सकते हैं कि अपने देश क्या समस्त ऐशियावासियों को हम अन्न खिला सकते हैं लेकिन सरकार अनएकोनामिक होल्डिंग्स का राष्ट्रीयकरण करे । डालमिया और बिड़ला जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के बड़े बड़े फार्म स्थित है और उनसे कोई भी इस देश को लाभ नहीं होगा ।

इससे आगे बढ़ कर भ्रष्टाचार के बारे में मैं जब देखता हूं तो पाता हूं कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक भी शब्द भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं कहा है । देश में आज भ्रष्टाचार का दमनचक्र लोकशाही के ऊपर बड़े जोर से चल रहा है और किसी दिन वह लोकशाही को हड़प सकता है । यह खेद का विषय है कि उन्होंने एक भी शब्द स भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं कहा ।

यह ठीक है कि मूंदडा और डालमिया को सजा मिली है लेकिन केवल मूंदड़ा और डालमिया को सजा देकर आप फ़ारिग़ नहीं हो जाते हैं और आप का कर्त्तव्य पूरा नहीं हो जाता है । इस देश के कोने कोने में और गली गली में मूंदड़ा और डालमिया मौजूद हैं । मैं स्व ं एक पूंजीपति के बारे में बतला देना चाहता हूं जो कि सत्ताधारी वर्ग को बहुत काफी धन देकर यहां के उद्योगों पर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे काला नाग धन पर बै ा रहता है, खजाने पर बै ा रहता है । न्हीं पूंजीपति महाशय को यहां दिल्ली में एक फील्ड आफिसर चाहिये । ५००० रुपये तनख्वाह देंगे जो फील्ड आफिसर उनके ब्लैक मनी को व्हा ट मनी बनाये, जो फील्ड आफिसर उनके काला बाजार के कमाये हुए पैसे को जोकि उन्होंने मज़लूम मजदूरों की आह लेकर कमाया है, उसे वहां दूसरों पर खुले खजाने काम करके दिखा दे कि वह वहां पर उनका व्हाइट ैसा है । मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि इस तरह के उद्योगपति और पूंजीपति जोकि आज शोषण कर रहे है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं उससे पूरा राष्ट्र तबाह होता चला जा रहा है । कम से कम वह शख्स शेखसादी के इस शेर से तो सबक सीखें :—

चूं आहंग रफ़तन कुनद जाने पाक,
च बरतख्त मुर्दीन च बरूये खाक ।।

ए पूंजीपतियो हमेशा के लिये तुम जिन्दा नहीं रहोगे, मरोगे, तुम्हारा भी अंत होगा लेकिन वहां पर लाखों करोड़ों मजदूर मजलूमों को मार कर और राष्ट्र का पतन करके तुम्हारा क्या भला होगा ?

इसके आगे मैं संकटकाल (इमरजेंसी) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि संकटकाल (इमरजेंसी) का दु पयोग हुआ है और हो रहा है। सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार ने बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चाहे वे शोशलिस्ट हों, कम्यूनिस्ट हों या अन्य राजनीतिक दल या पार्टी के कार्यकर्ता हों, उनको अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल कर गिरफतार किया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस एमरजसी में नौकरशाही पनप रही है। उसको बढ़ावा मिल रहा है। स्वयं जिस अलीगढ़ से मैं आता हूं वहां पर मुहम्मद नादिर ऊर्फ नादिर अली के नाम से एक इंसांन है। किसी पार्टी में वह चार आने का सदस्य नहीं है। किसी राजनीतिक मंच से वह कभी बोला नहीं। बोलना तो दरकिनार कभी किसी राजनीतिक मंच पर बैठा न ीं चाहे वह कांग्रेस का हो या विरोधी दल का हो। जो राजनीति का नाम नहीं जानता लेकिन आज वह वहां के कलक्टर साहब की तानाशाही का शिकार हो रहा है। डी० आई० आर० लागू करके उस मासूम इन्सान को जेल के सीखचों में डाल रखा है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं मैम्बर साहब से कहूंगा कि एक इंडिविजुअल का, किसी एक शख्स का केस रिप्रेजेंट न करें।

**श्री मौर्य :** यह केस बड़ा जरूरी है। मैं इसे नहीं रखना चाहता था लेकिन इसको लेकर पूरे जिले में तूफान सा मचा हुआ है . . .

**अध्यक्ष महोदय :** इस तरह से एक इंडिविजुअल केस को नहीं रख सकते और कलक्टर साहब के बरखिलाफ इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।

**श्री मौर्य :** खैर मैं इसे छोड़ कर आगे चलता हूं।

आदरणीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैरा १४ में यह कहा है :—

> "एमरजैंसी का एलान हो जाने के बाद जल्दी ही मजदूरों और प्रबंधकों की केन्द्रीय संस्थाओं ने उद्योगों में शांति बनाये रखने के लिये एक राय हो कर प्रस्ताव पास कर दिया जिसका मकसद यह था कि कारखानों में झगड़े बिल्कुल खत्म कर दिये जायें, उत्पादन को बढ़ाया जाए और जहां तक हो सके लागत में कमी की जाये। इसका नतीजा यह हुआ है कि केन्द्र में राज्यों में और बहुत से कारखानों में एमरजेंसी उत्पादन कमेटियां बना दी गई हैं।"

इस तरह की भावना मजदूरों के अंदर जाग्रत हुई। स्वयं राष्ट्रपति जी ने इस की ओर वहां पर पूरे राष्ट्र का ध्यान इस ओर दिलाया है लेकिन यह खेद और दुर्भाग्य का विषय है कि पूंजीपतियों ने मजदूरों की इस भावना से नाजायज फायदा उठाया है। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने इस पवित्र प्रतिज्ञा की आड़ में कठोर कर्मा सपूतों का शोषण किया है। जितना काम उन्हें करना चाहिये था उससे ज्यादा किया, पीक औवर्स में काम किया। उससे ूजीपतियों का फायदा हुआ।

स्वयं मेरे यहां के एक पूंजीपति हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी बात कहूं तो कहा जायगा कि फिर अलीगढ़ की बात करते हैं लेकिन मुझ से कहे बगैर नहीं रहा जाता कि हमारे चीफ मिनिस्टर वहां रहते हैं। इसी इमरजैंसी के जमाने में ४ लाख की जायदाद, चार लाख सा लगा कर उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें कि हमारे चीफ मिनिस्टर आकर आराम करते हैं। एक तरफ तो यह चक्कर हो और दूसरी तरफ मजदूर इमरजैंसी में न दे रहे हैं . . .

**अध्यक्ष महोदय :** आर्डर, आर्डर। मैंने मैम्बर साहब को कहा है कि यहां किसी के बरखिलाफ जिसको कि उसका जवाब देने का मौका न हो, कुछ न कहा जाय।

**श्री मौर्य :** मैं किसी का नाम नहीं ले रहा . . .

**अध्यक्ष महोदय** : इससे ज्यादा क्या नाम लिया जा सकता है ? क्या कोई सदस्य समझ नहीं रहे है ?

**श्री मौर्य** : मैं यही कहूंगा कि इस इमरजेंसी को हटाया जाय। इससे राष्ट्र को फायदा नहीं हो रहा है। बल्कि इससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। इमरजेंसी के हटने पर जो लोग चीन से मिलकर मुल्क को दगा देना चाहे या किसी और मुल्क से मिल कर देश के प्रति गद्दारी करना चाहें उन के लिए हमारे पास कानून है। उनके लिए नौर्मल लाज औफ दी लैंड काफी हैं। प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट है और ला आफ सैडीशन आदि हमारे पास मौजूद है। इनकी सहायता से हम देश द्रोहियों से निपट सकते हैं। मैं इसलिए मांग करता हूं कि इमरजेंसी को समाप्त किया जाय।

इमरजेंसी के होते हुये यहां पर उपचुनाव होने की बात चली है। बात साफ यह है कि इमरजेंसी के रहते उपचुनाव ईमानदारी तथा स्वतंत्रतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकते। आज हमारी जबानों पर ताला पड़ा हुआ है और वहां पर खुल कर कोई बात नहीं कही जा सकेगी। सत्तारूढ़ वर्ग के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही जा सकेगी, सत्ताधारी नेताओं और उनके द्वारा चलाई जा रही गवर्नमेंट के खिलाफ खुल कर कुछ भी कहा नं जा सकेगा। जिससे कि सारे राष्ट्र को धक्का पहुंचा है। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि इमरजेंसी के रहते हुये उपचुनाव ईमानदारी से निष्पक्ष नहीं कराये जा सकते हैं।

भारतीय सेनाओं के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सेना में भरती जातीयता के नाम पर हुई है। सन ४३ में अंग्रेजों के जमाने में इसके बारे में इश्तिहार निकलते थे जिनमें लिखा जाता था कि क्षत्रियों की भरती है, ठाकुरों की भरती है। इस तरह के पैम्फलैटस सन ४३ में देखे थे लेकिन आज जब कि जनतंत्र राज्य है, जबकि हम यह दावा करते हैं कि हम जातीयता में विश्वास नहीं करते है तब इस तरह के नोटिसबोर्ड लिखे जायें कि यहां पर अछूतों की चमारों की और भंगियों की भरती नहीं है, यह इस राष्ट्र के लिये शोभाजनक प्रतीत नहीं होता। यह बड़े अफसोस की बात है। जहां तक मार्शल कम्युनिटी की बात है मैं यह बता देना चाहता हूं कि मार्शल कम्युनिटी के बारे में अगर इतिहास उठा कर देखा जाय तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि शैडयूल्ड कास्टस या बैकवर्ड क्लासेज किसी भी माने में किसी भी मार्शल कम्युनिटी से कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। सन ४३ के बाद में भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि चमार और महार रैजीमेंट बनीं। उन्होंने इस देश की सीमाओं पर और यूरोप और इंग्लैंड में जाकर इस तरह से अपनी बहादुरी का सबूत दिया है सर पैट्रिक कारडिल जनरल हिंस के लेख, महार तथा चमार रैजीमेंट की वीरता से भरे पड़े हैं। तब यह जातीयता के नाम पर सेना में भरती करना और जातीयता के नाम पर रैजीमेंट बनाना देश के भविष्य को खतरे में डालना है। मैं यहां पर यह नहीं कहता कि चमार रैजीमेंट खोली जाय, भंगी रैजीमेंट खोली जाय। लेकिन वहां पर महार रैजीमेंट ने जैसी बहादुरी से काम किया उसी तरह से चमार और अन्य जो छोटी कही जाने वाली जातियां हैं वे भी बहादुरी के साथ काम कर सकती हैं। इसलिये जातीयता के नाम पर रैजीमेंट को समाप्त किया जाय और अगर उनको समाप्त न किया जाय तो जातीयता के नाम पर जो रैजीमेंट सन ४३ में बनी थी, ४४ में थी, ४५ में थी उनको सन १९४६ में कांग्रेस सरकार ने क्यों समाप्त कर दिया ?

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

**श्री मौर्य** : प्रदेश आपस में झगड़ रहे हैं। इस तरह की चर्चा सदन में आई और अखबारों में भी सुनने में आता है कि केवल प्रदेश ही आपस में नहीं झगड़ रहे है बल्कि केन्द्रीय मंत्री भी इस बात की शिकायत करते हैं कि वह केन्द्रीय सरकार के साथ में कोआपरेट नहीं करते हैं, केन्द्रीय सरकार का सहयोग नहीं करते हैं। इस के बारे में आदरणीय प्रेसीडेंट साहब को कुछ कहना चाहिये था। आज तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है, केन्द्र में भी और प्रदेशों में भी। जब उनमें आपस में यह नहीं चल पाता है तो भविष्य में किस तरह से निबटारा होगा, जबकि कहीं कम्यूनिस्ट सरकार होगी, कहीं सोशलिस्ट

सरकार होगी, कहीं रिपब्लिकन सरकार होगी तो कहीं कांग्रेस—कांग्रेस का तो मेरे ख्याल से कहीं नामोनिशान कुछ दिन बाद इस देश में नहीं रहेगा। जब बहुत सी पार्टियों की सरकार बनेगी तब साथ में किस तरह से पटरी बैठेगी और काम चलेगा।

चिकित्सा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि बराबर का सब को खाना मिले, मैं यह नहीं कहता कि एक तरह के सबको रहने के वास्ते मकान मिले, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर किसी पूंजीपति का बालक टी० बी० का शिकार हो और मिल में काम करने वाले मजदूर का बालक टी० बी० या तपेदिक का शिकार हो, तो कम से कम अगर खाना उनको एक जैसा नहीं मिल सकता, पढ़ने की व्यवस्था एक सी नहीं मिल सकती, रहने को एक जैसा नहीं मिल सकता तो कम से कम उनका इलाज तो एक जैसा हो। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस तरह का प्रजातंत्र है? यह किस तरह का स्वतंत्र भारत है जिसमें लाखों मजदूरों के बच्चे बगैर इलाज के मर जाते हैं? हजारों अस्पताल इस मुल्क में ऐसे हैं जो कि देहात या कस्बे में हैं और जिनमें कि कोई डाक्टर नजर नहीं आता।

एक बात कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय से तीन मिनट का समय और चाहूंगा। मेरी पार्टी से कोई भी नहीं बोला है।

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं केवल एक मिनट और ले लीजिए।

**श्री मौर्य** : कृपया दो मिनट तो मुझे दे ही दिये जायें।

**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा आगे बढ़िये।

**श्री मौर्य** : श्रीमन्, यहां पर २५ करोड़ शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति बसते हैं जिनमें कि २ करोड़ शैडयूल्ड ट्राइब्स हैं, ७ करोड़ शैडयूल्ड कास्टस् हैं और १६ करोड़ बैकवर्ड कलासेज के लोग हैं। भारत के इन २५ करोड़ शूद्र कहे जाने वाले व्यक्तियों के आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के विरुद्ध एक शब्द भी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में नहीं है। राष्ट्र के २५ करोड़ शूद्र कहे जाने वाले विशाल जनसमूह को यदि सामाजिक तथा आर्थिक शोषण की धधकती ज्वाला से नहीं बचाया गया तो लोकशाही का यह शीशमहल भी उसी ज्वाला में जल कर खाक हो जायेगा . .

**एक माननीय सदस्य** : अब कोई शूद्र नहीं कहता।

**श्री मौर्य** : यह भी खूब रही। आप शू के नाम पर इनाम देते हैं, आप नौकरियां देते हैं। आप बहुत से लोगों को एम० एल० ए० और एम० पी० को अछूत के नाते से इस सदन में बै ते हैं किस तरीके से आप नहीं मानते? आप मानते हैं अलबत्ता हम नहीं मानते और हम इस बात को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन आपकी सरकार मानती है और जातीयता का नाम देती है। वह जातीयता के नाम पर पगड़ियां और तमगे देती है। माननीय सदस्य उस को कैसे नहीं मानते?

मैं कह रहा था कि अगर पिछड़े वर्गों पर यह दमनचक्र इसी तरह से चलता रहेगा, अगर यह ज्वाला इसी तरह से उन के सिरों पर धधकती रहेगी, तो यह ज्वाला लोकशाही के शीशमहल को भी एक दिन जला देगी। मेरी विनती है कि हम इस देश के एक बहुत बड़े अंग को भुला कर लोकशाही को इस मुल्क में जीवित नहीं रख सकते हैं। आज मुझे आदरणीय बाबा साहब डा० अम्बेडकर के ये शब्द याद आते हैं कि "जातिविहीन समाज की स्थापना के बिना स्वाराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है।" यद्यपि आज हम आजाद हैं, लेकिन जातीयता के अजायबघर आज भी इस मुल्क में मौजूद हैं।

[श्री मौर्य]

है ? इस तरह की आजादी कहना आजादी को आजादी की तौहीन है, आजादी का मजाक उड़ाना है। यह किस तरह की लोकशाही इस तरह की लोकशाही पर चल कर हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब अपना भाषण खत्म कर दें।

**श्री मौर्य**: अखबारों से मुझे मालूम हुआ कि राज्य सभा में श्री वाजपेयी ने काश्मीर के संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर, श्री तैयबजी के भाषण के कुछ अंश को क्वोट किया। लेकिन उन के भाषण की एक लाइन उस में से छोड़ दी गई। अगर उस लाइन को जोड़ दिया जाए, तो जिन के खिलाफ वह बात कही गई थी, उनके साथ न्याय हो सकता है और श्री वाजपेयी को अपनी बात का जवाब भी मिल जाता है। राज्य सभा में उन्होंने इस भाग को क्वोट किया था :–

> "पाकिस्तान को काश्मीर का पाकिस्तान द्वारा अधीकृत क्षेत्र तथा वे प्रदेश प्राप्त हो जाने चाहियें जो उसके विकास के लिये आवश्यक हैं। लेकिन श्री तैयबजी ने इस संबंध में जो यह कहा था कि झेलम की घाटी वाला भाग भारत को मिलना चाहिये।" उसको छोड़ दिया गया। अगर इस लाइन को उद्धरण के साथ जोड़ दिया जाये, तो श्री वाजपेयी के राज्य सभा में जो कुछ कहा, उस के माने उल्टे हो जाते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त कर दें।

**श्री मौर्य** : अन्त में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हम इस देश के दबे हुए, उत्पीड़ित और शोषित लोगों को उठाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करें। अगर हम इस देश को करोड़ों लोगों को भूल जाएंगे और जातीयता पर आधारित असमानता और विषमता को बढ़ायेंगे तो फिर लोकशाही कभी भी इस मुल्क में जीवित नहीं रह सकती है। लोकशाही और जातीयता एक साथ नहीं रह सकते। जनतंत्र और असमानता एक साथ नहीं रह सकते। समता में ही लोकशाही जीवित रह सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए आप को धन्यवाद देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जबर्दस्ती बोलते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वह मुझे धन्यवाद देते हैं।

†**श्री** ह० प० चटर्जी (नवद्वीप) : स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् से हमें जिन संकटों का सामना पड़ा है यह उनमें सबसे विकट है। चीनियों ने खुले आम इस बात की घोषणा की है कि वे युद्ध के जरिये साम्यवाद लायेंगे। तिब्बत को साम्राजवादियों के चंगुल से छुड़ाने के नाम पर उन्होंने जो कुछ किया इतिहास सदैव उसका साक्षी रहेगा।

चीन पाकिस्तान और नेपाल से मित्रता बढ़ा रहा है। वह रूस की परवा भी नहीं करता है न उसे विश्व के जनमत की ही चिन्ता है। अतः हमें सारे मतभेद भुलाकर इस संकट का सामना करने को तैयार हो जाना चाहिये। मेरे विचार से समस्त राजनैतिक दलों को समाप्त कर दिया जाये और अपनी सारी शक्तियों इस संकट का सामना करने को केन्द्रित कर दिया जाये।

सरकार यह सुनिश्चित करे कि आपात के दौरान इस को जो अधिकार प्राप्त है उनका दुरुपयोग न किया जाये। ऐसे अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने के कई उदाहरण हैं। इसकी आड़ में पदाधिकारियों ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है जिनको वे नहीं चाहते हैं। मैं इसका एक उदाहरण

†मूल अंग्रेजी में

रखना चाहता हूं । एक हाई स्कूल के अध्यापक को उस जिले के एक प्रभावशाली व्यक्ति की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करने पर उन्हें साम्यवादी विचारों से सहानुभूति रखने वाला बताकर कैद में डाल दिया गया है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं ।

इसी प्रकार एक विधान सभाई सदस्य का घर लूट लिया गया। तथा राजनेतिक स्पर्द्धा रखने वाले कुछ सदस्यों ने उसके घर पर हमला बोल दिया ।

**श्री बालकृष्ण सिंह** (चन्दौली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे भी धन्यवाद देने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण यद्यपि संक्षेप में है लेकिन उस में अपने देश के वर्तमान और भविष्य का स्वरूप देखा जा सकता है। भारत ने जिस समाज की रचना का संकल्प किया है उस लक्ष्य की तरफ अब तक देश ने क्या किया है उस का संक्षिप्त विवरण देते हुए राष्ट्रपति ने उस संकट की ओर संकेत किया है जो चीन के आक्रमण से इस देश के सामने है। भारत शांतिप्रिय देश है और शांति के तरीके से अपने देश का निर्माण कर रहा था । लेकिन चीन को यह बात पसन्द नहीं थी कि भारत अपने प्रयोग में सफल हो। वह चाहता था कि भारत की तमाम योजनाएं विफल हो जायें । सलिये सीमा का झगड़ा खड़ा करके हमारे देश पर आक्रमण किया है। हमारी सभी योजनाओं को विफल करने की उसकी मंशा है। यदि इस बात का हमारी योजनाओं पर असर पड़ता है तो चीन की जो मंशा है उस की पूर्ती होती है। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि साधारण परिवर्तन के साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना चलती रहेगी । राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च संरक्षक की हैसियत से इस सदन को विश्वास दिलाया है कि यह सदन साहस, बुद्धिमानी, धैर्य, सहिष्णुता और कोआपरेशन के साथ उसे कार्यान्वित करेगा। यह सलाह समय के अनुसार है क्योंकि यह सदन जिम्मेदार है इस देश की नीतियों का निर्धारण करने के लिये और उसके नेतृत्व के लिये ।

चीन ने इस देश के साथ विश्वासघात किया, उस ने मित्र की परिभाषा को बदला है। अचानक इस देश पर आक्रमण करके उसने अपने सैन्य बल का प्रदर्शन किया है। शातिपूर्ण ढंग से अपनी समस्या को सुलझा लेने में हमारा विश्वास है, लेकिन यदि कोई देश शांति नहीं चाहता, और जिस से विश्व की शांति को खतरा है, तो जरूरी है कि उसे शांति का पाठ पढ़ाया जाये। जिस धृष्टता के साथ चीनियों ने हमारी भारत भूमि पर अपने अपवित्र चरणों को रक्खा है उस से देशवासियों को बड़ा रोष है। उस आक्रमण के कारण आज अपने देश में जिस तरह की राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ है और जिस तरह की एकता हुई है, वह इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं थी। इसलिये जितना शीघ्र हो सके इन चीनियों को इस भारत भूमि से निकाल बाहर किया जाय। लेकिन यह सब काम होना चाहिये पूरी तैयारी के साथ । कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों को मान कर इस देश ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। इस से तटस्थ और मित्र देशों को यह समझने का अवसर मिला है कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान नहीं चाहता, चीन सीमा समस्या को सुलझाना नहीं चाहता । उसकी नीति दूसरी है। उससे इस देश को छुटकारा मिले, इस के लिये जरूरी है कि अपने यहां पूरी सैनिक तैयारी हो। राष्ट्रपति को चाहिये था कि कुछ इस संकट के प्रति अपने अभिभाषण में अधिक उल्लेख करते। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ही संकेत किया है। देश को विश्वास है अपने देश के सैनिकों के शौर्य और वीरता पर। वे स्वतंत्र भारत के सैनिक ही नहीं है बल्कि उस भारत माता के लाल हैं जिस के सिर पर चीनियों ने आघात करके उस की मर्यादा को धक्का पहुंचाया है। आज देश के बच्चों का स्नेह युवकों का सहयोग और बुड्ढों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। आज उन्हें अच्छे हथियार दिये जायें । वे अच्छे हथियार जिन का निर्माण चाहे देश में हो या जो हमारे मित्र देश हैं उन से मंगाये जायें, ताकि हमारे सैनिक समर्थ हों चीनीयों को भारत भूमि की सीमा से बाहर कर देने में।

[श्री बाल कृष्ण सिंह]

इस संकट की घड़ी में उद्योगपतियों में अभी राष्ट्रीय भावना की बहुत कमी है। उनकी मिलों और उद्योगों में काम करने वाले मजदूर उन से आगे हैं। उनको प्रेरणा लेनी चाहिये अपने यहां के मजदूरों और श्रमिकों से। एक तरफ तो मजदूर इस देश का निर्माण करने के लिये, उत्पादन को बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प हैं और दूसरी तरफ मिल मालिक उन के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण बतलाऊं। हमारी कांस्टिट्यून्सी में एक साहू केमिकल फैक्ट्री, वाराणसी में है। वहां पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। इस खाद को बनाने के लिये कारबन मोनो आक्साइड गैस तैयार होती है। वहां पर ो ब्वायलर हैं। एक ब्वायलर में काम होता है और दूसरे की मरम्मत होती है। ७ फरवरी १९६३ को जिस ब्वायलर की मरम्मत हो रही थी उस में मजदूर काम कर रहे थे। अचानक उस में कारबन मोनो आक्साइड गैस आ गई और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वह बेहोश हो कर नीचे गिर पड़े। सूचना मिलने पर जितने कर्मचारी वहां पर थे या जो दूसरे लोग थे वे उन को बचाने के लिये दौडे। सब उस में बेहोश होते गये। एक नौजवान इंजीनियर भी दौड़ा कि किसी तरह से उन लोगों को बाहर निकाला जाय, वह भी ऊपर से गिरा और उस के सिर में चोट आई। वह खून से लथपथ हो कर बेहोश हो कर गिर पड़ा। जब किसी तरह से प्लान्ट को बन्द किया गया और आदमियों को उस में से निकाला गया तो ३४ आदमी बेहोश थे। उस फैक्ट्री में एक भी ऐम्बूलेन्स नहीं थी कि उन लोगों को ढोकर के अस्पताल ले जाया जाता। उस गैस के उपचार के लिये उस कारखाने में कोई सामग्री नहीं है। ट्रकों में लाद कर उन्हें वाराणसी में कबीर चौरा अस्पताल ले जाया गया। उन में से तीन आदमियों को जान से हाथ धोना पड़ा। धन्यवाद है उस चौरा अस्पताल के डाक्टरों और वहां के कर्मचारियों को जिन्होंने तत्काल उपचार का प्रबन्ध किया और उन को होश में लाये। मुझे शिकायत मिली है कि उस फैक्ट्री में जो गैस को ले जाने के लिये पाइप होते हैं वे बहुत निकृष्ट कोटि के हैं और किसी वक्त भी स किस्म की दुर्घटना हो सकती है। यह जो दुर्घटना हुई है वह बहुत बड़ी चीज है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में जहां इतनी जहरीली गैस तैयार होती है कोई ऐम्बुलेन्स नहीं है और न वहां पर गैस के उपचार के लिये कोई अस्पताल या साधन है। मैं निवेदन करूंगा कि इस संकट की घड़ी में जब मजदूर देश के निर्माण और औद्योगिक उत्पादन में लगा हुआ है तो उस को मिल मालिकों की इस प्रकार की असावधानी से बचाना चाहिये। मैं चाहूंगा कि इस फैक्ट्री की खुली जांच हो।

मुझे आप का अधिक समय नहीं लेना है। केवल ो तीन बातों के सम्बंध में कुछ निवेदन करना है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय हिन्दी के प्रश्न को ले कर घटना घटी उस के लिये मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं हिंदीभाषी क्षेत्र का रहने वाला हूं, उस बनारस जिले का हूं जहां पर नागरी प्रचारिणी सभा है और जो हिन्दी के उत्थान के लिये बहुत बड़ा कार्य कर रही है, और पहले भी हिन्दी की तरक्की और उत्थान के लिये उस संस्था के सदस्यों ने अपना जीवन लगाया था। मुझे बडा दुःख है कि हिन्दी को ले कर एक अशोभनीय घटना घटी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी किसी एक पार्टी की भाषा नहीं है, वह समूचे देश की भाषा है, हिमालय पहाड़ से ले कर कन्या कुमारी अन्तरीप तक। हमारे देश निवासियों में हिन्दी पढ़ने की लगन है। हिन्दी के प्रति उनका प्रेम है। दक्षिण भारत के जिन वक्ताओं ने यहां पर कहा उन लोगों ने भी इस बात को बतलाया कि दक्षिण में लोग बड़ी तेज़ी के साथ हिन्दी सीख रहे है। हिन्दुस्तान की जितनी भाषायें हैं सब पूरे देश की भाषाएं हैं चाहे हिन्दी हो या दूसरी भाषा हो। हिन्दी राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन की गई है। हिन्दी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र भाषा के प्रति कोई भी व्यक्ति कोई दूसरी बात नहीं सोच सकता। हिन्ी की आड़ में किसी पार्टी को अपने पोलिटिकल स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। हां यह अलग बात है कि हिन्दी के विकास के लिए यदि कहीं पर कोई रुकावट होती हो या कहीं सरकारी तौर तरीके के माध्यम में कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उस की ओर जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर मैं आप का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कुछ टैकनिकल संस्थाओं जैसे बम्बई, खडगपुर, कानपुर और मद्रास की टैकनिकल संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा मई के पहले सप्ताह में होगी। उस के लिए प्रश्नपत्र अंग्रेजी में होंगे और यह कहा गया है कि उस का उत्तर अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से दिया जाये। अंग्रेजी से हमारी कोई शिकायत नहीं है। अंग्रेजी से मुझे भी प्रेम है और जब तक हिन्दी में तमाम काम ठीक से और सब टैक्निकल टर्म्स ठीक नहीं हो जाते तब तक अंग्रेजी भी इन संस्थाओं में रहनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, जो राष्ट्रभाषा है और हमारे देश के कई प्रान्तों में साइंस की पढ़ाई हिन्दी के माध्यम से होती है तो जब हिन्दी के माध्यम से साइंस की पढ़ाई होती है और यहां अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में उत्तर देने के लिए अगर कहा जायगा तो हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़े हतोत्साहित होंगे और हिन्दी के विकास में इस का बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन टैक्निकल स्कूलों में जहां पर इन संस्थाओं में भरती होने के लिए परीक्षा होने वाली है वहां अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी उत्तर देने की अनुमति दी जाय क्योंकि हमारे देश में साइंस की पढ़ाई हिन्दी के माध्यम से भी होती है।

मान्यवर, आज देश के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि खेती को प्रोत्साहन दिया जाये। ऐसी बंजर और ऊसर जमीनें जहां है उन को किसान तोड़ कर खे ी के योग्य बनाये।

एक और अव्यवस्था हो रही है। हमारी कांस्टीटुएंसी में चकिया तहसील है। वह एक पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी इलाके के सम्बंध में मान्यवर, मैं समझता हूं कि वहां के निवासियों के पास खेती योग्य भूमि नहीं है और जीविका का अन्य कोई साधन नहीं है, तो उन्हें अगर कानून परिवर्तन करने के बाद भी कोई सुवि ा उन के जीविकोपार्जन और विकास के लिए अगर मिल सकती है तो देनी चाहिए। वहां पर महाराज के टाइम में गांव की जमीन माल विभाग के अधीन थी और बाकी फौरेस्ट की जमीन फौरेस्ट विभाग की देखरेख में थी। मैं विनेदन करूंगा कि विलयन के बाद भी जो जमीन महाराज के टाइम में माल विभाग के अधीन थी वह माल विभाग की रहे और जो जंगल विभाग की थी वह जंगल विभाग की रहे।

अन्त में मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि अभी मैंने अखबारों में देखा है कि दो, एक सर्वोदय नेता यह कहते हैं कि लद्दाख और नेफा के ऐरिया में जहां चीनियों ने क़ब्जा कर लिया है, कुछ बिना हथियार के लोग वहां जाकर सत्याग्रह करें। अब मान्यवर, सत्याग्रह की बात तो मेरी समझ में आती नहीं, हां एक बात समझ में आती है कि यदि सर्वोदयी नेता और उन के कार्यकर्ता उस चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र में जा कर दो-दो, एक-एक को टोली बना कर गांवों में बसें और वहां के लोगों के मनोबल को ऊंचा करें और अपने रचनात्मक कार्य द्वारा उन गांवों का विकास करें तो देश का बड़ा कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

**श्री कुलेश्वर मीना** (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले आप को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अपनी मैडेन स्पीच देने के लिए आप ने मुझे समय दिया। राष्ट्रपति महोदय का अभिभा ण जोकि संसद के ोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समक्ष दिया गया उस का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ बातें जो उन के भाषण में मिली उन को मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में देश को यह आवाहन किया कि उठो, जागो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाये। श्रीमन् हमारा देश आजादी के पश्चात शनैः शनैः प्रगति कर रहा था और अपनी पंचव ीय योजनाओं के द्वारा देश का विकास कर रहा था। परन्तु इसी बीच हमारे पड़ौसी देश चीन ने भारत पर आक्रमण किया। वह आक्रमण केवल आक्रमण ही नहीं वरन् एक बर्बतापूर्ण आक्रमण था। इस आक्रमण से देश को एक फ़ायदा यह हुआ कि इतिहास

[श्री धुलेश्वर मीना]

ने एक नया सबक पेश किया और वह यह कि देश एकता के और संगठन के सूत्र में बंध गया और देश का प्रत्येक नागरिक यह महसूस करने लगा कि देश के प्रति उस का क्या कर्त्तव्य है। देशवासी यह समझने लगे कि मुल्क की आजादी को कायम रखने के लिये उन्हें क्या करना चाहिए। लोगों ने खुशी से न दिया, खून दिया और जवानों को भी दिया। इस के साथ ही न केवल हमारे देश के ही अन्दर बल्कि विदेशी राष्ट्रों ने भी हमारा साथ दिया चाहे वह कम्युनिस्ट मुल्क हों या नौन-कम्युनिस्ट मुल्क हों। हम यू० एस० ए० और यू० के० के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं साथ ही यू० एस० एस० आर० का भी कि ऐसे विपत्ति काल में वायदे के अनुसार उसे जो मिग विमान देने थे उसे देना उस ने स्वीकार किया ।

इस सदन के कुछ माननीय सदस्य देश के नेताओं से यह बारबार कहते हैं कि इमरजेंसी को ख़त्म कर देना चाहिए। इस समय सरकारी पार्टी ही इस इमरजेंसी का फायदा उठा रही है। ख़ास कर मैं प्रोफेसर रंगा के इस वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस में उन्होंने यह कहा कि समय आ गया है जबकि देश की सरकारी पार्टी को कम्युनिस्ट पा र्टी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आपतकालीन स्थिति का नाजायज़ फ़ायदा सत्तारूढ़ पार्टी उठा रही है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा हाउस को यह कहना चाहता हूं कि क्या इस आपतकालीन स्थिति का फ़ायदा सत्तारू पार्टी ही उठा रही है? मैं यह कहना चाहता हूं कि जबकि इमरजेंसी चल रही है, हमारी कांस्टीटुएंसी के अन्दर रक्षा कोष के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा था तो दूसरी तरफ़ स्वतंत्र पार्टी की मीटिंग चलती थी और उन्होंने लोगों में यह गलत धारणा फैलाई कि देखिये आपने पहला गलत काम यह किया कि कांग्रेस पा र्टी को वोट दिया और वोट देने के साथ आप से अब चंदा वसूल ो रहा है। "कल आप से ब्लड लिया जायेगा। आज जवान लिये जाते हैं। कल अपनी ज़मीन को बेच कर आप को चन्दा देना पड़ेगा।" इस तरह से जनता में ये ग़लत धारणायें फैलाई जाती हैं। इस से प्रकट होता है कि इमरजेंसी का नाजायज़ फायदा ये उठा रहे हैं, न कि सरकारी पार्टी। मुझे यह कहने के लिए माफ़ किया जाये कि सरकार की ढीली नीति भी इस के लिए जिम्मेदार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस इमरजेंसी पीरियड में इस प्रकार की पार्टियां और इस प्रकार के लोगों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है ।

यह दिखाई देता है कि दो तीन दिन के बाद फिनांस मिनिस्टर साहब जो बजट पेश करेंगे, उस में कुछ इनडाइरेक्ट टैक्सिज़ लगेंगे। लेकिन जो इनडाइरेक्ट टैक्सिज़ लगते ये, वे केवल इन डायरेक्ट ही नहीं रहते हैं, बल्कि वे गरीब लोगों पर भी असर डालते हैं। मैं समझता हूं कि इस से बेहतर तो यह होगा कि सरकार के जो कार्य महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन को क्यों न बन्द कर दिया जाये। चाहे केन्द्र हो और चाहे स्टेट्स हों, मिनिस्टरों की इन लम्बी पल्टनों को क्यों न कम किया जाये? जिन गवर्नमेंट बाडीज़ का महत्व नहीं है, उन को खत्म कर दिया जाये। उदाहरण के लिये हम ने देखा है कि पहले प्रशासन में कमिशनरियां चलती थीं, लेकिन अब उनको खत्म करके कलेक्ट्रेट को उस के अधिकार दे दिये गये हैं। वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में डी० आई० जी और एस० पी की पावर्ज और क्वालिफिकेशन्ज़ बराबर होती हैं। तो क्यों न डी० आई० जी को खत्म कर के एस० पी को उस की पावर्स दे कर पैसा बचाया जाये?

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट का उल्लेख किया है। मैं मानता हूं कि १९६०-६१ और १९६१-६२ में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, लेकिन वर्तमान साल में उत्पादन के कम होने की आशंका है। उस का कारण यह है कि गवर्नमेंट खेती के विकास के लिये जो प्रयत्न कर

रही है और किसानों के हित के लिये जो कार्य कर रही है, उसका फायदा पूर्ण रूप से किसानो के पास नहीं पहुंचता है। इस सम्बन्ध में जो सरकारी पैसा लगाया जाता है, वह किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, वे गावों में जा कर किसानों को खेती के अधुनिक तरीकों से अवगत नहीं करते हैं। या तो वे लोग वास्तविक एक्सपर्ट्स नहीं है और या उनको समय नहीं मिलता है कि वे किसानों के पास जा कर सही ढंग से खेती करने की विधि उनको बतायें।

जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बताया है, इस साल के अंत तक सारे हिन्दुस्तान में कम से कम पांच करोड़ से भी अधिक विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कालेजिज़ से पढ़ कर निकलेंगे। यह बात सही है कि हम को शिक्षा के प्रसार की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और अशिक्षा, इल्लीट्रेसी, को खत्म करना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि जो ग्रेजुएट्स हमारे कालेजिज़ और यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं, उन को किसी भी प्रकार सर्विस नहीं मिल पाती है। इस लिये मेरा निवेदन है कि एजूकेशन के ज्यादा विकास के साथ साथ एजूकेशन सिस्टम में मूल रूप से परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। आज विद्यार्थियों की एम०ए० या बी०ए० की डिग्री प्राप्त कर के भी सर्विस के लिये दर दर भटकना पड़ता है। इस लिये शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर के विद्यार्थीयों को टेक्निकल शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिये, ताकि वे एम० ए० या बी० ए० पास करके अपने प्रोफेशन में लग जायें और उन को अपनी जीविका चलाने के लिये साधन मिल सकें।

अन्त में मैं आपका ध्यान गोल्ड कंट्रोल की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस के परिणामस्वरूप बहुत बेरोज़गारी या अनएम्पलायमेंट फैलेगी। जो लोग होशियार थे, वे तो पहले से ही सम्भल गये, लेकिन जो गरीब थे और जो इस बात को नहीं समझते थे, उन पर इस का असर पड़ेगा और वही बेकार हो जायेंगे। इसलिये इस में परिवर्तन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया।

**श्री रामसेवक यादव** (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ा और पाया कि वह अभिभाषण उत्साहवर्धक नहीं है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में समाजवादी व्यवस्था का हवाला दिया है। परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि "समाजवादी व्यवस्था" शब्द का प्रयोग एक फैशन सा बन गया है और वह जनता में एक तरह से बुद्धि-विभ्रम पैदा करने और उसको बहलाने का एक हथियार बन गया है। जहां तक समाजवादी व्यवस्था के इस अर्थ का सम्बन्ध है कि आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर किया जाये, उस दिशा में प्रगति नहीं के बराबर है। ज्यादा न कह कर फौज में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में जो बड़ा भारी फर्क है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं।

आज सिपाही को ६० रुपये, जमादार को १४५ रुपये, लेफ्टिनेंट को ५४० रूपये, कैप्टन को ६६० रुपये, मेजर को १३०० रुपये, लेफ्टिनेंट कर्नल को १५०० रुपये, कर्नल को १७३० रुपये और ब्रिगेडियर को १६५० रुपये वेतन मिलता है। मैं केवल वहीं तक जाता हूं। एक सिपाही को ६० रुपये और ब्रिगेडियर को १६५० रुपये, अगर सरकारी कर्मचारियों में और खास तौर से सिपाही और अफसरों के वेतन में इतना जबर्दस्त फर्क हो, तो हम इस को कौन सा समाजवाद कहें ? यह समाजवाद नहीं है।

जहां तक पंच-वर्षीय योजनाओं का प्रश्न है, राष्ट्रपति जी ने पंच-वर्षीय योजनाओं का हवाला दिया और कहा कि वे सफल हुई हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी पंच-वर्षीय योजनायें सफल नहीं हुईं, क्योंकि अगर वे सफल हुई होतीं, तो हम चीनियों से न पिटते। किसी भी देश में औद्योगिक तरक्की, कल-कारखाने और खेती का दुरुस्त होना लम्बी बांह के बराबर है और फौजी ताकत

[श्री रामसेवक यादव]

मुट्ठी के। अगर लम्बी बांह मजबूत और ताकतवर है, तो मुट्ठी बांधने में देर नहीं लगेगी, बड़ी ही जल्दी मुट्ठी बंध जायेगी और देश किसी भी संकट का समाना कर सकेगा। अगर हम उस दिशा में देखते हैं, तो सरकार स्वयं कहती है कि तैयारी कर के लड़ने में ज्यादा समय लगेगा। उस से पता चलता है कि पंच-वर्षीय योजनाओं के द्वारा कोई तरक्की नहीं हुई है और उन में भी हम को असफलता ही मिली है। अगर चीन और हिन्दुस्तान की औद्योगिक तरक्की के आंकड़ों को पेश किया जाये, तो पता चलता है कि जैसा कि माननीय सदस्य, श्री शिव नारायण ने कहा है—हम कछुए की चाल से चल रहे हैं।

इस सदन में कहा गया है कि हमारी तटस्थता की नीति बहुत बढ़िया है। हम ने बार बार कहा है और आज फिर कहना चाहते हैं कि अगर तटस्थता की नीति हो, तो अच्छा है, लेकिन वह है नहीं। हमारी आजादी के बाद दो चीन बने, एक तो कम्यूनिस्ट चीन और दूसरा फारमोसा का चीन। यद्यपि फारमोसा के वर्तमान शासक, च्यांग काई-शेक, ने हमारी आजादी की लड़ाई में हमारी मदद की थी, लेकिन हम उस एहसान को भूल गए और बड़ी निर्लज्जता के साथ यह कोशिश करते रहे कि कम्यूनिस्ट चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिया जाये और हम ने फारमोसा वाले चीन को मान्यता नहीं दी। लेकिन हमने एक बार भी नहीं कहा है कि कम्युनिस्ट चीन और फारमोसा चीन जो हैं, उन दोनों को स्थान मिलना चाहिये। सदस्यता मिलनी चाहिये। अगर सरकार ने नहीं कहा है तो मैं चाहता हूं कि वह इस चीज़ को कहे।

कम्युनिस्टों ने तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हम फलां देश से सहायता न लें क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जो तटस्थता की नीति है वह समाप्त हो जायेगी। सरकारी पक्ष की ओर से भी यही दुहाई दी जाती है। मैं निवेदन करता हूं कि जो देश कोलम्बों में एकत्र हुये थे, उनमें से दो प्रमुख देश हैं, इंडोनेशिया और मिश्र, उनकी ताकत कैसे बढ़ी चढ़ी है? दो हजार लड़ाकू वायुयान मिश्र के पास हैं, वे किस के दिये हुये हैं? रूस के ही तो वे दिये हुये हैं। छः अरब से अधिक की सैनिक सहायता इंडोनेशिया को रूस ही ने तो दी है। अगर ये देश रूसी सैनिक सहायता ले करके तटस्थ रह सकते हैं, बिन लगाव वाले रह सकते हैं, बिन लगाव वाले देश माने जा सकते हैं तो चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये, अपनी जमीन से उनको हटाने के लिये तथा अपनी भूमि को वापिस लेने के लिये और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये अगर हम किन्ही देशों से सहायता लेते हैं तो इससे कैसे तटस्थता की हमारी नीति पर आघात पहुंचता है, कैसे तटस्थता हमारी टूट जायेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया है। वैसे तो श्रीमान्, हमारी तटस्थता है भी नहीं।

जब हम चीनी आक्रमण की ओर तथा अपनी असफलताओं की ओर देखते हैं तो उस के बहुत से कारण हैं और यह भाषा वाला कारण भी कम बड़ा कारण नहीं है। चीन के अफसर, चीन की जनता, चीन के जवान सब चीनी भाषा बोलते हैं और हमारे अफसर, हमारे जवान और हमारे देश की सरकार की भाषा जो है, वह अंग्रेजी है जिसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारी फौज के अन्दर तरक्की किस आधार पर मिलती है? अफसर किस आधार पर बनाये जाते हैं? जो गिटपिट बोलें, छुरी कांटे से खाना खाना जानते हों, मेज़ के तर्ज तरीके जानते हों, यह जानते हों कि मेजों पर कैसे बैठा जाता है और क्लबों की जिन्दगी कैसे बिताई जाती है, उनको अफसर बनाया जाता है। यह है वह आधार जिस पर अफसरों की भरती की जाती है, जिस पर पलटनों में अफसर नियुक्त किये जाते हैं। कौन कितना बहादुर है, कौन कितनी कठिन जिन्दगी बिता सकता है, यह आधार आज नहीं है। जो आधार आपने बना रखे हैं, उनको आपको बदलना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारी पल्टनों में, हमारी मिलिटरी में अफसरों और सिपाहियों में कोई रिश्ता नहीं है। जब तक वह रिश्ता आप कायम नहीं करते हैं, जब

तक पलटनों को और अपनी फौज को नये ढंग से आप संगठित नहीं करते हैं, तब तक चीन जैसे राक्षसी देश का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं, उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। हमने संकटकालीन स्थिति की घोषणा की और कहा कि हम चीन का मुकाबला करेंगे। लेकिन हम कैसा मुकाबला कर रहे है? फूलों की प्रदर्शनियों का हम उद्घाटन कर रहे हैं। हमने संकटकालीन स्थिति के नाम पर उपचुनाव इत्यादि बन्द करा दिये थे, उनको दुबारा करा रहे हैं। सरकारी नौकरों की छुट्टियां इत्यादि बन्द कर दी थीं, वे फिर से जारी कर दी गई हैं। इस सब से यही पता चलता है कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। यह सब देख कर तो उस जानवर की कहानी की याद हो आती है जो रात में जब ठंडक पड़ी तो कहने लगा कि जैसे ही सुबह होगा, मकान तैयार करूंगा लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकला, धूप लगी, अपनी बात को भल गया और फिर उसी तरह से रहने लग गया। इसी तरह से चीन ने दो डंडे मारे तो जरा हम में तेजी आई, उसके बाद जब हम को तैयारी का मौका मिला तो लड़ाई बन्द हो गई और हम चुपचाप बैठ गये। यह स्थिति हमारी है। मैं नहीं समझता हूं कि तैयारी की दिशा में हम कुछ कर रहे हैं। आज भी वही भ्रष्टाचार है, वही फिजूलखर्ची है, वही दावतनामे हैं। सभी चीजें एक एक करके पहले की ही तरह चल रही हैं। हां एक चीज है, कि एमरजेंसी में विरोधियों को कैसे दबाया जाए। हमारे किशन पटनायक जी की बात आप जानते ही हैं। जरा कुछ कहा नहीं कि अन्दर कर दिया गया। राष्ट्र प्रेम का सवाल उठाया जाता है। हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम में हम किसी से कम नहीं हैं। हां एक बात है। अगर जबरदस्ती धन इकट्ठा किया जाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अगर यह कानून नहीं होता तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश से आवाज गूंजती इसके बारे में और अखबारों में भी यह चीज आती कि रक्षा कोष के लिये धन एकत्र करने में जबरदस्ती हो रही है। आज लोग डरते हैं। अगर वे कुछ कहें तो वे जानते हैं कि उनको जेल का दरवाजा दिखा दिया जाएगा। लोगों को मारा पीटा जा रहा है। हमारे बाराबंकी जिले से एक रिट पेटीशन पहुंच गई है अदालत में। जबर्दस्ती जो हो रही है उसके खिलाफ दरख्वास्तें दी गई हैं और उसकी जांच हो रही है। गोंडा जिले में भी यह हो रहा है। चूंकि भारत सुरक्षा अधिनियम है, इस वास्ते ये सारी चीजें सामने नहीं आ रही हैं।

भाषा का सवाल भी उठाया जाता है। इस प्रश्न से मेरी पार्टी का बहुत गहरा सम्बन्ध है। १९ तारीख के बाद से और शायद १८ तारीख ही से सोशलिस्टपार्टी के लोग इस सदन के और इस देश के दो सैंकड़ा अंग्रेजी अभिमुख बड़े लोगों के जो ९८ सैंकड़ा की छाती पर लदे हुए हैं, कोप का भाजन बने हुए हैं। हमारी निन्दा की जा रही है, हमें अशिष्ट बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें कहा जाता है कि ये लोग हिन्दी लादना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा बड़ा असत्य और गलत-बयानी दूसरी नहीं हो सकती है। सोशलिस्ट पार्टी हिन्दी लादना नहीं चाहती है। वह तो जनभाषाओं को प्रतिष्ठित करना चाहती है। इन जनभाषाओं में तमिल, तेलेगू, मराठी, बंगला, उड़िया इत्यादि सभी भाषायें आ जाती हैं और साथ ही साथ हिन्दी भी आ जाती है। कहीं हम ने नहीं कहा कि हम हिन्दी लादना चाहते हैं। हम तो इस हद तक जाते हैं कि अंग्रेजी न रहे और इस के बजाय कोई भी भाषा हो जाय। संविधान में कहा गया है, ३४३ से ले कर ३५१ संविधान के जो अनुच्छेद हैं उन में साफ साफ यह कहा गया है कि सन् १९५० से ले कर १९६५ तक अंग्रेजी निरन्तर घटती जायेगी, उस की जगह राष्ट्रभाषा हिन्दी लेती जायेगी और सन् १९६५ वह दिन होगा जब अंग्रेजी बिल्कुल मिट चुकी होगी। हम तो यह भी कहते हैं कि दक्षिण भारतीय या दूसरे जो हिन्दी नहीं समझते हैं, वे चाहें तो केन्द्र से अपना व्यवहार अंग्रेजी में कर सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि अपनी जनभाषाओं को वे अपने यहां प्रतिष्ठित करें। अगर उन को कोई भय है तो उनके लिए दस पंद्रह बरस के लिए केन्द्र में नौकरियां, गजेटिड नौकरियां सुरक्षित रखी जा सकती हैं या हमेशा के लिए सीटें सुरक्षित रखी जा सकती हैं या कोई अन्य सुझाव वे अगर पेश करना चाहते हैं तो सोशलिस्ट पार्टी उस को भी मानने के लिए तैयार है लेकिन शर्त इतनी ही है कि अंग्रेजी जाय। अंग्रेजी क्यों जाये, इस का

[श्री राम सेवक यादव]

कारण यह है कि अंग्रेजी के रहते हमारे देश का औद्योगीकरण नहीं हो सकता है, अच्छे टैक्नीशियंज़ पैदा नहीं हो सकते हैं, ज्यादा संख्या में डाक्टर पैदा नहीं हो सकते हैं। जब तक ये गिटपिट वाले दो सैंकड़ा लोग हैं, देश की जनता को जनतंत्र में अपना हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है और न ही हम चीनियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमें कहा जाता है कि हम हिन्दी फैनेटिक हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम सेठ गोविन्द दास जी की तरह से हिन्दी लादने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अंग्रेज़ी जाये, उस का स्थान कोई भी दूसरी भाषा ले। हम केवल हिन्दी के ही प्रेमी नहीं हैं, हम तो जितनी भी जनभाषायें हैं, उन सभी के प्रेमी हैं। हम अंग्रेजी के दुश्मन सिर्फ इसलिए हैं कि इस का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होना चाहिए। अगर कोई अंग्रेजी का ज्ञान हासिल करना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अंग्रेजी का प्रयोग अगर कोई अपने निजी काम के लिए करना चाहे तो वह वैसा कर सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में राज काज नहीं चलना चाहिए। हम यहां अंग्रेजों के ऊपर हुकूमत नहीं कर रहे हैं और न ही यहां की जनभाषा अंग्रेजी है। हमारे देश में दो फी सैकड़ा लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, बाकी ९८ फीसदी अंग्रेजी नहीं जानते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं ने अपने राष्ट्रपति जी से निवेदन किया था कि वह अंग्रेजी के सिवा किसी भी भाषा में अपना भाषण करें। मैं उन की बड़ी इज्ज़त करता हूं। मैं ने उनसे निवेदन किया था कि १९५० में राष्ट्रपति जी ने यह परम्परा डाली थी कि राष्ट्रभाषा में वह अपना अभिभाषण पढ़ें। हमारे राष्ट्रपति जी दस बारह साल उप-राष्ट्रपति रहे और संविधान की धारा ३५१ के अनुसार शपथ लेते रहे जिसमें यह कहा गया है कि बराबर इस बात का प्रयास किया जायेगा कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग अधिक से अधिक हो। लेकिन दुःख है कि हमारे राष्ट्रपति जी ने शपथ लेने के बावजूद भी अभिभाषण को राष्ट्रभाषा में नहीं पढ़ा। मैं ने तो उन से यहां तक निवेदन किया था कि अगर वह राष्ट्रभाषा में नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी भी प्रादेशिक भाषा में पढ़ें और प्रादेशिक भाषा उन की मातृभाषा ही हो सकती है। यहां तक भी जो मैं ने उनसे कहा था, इसको भी उन्होंने अनसुना कर दिया। मैं ने उन को हवाला दिया था कि प्रथम राष्ट्रपति ऐसा ही करते थे। मुझे उनका उत्तर मिला है, जिस को मैं आप की आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

†**तथा सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : क्या हम राष्ट्रपति द्वारा माननीय सदस्यों को भेजे गए पत्रों की चर्चा कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शिष्टाचार की दृष्टि से यह अधिक अच्छा हो कि माननीय सदस्य राष्ट्रपति से इसकी अनुमति ले लेवें।

**श्री राम सेवक यादव** : मैं सिर्फ पढ़ ही दूंगा और कुछ नहीं कहूंगा।

उन्हों ने लिखा है उसका संक्षेप यह है कि 'यह कहना गलत है कि सामान्य प्रथा यह है कि अभिभाषण पहिले हिन्दी में पढ़ा जाना था बाद में अंग्रेजी में। पहिले कुछ वर्षों में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण पहिले अंग्रेजी में पढ़ते थे बाद में हिन्दी में। यह केवल सुविधा का प्रश्न है। मैं पहिले भाषण को अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं। बाद में उपराष्ट्रपति उसे हिन्दी में पढ़ेंगे।

अब फिर मैं ने एक दूसरा पत्र लिखा जिसमें मैं ने निवेदन किया कि आप मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में पढ़ें। मुझे उसका यह उत्तर मिला जो संक्षेप में इस प्रकार है :

"यह सिद्धान्त की बात है कि अभिभाषण हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ा जाना चाहिये। तथापि इन का क्रम अपनी सुविधा का प्रश्न है . . . . ।

देश में लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए शिष्टाचार और सहिष्णुता अत्यन्त आवश्यक है . . . . "

यह बात सही है। उस दिन जिस बात के लिए हम लोगों की भर्त्सना की गई और कहा गया कि हम लोग बड़े डिसकर्टियस हैं और व्यवहार के अच्छे नहीं हैं, शिष्ट व्यवहार नहीं करते हैं, उन सभी लोगों के सामने, उन सभी सदस्यों के सामने हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे इस नाते ––

"गुलों से ख़ार अच्छे हैं, जो दामन थाम लेते हैं।"

मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं ने राष्ट्रपति जी का कोई अपमान या मानहानि नहीं की। मैं ने संविधान की ओर उन का ध्यान खींचा, उनसे निवेदन किया कि संविधान की परम्पराओं के यह विपरीत है। उन्होंने मेरा निवेदन नहीं सुना। मेरे पास इसके सिवा चारा ही क्या था कि या तो मैं सदन त्याग देता या उनकी बात सुनता। अगर हमारे मन की बात नहीं थी तो हमें अधिकार था कि हम सदन का त्याग कर दें। इस के अलावा मैं ने कोई काम नहीं किया। लेकिन उसको ले कर इतनी बातें हुईं। मुझे दुःख है इस बात का। यह गांधी जी का देश है, हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्रीय हमारी लोक सभा है। लोक सभा में मातृभाषा होनी चाहिए, लेकिन लोक सभा में हम विदेशी भाषा में कार्य चलाते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि वह भारत का बाप जो अपने लड़के को अंग्रेज़ी में तालीम देता है, मातृ भाषा में नहीं देता, वह उन बच्चों का दुश्मन है, अपना दुश्मन है और देश के दुश्मन है। आज उन भावनाओं से प्रेरित हो कर ही मुझे कहना पड़ता है कि अभी हमारी आजादी के पन्द्रह ही साल हुए हैं, उस से भी कम महामना राष्ट्रपिता के हमारे बीच में रहते हुए हुए। उस के थोड़े ही समय बाद हर कोई आदमी इस देश में हल्ला मचाता है कि जनतंत्र जनभाषा के बिना निष्प्राण है। जब तक जन भाषा नहीं होगी, हमारी पंचसाला योजनायें बेकार हैं, बिना उसके देश का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन जब हम उन्हीं भावनाओं को अपने भारतवर्ष में लागू करते हैं तो उसके लिए हमें कोसा जाता है, हमें दंडित करने की व्यवस्था की जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब रूस और अमरीका बैठे रहे थे तो ख्रुश्चेव ने मेज पर जूता पटका था। जूता पटकने का मैं हामी नहीं हूं, मैं उस की बुराई करता हूं, लेकिन किसी माई के लाल के मुंह में जबान नहीं थी, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के मुंह में जबान नहीं थी कि इस कार्य को बयान द्वारा ही बुरा कहा जाता। लेकिन यदि यहां हम कहें कि भारत में जन भाषा को प्रतिष्ठित होना चाहिये, और अंग्रेज़ी, जोकि २ फी सदी लोगों की बोली है, उसको मिटना चाहिये, तो मुझे उसके लिए सजा दी जाती है। किसी माननीय सदस्य को इस सदन की मर्यादा का, मान सम्मान का, ध्यान नहीं रहा। मैं राष्ट्रपति जी की बड़ी इज्ज़त करता हूं, राष्ट्रपति जी हैं, लोक सभा है, सारा देश है, मैं हूं, आप हैं, इस सारे हिन्दुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको संविधान के अन्तर्गत अधिकार मिले हुए हैं न? हमारे यहां संविधान सबसे बड़ा है। राष्ट्रपति को कहीं से यह अधिकार नहीं मिलता कि इस सदन में, जोकि स्वयम् अपना मालिक है, अपने काम को चलाने के लिए इस सदन के किसी सदस्य को दंडित करने के लिए किसी को इशारा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ने उस दिन की कार्रवाई को जब पढ़ा तो उस में पाया कि राष्ट्रपति जी ने आप को आदेश दिया कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाय, या कुछ कार्य किया जाय। यहां के किसी भी माननीय सदस्य . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** यह बात गलत है। कार्रवाई का यह मतलब था कि वहां उन को बोलने दिया जाता ताकि जो कार्रवाई हो वह वहां ठीक से चल सके। कार्रवाई जो है उसके आप गलत माने न लगायें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**श्री राम सेवक यादव :** "टेक ऐक्शन" के मैं यही अर्थ लगाता हूं, **आर डू समथिंग**।

**अध्यक्ष महोदय :** "टेक ऐक्शन" का मतलब था आप उनको बोलने देते। इसलिए मैं खड़ा हुआ कि आपसे कहूं कि आप उनको बोलने दीजिए। अगर उस वक्त आप इजाजत न देते, तो मालूम नहीं उस वक्त मेरे मन में क्या खयाल आता ताकि वह स्पीच कर सकें।

**श्री राम सेवक यादव :** खैर उस वक्त मैं ने यह निवेदन किया कि जो वर्तमान स्थिति है, मेरे उस कर्म पर, जिसे मैं उचित समझता हूं क्योंकि मैं ने संविधान की रक्षा की है, संविधान को तोड़ा नहीं है, संविधान की उन लोगों ने रक्षा नहीं की जिन्होंने बराबर १२ या १५ सालों से कसमें खाई हैं कि वे राष्ट्र भाषा का प्रचार करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे, लेकिन दस साल के बाद, पन्द्रह साल के बाद भी वह चीज़ नहीं हो सकी है . . . .

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** यह राष्ट्रपति पर आक्षेप है, क्योंकि वह कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने परम्परा का उल्लंघन किया।

**अध्यक्ष महोदय :** वह मेम्बर्स को कह रहे हैं। प्रेजिडेंट को नहीं।

**श्री राम सेवक यादव :** मैं प्रेजिडेंट के लिये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रेजिडेंट साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, इसलिए प्रेजिडेंट साहब का नाम न लिया जाय।

**श्री राम सेवक यादव :** मैं तो सरकार से, सरकारी दलों से, अपने मित्र मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि उन्होंने पिछले पन्द्रह सालों से बराबर संविधान की शपथ लेने के बावजूद उस की रक्षा नहीं की। मुझे तो यहां वह कहावत याद आती है कि "उल्टे चोर कोतवाले डाटे"। आज जिसने उसको उठाया आप उसे सजा दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा के लिये जो वर्तमान सजा हमें दी जायेगी उसे मैं स्वीकार करूंगा, इस आशा के साथ कि शायद भविष्य में हमें इस का कुछ इनाम भी मि मिले।

**श्री ब० सू० मूर्ति :** हम संविधान की रक्षा करने के लिये तैयार हैं, मगर आप प्रेजिडेंट साहब को बोलने देने के लिये तैयार नहीं हैं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनवाद) : राष्ट्रपति के भाषण में जनता की भावनाओं को पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ है। चीन के आक्रमण से देश पर आये संकट का हमें सही अनुमान लगाया है।

यह कहा जाता है कि हमारा देश इस आक्रमण का सामना करने को तैयार नहीं था। यह ठीक है। इसका कारण यह था कि हम देश के आर्थिक विकास के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयत्न कर रहे थे। हमने सैनिक आक्रमण के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया और यदि चीन हम पर विश्वासघात कर अचानक आक्रमण कर दे तो हमें अपने मानसिक और बौद्धिक दृष्टिकोण को बदलना होगा।

राष्ट्रपति ने ठीक कहा है कि हम सभी विवादों का निपटारा शांति से करेंगे तथापि यदि कोई शक्ति के बल पर हम पर अपनी इच्छा लादना चाहेगा तो हम उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने जिनमें से अधिकांश कोयला खानों के मजदूर हैं उन्होंने अपनी तुच्छ आय में से भी नवम्बर में ५ दिनों का वेतन तथा दिसम्बर व जनवरी में दो दो दिनों का वेतन दिया तथापि मैंने उन्हें राय दी कि इसके साथ उन्हें उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। वस्तुतः युद्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

जीतने के प्रयत्न केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं अपितु खेतों और कारखानों में भी किये जा रहे हैं जिसके लिये जनता भरसक प्रयत्न कर रही है ।

जहां तक प्रतिरक्षा नियमों के अधीन हिरासत में लिये गये व्यक्तियों का संबंध है मुझे यह जान कर हर्ष हुआ है कि इस संबंध में उतनी गिरफ्तारियां नहीं की जा रहीं है जितनी कि स्वतंत्रता के पूर्व की जाती थी । सारे भारत में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की जो संख्या दी गई है वह केवल ७५८ है इसे अधिक नहीं कहा जा सकता है ।

हमें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग विरोधी पक्ष को समाप्त करने के लिए किया जायेगा । किन्तु विरोधी पक्ष को समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । प्रश्न तो यह है कि राष्ट्रीय शक्ति को इस भयंकर आक्रमण का सामना करने के लिये तैयार किया जाये ।

तटस्थता की नीति की भी आलोचना की गई है । एक पड़ौसी राष्ट्र के द्वारा आक्रमण किये जाने पर हम अपने देश के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिये लड़ सकते हैं । तटस्थता की नीति हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकती ।

यह शक्ति के गुट या सैनिक गठबन्धनों का प्रश्न नहीं है यह एक दूसरे पर आक्रमण करने के विषय में सोचने का भी प्रश्न नहीं है भारत के अपने निज के सिद्धान्त हैं । यहां तक कि साम्यवादी भी दूसरे साम्यवादी राष्ट्र चीन द्वारा किये गये इस आक्रमण की निन्दा करते हैं । इससे यह अर्थ निकलता है कि वह इस आक्रामक अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी दृष्टिकोण का नहीं अपितु भारतीय संस्कृत का समर्थन करते हैं । तटस्थता के इस प्रश्न का गलत अर्थ निकाला जा रहा है । किसी गुट के साथ गठबन्धन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । प्रश्न यह है कि हम उतनी शक्ति पैदा कर लें जिससे हम हर प्रकार के आक्रमण का सामना करने में समर्थ हो सकें ।

लन्दन के "इकोनोमिस्ट" ने इस आक्रमण के विषय में आलोचना करते हुये लिखा है भारत की प्रतिरक्षा इसलिए कमजोर रही कि उसने आर्थिक प्रगति को प्रतिरक्षा से अधिक महत्त्व दिया । यह अभी कहना असम्भव है कि क्या इस संकट की गंभीरता कुछ रूकावटों को दूर करके नई गति दे सकेगी ।

इससे यह पता चलता है कि यह विदेशी पत्र भारत की कठिनाइयों को समझ रहा है । वास्तव में प्रगति के मार्ग में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । किन्तु इन कठिनाइयों ने जनता में दृढ़ शक्ति उत्पन्न कर दी है जो हमें प्रगति और विकास के मार्ग पर ले जा रही है । किन्तु हमें सावधानी के साथ उस समस्या को समझना होगा और उसका हल ढूंढ़ना होगा । इसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर ही है कि इस वर्तमान संकट में हम सारी रूकावटों को दूर कर सकें । यहां पर वास्तविक एकता का प्रश्न उत्पन्न होता है । यदि हमें प्रगति की गति को बढ़ाना है तो यह केवल जनता के सम्मिलित प्रयत्न से ही हो सकेगा ।

**श्री यशपाल सिंह** (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, कई दिन से मैं बहस सुन रहा हूं और १०० फीसदी कांग्रेसियो के मुंह से जो बातें मैंने सुनी हैं, उन्हीं का जवाब देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । सब लोगों ने यह कहा है कि अपोजीशन की तरफ से, जों काम और अच्छे काम कांग्रेसी सरकार ने किये हैं, उनकी तारीफ नहीं की गई । हर एक ने यह कहा है कि जो काम ऐडमाइरेबुल है, प्रशंनीय है उनके लिये हमारा गुणगान नहीं किया गया है । इस के लिये मेरी अर्ज यह है कि अपोजीशन का काम क्रिटिसाइज करना है, गुणगान करना नहीं है । अगर सरकार ने १० मील लम्बी सड़क बनाई है तो उस की तारीफ करना हमारा काम नहीं है । अलबत्ता जो बीच में एक मील सड़क टूटी हुई है उसको क्रिटिसाइज करना हमारा काम है । डाक्टर का काम औपरेशन करने का है । जहां जख्म पक गया है वहां नश्तर लगाकर चीरने का है । जहां से जिस्म तंदरुस्त है, वहां पर मालिश करने का काम किसी खिदमतगार का काम है, डाक्टर का काम नहीं है । हम लोग यहां पर क्रिटिसाइज करने के लिये आए हैं । बार बार यह कहा जाता है कि

[श्री यशपाल सिंह]

हमारी तरफ से कोई आल्टरनेटिव कोई आल्टरनेट सजेस्टियन या कोई कन्क्रीट सजेस्टियन नहीं दिया गया है। इसके लिए एक ही सजैशन है। जिस तरह से रूहानियत के बिना खुदा नहीं मिलता है, आध्यात्मिकता के वगैर परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, जिस तरह से भजन के वगैर बन्दगी नहीं होती है, ठीक उसी तरह युद्ध के बिना देश की रक्षा नहीं हो सकती है। इस समय कोई आल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। इस समय केवल एक ही रास्ता है—युद्ध का। अगर हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो देश की इज्जत की रक्षा नहीं हो सकती है। आज देश को युद्ध के लिये तैयार करना पड़ेगा। आज कोलम्बो-प्रस्तावों और आर बिट्रेशन वगैरह की जो बातें बनाई जाती हैं, वे सिर्फ इस लिये कही जाती है कि हमारे हलवे-मांडे और रंगीनियों में कमी न आए। उसमें देश की रक्षा का कोई सवाल नहीं है। आज हमारा देश उस परिस्थिति में से गुजर रहा है, आज हमारे देश के सामने वह नजारा है, आज हम उस काल में से गुजर रहे है, जिसके बारे में हिटलर ने, अपनी आटोवाइग्राफी में लिखा है :—

"उस समय तलवार हल का काम देगी और युद्ध में गिरे हुये आंसू आने वाली पीढ़ी के लिये भोजन तैयार करेगी ।"

आज वह वक्त आ गया है कि हिन्दुस्तान के बच्चे बच्चे को फौज के लिये तैयार किया जाये। कांग्रेस सरकार नाकाबिल साबित हुई है। वह सिर्फ बातों से इस मसले को हल करना चाहती है। देश में कोई ऐसा एटमास्फीयर तैयार नहीं किया गया है, जिस से देश युद्ध के लिये तैयार हो सके, लड़ाई के लिये तैयार हो सके।

आज ऐसी बातें कहीं जाती है कि लड़ाई लम्बी चलेगी। लम्बी लड़ाई क्यों चलेगी? क्या हिन्दुस्तान में ४४ करोड़ गधे रहते है, क्या हिन्दुस्तान में ४४ करोड़ नपुसंक रहते हैं, क्या हिन्दुस्तान में ४४ करोड़ कुत्ते रहते हैं कि लम्बी लड़ाई चलेगी? यह महाराणा प्रताप और गुरू गोविन्द सिंह की औलाद है। यह भगवान कृष्ण और अकबर की औलाद है। यह भगवान राम की औलाद है लम्बी लड़ाई का कुछ मतलब नहीं है। लड़ाई की साइकालीजी और स्ट्रैटेजी यह है : "आई केम, आई सा, आई कांकर्ड"।

जब सरकारी बेंचिज की तरफ से कहा जाता है कि लड़ाई लम्बी चलेगी, तो ब्लेक-मार्केटियर यह सोच लेता है कि बहती गंगा है, हाथ धो लो, जितना ब्लैक-मार्केटिंग कर सकते हो, उतना कर लो, मोटर का जो पुर्जा एक रुपये में बिकता था, उसको १५० रुपये में बेच लो" ऐसी बातें केह कर ब्लैक-मार्केटियर्ज को बढ़ावा दिया जाता है।

इन पन्द्रह सालों में देश को यह तालीम और ट्रेनिंग दी गई है कि अगर एक हाईड्रोजन बम गिर गया, तो करोड़ों आदमी नष्ट हो जायेंगे और अगर एक एटामिक बम गिर गया तो पचास लाख आदमी नष्ट हो जायेंगे। यह ट्रेनिंग और यह शिक्षा गलत थी। हमें तो इस ट्रेनिंग की जरूरत थी कि "सम्भावितस्यचाकीर्तिः मरणावतिरिच्यते"। हमें उस शिक्षा की जरूरत थी, जिसमें यह पढ़ाया जाता कि जिल्लत की जिन्दगी से मौत अच्छी होती है, अपमान के जीवन से मृत्यु बेहतर होती है। वह ट्रेनिंग हमें नहीं दी गई। हमें डर दिखाया गया और जो आज भी डर दिखाते है, जो आज भी इन्फ़ीरियारिटी कम्पलेक्स की बात कहते है, जो आज भी हीनता की बात कहते हैं, वे देश की सेवा नहीं कर रहे हैं।

इस माननीय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने २२ जनवरी को हमारे प्रधान मंत्री ने क्वश्चन आवर में यह ऐलान किया कि वाकई हमारे पास इतनी राइफ़लें नहीं हैं, जिन से हम एन० सी० सी० की ट्रेनिंग कालेजों को दे सकें। जिस देश के पास स्कूलों और कालेजों में ट्रेनिंग देने के लिये राइफ़लें नहीं हैं, क्या वह देश लद्दाख के मोर्चे पर राइफलें भेज सकता है? अगर सरकार की कोई कमजोरी, वीकनेस या कमी हैं, अगर वह कहीं लूज करती हैं,

तो इसका मतलब यह नहीं हैं कि इस का ढिंढोरा पीटा जाये, क्योंकि ढिंढोरा पीटने से दुश्मन और ज्यादा हम पर हावी होता है ।

सरकार की ओर से यह कहा गया है कि हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे । बिल्कुल ठीक है । जो लड़ाई के लिए तैयार होता है, उस पर कोई हमला नहीं होता है । जो लड़ाई के लिए तैयार हो, क्या उस पर हमला कर के कोई अपना सिर तुड़वायेगा या अपनी मौत बुलवायेगा ? यह सरकार तो दुश्मन को आह्वान देती हैं, दावत देती है और उसको यह कहती है कि "वाकई हम लोग लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, आओ, तुम्हारे लिए मैदान खाली है" ।

आज दो ही रास्ते हैं । चाहे कोलम्बो प्रस्ताव हो, चाहे नेगोशिएशन्ज हों, चाहे ८ सितम्बर की स्थिति की बात हो, यह ज़िल्लत, शिकस्त और पराजय का रास्ता है । देश की इज्जत की रक्षा केवल दूसरे ही रास्ते से हो सकती है और वह रास्ता है युद्ध का । कांग्रेस सरकार को इस देश ने वह सम्मान, इज्ज़त, आनर और एज़ाज़ दिया, जो किसी शहन्शाह को भी नहीं मिल सका । और कांग्रेस सरकार ने उस सम्मान के एवज़ इस देश के ४४ करोड़ इंसानों को पराजय का कंलक दिया, शिकस्त का दाग़ दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि चाइना ने तो सीज़फायर किया है, हम ने क्या किया है । अगर हम में मिलिटरी स्ट्रेंग्थ और शक्ति होती, अगर हम में बल-वीर्य होता, तो क्या हम कासा-ए-गदाई ले कर, भिक्षा-पात्र ले कर, चाइना के सामने खड़े होते कि हमारे कैदी, हमारे ज़ख्मी और बीमार और हमारी लाशें वापस दे दो ? अगर हम में क्षात्र-तेज होता, अगर हमारी बांहों में बल होता, अगर हममें मिलिटरी स्ट्रेंग्थ होती, अगर हम में बल-वीर्य होता, तो हम एक कैदी के एवज़ एक लाख कैदी बनाते, एक ज़ख्मी के एवज़ एक लाख को ज़ख्मी करते, एक लाश के एवज़ एक लाख लाशें बिछा देते। यह हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी को यह देश बर्दास्त नहीं कर सकता है । आज ४४ करोड़ इन्सानों की आंखें खुली हुई हैं । आज ४४ करोड़ इन्सान इस ज़िल्लत को बर्दास्त नहीं कर सकते हैं ।

अगर यह सरकार इस देश की इज्ज़त की रक्षा नहीं कर सकती है, तो उस की तारीफ़ इसी में है कि वह पद छोड़ दे । बार-बार कहा जाता है और अभी माननीय सदस्य, श्री शिवनारायण, ने कहा कि अगर मेरे हाथमें डिफ़ेंस आफ़ इंडिया रुल्ज़ का संचालन होता, तो मैं एक एक स्वतंत्र पार्टी के सदस्य और जनसंघी को जेल में डाल कर छोड़ता । ये हम को जेल से डराते हैं ? हम जेल में पैदा हुए। मैं तेरह साल की उम्र में काल-कोठरी में रहा हूं । हम ने आठ सौ साल तक दरख्तों की छाल चबा कर इस देश की रक्षा की है । हम ने आठ सौ साल तक खून के दरयाओं में नहा कर इस देश की रक्षा की है । हम ने कंकड़ों और पत्थरों के ढेर पर सो कर इस देश की रक्षा की है । इस के बावजूद आज हम को डराया जाता है कि हम को जेल में डाल दिया जायेगा । ये खिलौने हैं, जो हमें जलों से डराते हैं । हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं । हम कहते हैं कि हम ने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, खून दिया है, मुसीबतें उठाई हैं । मैं पंडित चन्द्रशेखर शर्मा "आज़ाद" के साथ जंगलों में मारा मारा फिरा मैं भाई भगतसिंह के साथ फांसी की कोठरी में रहा । हम ने इस देश के लिए मुसीबतें उठाई हैं । हमें इस देश का दर्द है ।

"जिसे है फ़िक्र मरहम की, उसे दुश्मन समझते हैं,

इलाही खैर हो, यह ज़ख्म अच्छा हो नहीं सकता" ।

हम इस सरकार के खैर-ख्वाह हैं और हम उस को नेक रास्ता दिखाना चाहते हैं । भारतमाता गवर्नमेंट से बड़ी है और हमारे देश की इज्ज़त सरकार से बड़ी है । अगर यह सरकार देश की रक्षा नहीं कर

[श्री यशपाल सिंह]

सकती है, तो वह हट जाये। यह तो एक थोथी दलील है कि मैजारिटी बना लो और हमें हटा दो। मैं साफ कहना चाहता हूं कि उसकी महिमा इसमें है कि वह अपने पद छोड़ दे। वह ना-एहल है। इस सरकार की कैबिनेट के एक मेम्बर ने ही संसार के सामने एक आदर्श पश किया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री की कोई ख़ता नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि मेरे जमाने में ज्यादा एक्सिडेंटस हुए हैं, इसलिए मैं मुस्ताफी होता हूं। यह सरकार उस आदर्श के अनुसार चले और चूंकि वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकी है, इसलिए ईमानदारी और देशभक्ति का तकाज़ा यह है कि वह अपने पद छोड़ दे। यह दलील ठीक नहीं है कि मैजारिटी बना कर हमको हटा दो। जिस दिन हमारी मैजारिटी बनेगी, उस दिन बाकायदा जबाब-तलब किया जायेगा कि किस से पूछ कर देश के नौजवानों को भट्टी में झौंक दिया गया था, जब कोई शक्ति नहीं थी। उस दिन पूछा जायगा कि किस से पूछ कर आठसाल तक हमारी फ़ौजों को यह हुक्म दिया गया था कि जब चीनी गोली चलायें, तो उस के बाद ही गोली चलाओ। दुश्मन हमारे घर में घुसा बैठा है, दुश्मन हमारे इस पालियामेंट हाउस में घुसा बैठा है, लेकिन मैं अपने पहरेदारों को यह हुक्म दे दू कि जब दुश्मन गोली चलाए उस के बाद गोली चलाओ!

जिन के मरे नहीं हैं, वे कहते हैं कि बातों से मसला हल करो। जिनका खून नहीं बहा है, वे कहते हैं कि कोलम्बो-प्रस्तावों से मसला हल करो। हमारे मरे हैं। मेरा सगा भतीजा मारा गया। मेरे बटे, विक्रमसिंह, के चीनियों ने कुल्हाड़ियों से तीन टुकड़े कर के उसका खून पीया। मैंने वहां जाकर देखा। मैंने वहां का मुआयना किया। खून पीते वक्त उन्होंने यह कहा कि वैसे तो हर एक हिन्दुस्तानी बदमाश है, लेकिन तीन का खून हमें मीठा लगता है—सिख, जाट और राजपूत, इन तीनों का खून हम को मीठा लगता है। हमारे खून को चीनी की तरह से मीठा समझ कर पीया गया है। क्या हम उनको माफ़ कर देंगे? आज देश की आत्मा और देश की खुददारी जाग चुकी है। आज देश में आत्म-सम्मान है। जिन देशों में आत्म-सम्मान है, वे कभी कोलम्बो-प्रस्तावों की बात नहीं कर सकते।

आज चाइना ने कह दिया है कि कोलम्बो-प्रस्तावों का यह टोकरा सड़ा हुआ है, इसमें कीड़े पड़ चुके हैं, यह बेकार हो चुका है और अगर इस को चीन की सरजमीन पर रखा जायगा, तो चीन में एक बीमारी, एक कानटेजियस डिज़ीज़, एक एपिडेमिक फैल जायगा। चीन ने उस टोकरे को लात मार दी है। हमारा भी यह फ़र्ज है, हमारी देशभक्ति और सिन्सेरिटी का भी यह तकाज़ा है कि हम लोग भी उसे छोड़ दें और अपने देश को, अपनी फ़ौज को लड़ाई के लिए तैयार करें।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को मैंने सुना और फिर कई दफ़ा उस को पढ़ा। मेरी समझ में नहीं आया कि देश में क्या निर्माण हुआ है। तीन मुख्य निर्माण-कार्य ये हैं, चरित्र का निर्माण, अपनी आवश्यकता की खुराक का देश में ही पैदा होना और फ़ौजी ताकत पैदा करना। इन तीनों के मामले में हम निहत्थे और बेकार खड़े हैं। हम दूसरे मुल्कों से २६ अरब रुपये का गेहूं ले कर खा चुके हैं। हम आज भी दूसरे मुल्कों के सामने हाथ पसारते हैं। आज भी हम दूसरे मुल्कों के मौहताज हैं।

जहांतक चरित्र का प्रश्न है, आज हालत यह है कि इस कैपीटल में एक एक दिनमें सैंतीस सैंतीस अग़वा होते हैं। माननीय मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री, सच बोलने वाले हैं। उन्होंने पालियामेंट में यह माना है कि वाकई जरायम में इज़ाफ़ा हुआ है, वाकई अपराध दिन-रात बढ़ते जा रहे हैं। आज दिल्ली की सडकों और चौराहों पर वे नग्न चित्र लगे हुए हैं, जिन के ख़िलाफ़ महात्मा गांधी ने जिन्दगी भर जद्दो-ज़हद की थी। आज दिल्ली की सड़कों और चौराहों पर यह लिखा हुआ है, "४४ करोड़ लोगों के दिलों पर शासन करने वाली सुरैया," "४४ करोड़ लोगों के दिलों पर शासन करने वाली मधुवाला"। इसका मतलब यह है कि ४४ करोड़ ज़ानी हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं? कहां

हैं हमारी हाई कोर्टस, कहां है हमारी सुप्रीम कोर्ट, कहां है हमारा मौरेल, कहां है हमारा डिसिप्लिन, कहां है हमारी सरकार ? जिन लोगों ने यह लिखा कि ४४ करोड़ लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाली सुरैया, उनके हाथ कटवा दिये जाने....

**अध्यक्ष महोदय** : ४४ करोड़ के अलावा भी कुछ आदमी हैं ।

**श्री यशपाल सिंह**: वाकई में और भी ज्यादा हैं । अगर देश का चरित्र होता तो इस बात की इजाजत न दी जाती है कि कोई कहीं भी किसी तरह से भी लाउड स्पीकर लगा कर के, माइक के ऊपर खड़ा हो कर के....

**श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना)** : प्वाइंट आफ आर्डर, सर....

**श्री यशपाल सिंह** : मुझे बड़ी कोशिशों के बाद थोड़ा सा समय मिला है और मुझे अपनी स्पीच जारी रखने दीजिये । जब आप बोलें तो अपनी बात कह सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं क्या करूं, वह प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं ।

**श्री यशपाल सिंह** : मैं यह निवेदन...

**अध्यक्ष महोदय** : उनका प्वाइंट आफ आर्डर तो सुन लीजिए ।

**श्री रा० शि० पाण्डेय** : अध्यक्ष महोदय, मधुबाला और सुरैया, कलाकार हैं और चित्रों में अभिनय करती हैं । उनके नाम से तथा उन के साथ व्यभिचार का सम्बंध जोड़ा जाये, यह प्रतिष्ठा के अनुकूल बात मालूम नहीं देती है ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन का कहने का मतलब यह है कि जो इश्तहार लगते हैं उन में लिखा रहता है कि ४४ करोड़ पर वे राज करती हैं । उन पर वे राज नहीं करती हैं । वे कहते हैं कि हम कहां से शामिल हो गये ? लेकिन आबादी ४४ करोड़ से ज्यादा है और वे उस में आ जाते हैं ।

**श्री यशपाल सिंह** : हम उन में शामिल नहीं हैं....

**अध्यक्ष महोदय** : आप उन में आ जायेंगे, जो बाकी लोग हैं ।

**श्री यशपाल सिंह** : देश का चरित्र सब से पहली चीज है । मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर देश का चरित्र होता तो देश में कानून बनाये जाते । कोई कहीं सिग्रेट का धुआं फेंक दे, कोई कहीं बैठ कर शराब पीना शुरु कर दे, कोई कहीं बदबू फैलाता रहे, कोई कहीं माइक लगा कर कुलटाओं के गाने गाना शुरु कर दे, चाहे बच्चों के इम्तहान हो रहे हों, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा हो या पूजा पाठ कर रहा हो और चाहे डाक्टर आपरेशन कर रहा हो, कोई रोक टोक नहीं है । बेवाओं के राज में भी थोड़ी बहुत रोकटोक हो जाती है । विधवा रुल में भी कुछ मारेल रैस्ट्रिक्शंज होती हैं । विडो राज में भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं मारल स्टेंडर्ड होता है । लेकिन कांग्रेसी राज में कोई मारेल स्टेंडर्ड नहीं है । अगर देश को तैयार करना है, तो शराब को बंद किया जाय, अगर देश को तैयार करना तो सिनेमा घरों के अन्दर जो बुरे बुरे गाने गाये जाते हैं, इनको बन्द किया जाए और सिनेमा घरों को बन्द कर के इन जगहों पर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल खोले जायें और लोगों को फौजी तालीम दी जाए । अगर ऐसा किया जाता है, तो आप देश की रक्षा कर सकते हैं, वर्ना नहीं कर सकते हैं ।

[श्री यशपाल सिंह]

बार बार यह कहा जाता है कि स्वतंत्र पार्टी जमीदारों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, राजा महाराजाओं की पार्टी है। मैं कहता हूं कि एक दो राजा महाराजाओं के आने से हमारी पार्टी अमीरों की हो गई, लेकिन कांग्रेस में पाच दर्जन राजे महाराजे हैं, क्या वह राजा महाराजाओं या अमीरों की पार्टी नहीं हुई। हमारी पार्टी में तो दो राजे महाराजे हैं लेकिन कांग्रस में पूरे पांच दर्जन हैं। किस तरह से हमारी पार्टी अमीरों की हो गई, समझ में नहीं आता है। कहा जाता है कि हम जमीदार हम जब थे तब थे, आज नहीं हैं, आज तो हम काश्तकार हैं। उधर से बार बार मेरी पगडी का जिक्र किया जाता है। मैं साफ कहता हूं कि इस पगड़ी के साथ हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है। यह जमीदारों की पगड़ी नहीं है, यह इण्डियन कल्चर की पगड़ी है। मुझे इतिहास की वह बात याद आती है कि जब महाराणा प्रताप का भाट अकबर के दरबार में गया था और जब सलामी दी पगड़ी उतार कर सलामी दी तो इस पर राजा अकबर ने कहा कि यह दरबार की तौहीन है तो उस ने जबाब दिया कि सिर मेरा आप के कदमों में झुक सकता है लेकिन पगड़ी महाराणा प्रताप की है यह किसी के कदमों में नहीं झुकती है, सिर्फ भगवान के सामने झुकती है। हम लोगों को जमींदार कह कर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं आज भी डंके की चोट कहता हूं कि हम में ऐसे आदमी हैं जिन्होंने बीस बीस हजार एकड़ जमीन हरिजनों और मजदूरों में तक्सीम की है। आज भी हम में ऐसे लोग हैं जो तन मन धन से हरिजनों और मजदूरों की सेवा में लगे हुए हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि हम देश को एक सूत्र में पिरोयें। पार्टीबाजी की बिना पर हम को बार बार कहा जाता है कि कोई चर्चिल नहीं है तो चैम्बरलेन राज कर रहा है। यह सरकार की खता है। सरकार ने किसी पार्टी को पनपने नहीं दिया है, सरकार ने अपोजीशन को पनपने नहीं दिया है। दूसरे मुल्कों में अपोजीशन लीडर की वही इज्जत होती है जो प्राइम मिनिस्टर की होती है। लेकिन हमारे देश की यह हालत है कि आज भी मुखालिफ पार्टी के लोगों के लैक्चरों को सी०आई०डी० वाले नोट करते हैं। हम डरते नहीं हैं सी० आई० डी० से। लेकिन नाक इनकी कटती है, शर्म हम को आती है। हजू होती है जनतंत्र की, लज्जा के मारे हम लोग मरते हैं। ४४ करोड़ इंसानों को एक सूत्र में पिरोकर हम हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा कर सकते हैं। न कोलम्बो प्रस्तावों की तरफ देख कर और न ही मिलिटरी एड की तरफ देख कर हम हिन्दुस्तान की रक्षा कर सकते हैं। हम अमरीका के भिखारी नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिये। मैं नान-एलाइनमेंट को मानता हूं। लेकिन नान-एलाइनमेंट पहाड़ की होती है, चट्टान की होती है, तिनके की कोई नान-एलाइनमेंट नहीं होती है। आप फौजी ताकत पैदा करें। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। ४४ करोड़ इंसानों को एक पूत्र में पिरो कर तथा फौजी ताकत पैदा करके ही हम देश की रक्षा कर सकते हैं। हम सब को सिपाही बन कर देश की रक्षा करनी है और तभी देश की रक्षा हो सकती है।

मैं मजबूर हूं कि मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता हूं।

**श्री कुं० कृ० वर्मा** (सुल्तानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज कई रोज़ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर वाद-विवाद यहां पर चल रहा है। जो अभिभाषण माननीय राष्ट्रपति जी ने दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और उन्हें उसके लिए मैं धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विरोधी पार्टियों की ओर से कई आक्षेप सरकार की नीतियों पर, सरकार की कारगुजारियों पर किए गए हैं। यह आक्षेप भी किया गया है कि सरकार सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है, कम्पलेसेंट है और उसकी नीतियां ठीक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एमरजेंसी में जो बातें होनी चाहियें वे कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती हैं और सभी लोग ढीले ढाले हैं, सोये हुए हैं और कोई कार्य इस सम्बन्ध में नहीं हो रहा है। माननीय सदन की यहां पर बैठक बुलाई गई है और माननीय राष्ट्रपति जी ने कई बातों की ओर संकेत किया है जिस में युद्ध के बारे में भी काफी जिक्र है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे राष्ट्र में जो कुछ भी सत्कार्य होने हैं वे इसी दृष्टिकोण से होने हैं कि युद्ध की तैयारी हम करें और हमें अपने शत्रुओं को अपनी भूमि से हटाना है। ये सभी चीजें होते हुए भी मैं नहीं समझता हूं कि अगर एमरजेंसी पीरियड है, अगर यहां पर संकटकालीन परिस्थिति है तो जो विषय कि इस माननीय सदन में कई बार हो चुके हैं, जिन पर कई बार डिसकशन हो चुका है प्रस्ताव पास हो चुके हैं चाहे बहुमत से और चाहे सर्वसम्मति से, तो फिर उन्हें ही, उन्हीं बातों को छेड़ना, उन्हीं बातों पर वाद-विवाद करना यह क्या एमरजेंसी दिखलाता है। क्या यह चीज नहीं जाहिर करती है कि इस माननीय सदन का और सार्वजनिक समय का नाश किया जा रहा है उस प्रस्ताव पर बार-बार वादविवाद करके जिस पर कि यह माननीय सदन बहस कर चुका है।

जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध हैं, चाहे समय हो या न हो, वे कोई न कोई आक्षेप जरूर करना चाहते हैं, कोई न कोई चुटकी जरूर लेना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक चीज का समय होता है। अगर उनकी पार्टी ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिस में उन्होंने चीनी आक्रमण का विरोध किया है, चीन की निन्दा की है और अपील की है कि हमारा देश और सभी लोग मिल करके इस आक्रमण का मुकाबला करें और जो दूसरे कम्युनिस्ट देश हैं वे भी भारतवर्ष का साथ दें तो फिर उस सिलसिले में यह कहना कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए, इस पार्टी को अवैधानिक घोषित कर दिया जाए, मैं नहीं समझता कि इसका कौनसा मौका है। अगर कोई प्रस्ताव नेकनीयत से पास नहीं करता है, अगर उसके विरुद्ध कुछ व्यक्ति या सदस्य काम करते हैं तो उनके खिलाफ जो इस वक्त डिफेंस आफ इंडिया रूल्स हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। हमने देखा है कि कुछ को जेल भेजा गया है।

हम इस समय चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि हमारे देश का उत्पादन बढ़े। हम सुरक्षा के लिये जितने भी प्रयत्न कर सकें उतने करें। इस सिलसिले में यहां कम्यूनिटी डवलपमेंट के मंत्रालय ने एक स्कीम तैयार की, जिस में हर पार्टी के सदस्यगण, जो उस कमेटी के सदस्य थे, बुलाये गये, और सब की सहमति से वह चीज तैयार हुई। उस में श्रम बैंक की व्यवस्था की गई कि हर गांव सभा में जितने लोग काम कर सकते हैं वह एक दिन का श्रम हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिये दें। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि हमारे रंगा साहब ने उस का भी विरोध किया, जब कि उन की पार्टी के सदस्य भी उस में थे और उससे सहमत थे। मैं नहीं समझता कि इस में कौन सी खराबी की चीज है कि लोग श्रम कर के उत्पादन को बढ़ावें। लेकिन चूंकि सरकार ने उस को अपना लिया है, वह स्कीम चालू है, उस की व्यवस्था हो रही है, इस लिये उस का विरोध करना चाहिये, मैं नहीं समझता कि किस तरह से कहा जायेगा कि उन्होंने इमर्जेन्सी के अनुकूल यह बात कही।

दूसरी बात यह कि नानअलाइनमेंट की पालिसी हमारी बहुत अर्से से है और उस का माननीय सदन ने कितनी ही बार समर्थन किया है। इस माननीय सदन में वह चीज पास हुई है। हम ने कितनी बार इस चीज को समझाया कि अगर हम किसी गुट में जा कर शामिल

[श्री कु० कृ० वर्मा—जारी]

हो जाते हैं, उस में विलीन हो जाते हैं, तो दूसरे जो ब्लाक हैं हम खामख्वाह उन से शत्रुता मोल लेते हैं, और यह कोई बुद्धिमानी की चीज नहीं है। यह चीज बुद्धि से परे है। उस का समर्थन काफी हुआ। बहुत से राष्ट्र जो कि एक गुट बनाये हुए हैं स्वयम् अब हमारी इस नानअलाइनमेंट की नीति की प्रशंसा करते हैं। वे इस से सहमत हैं। वह साफ इस बात को कहते हैं कि हम यह नहीं चाहते कि भारतवर्ष अपनी इस नीति को बदले। लेकिन स्वतन्त्र पार्टी चाहती है कि नहीं, इस नीति का त्याग कर दिया जाय, यह नीति बदल दी जाय और हम पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में शामिल हो जायें। मैं समझता हूं कि यह तो वही बात हुई जैसी की मसल कही जाती है कि "मुद्दई सुस्त गवहा चुस्त"। एक तरफ तो दुनिया के जितने राष्ट्र हैं उन में से सभी लोग इस की प्रशंसा करते हैं और इस से सहमत हैं, दूसरी तरफ़ हमारे यहां स्वतन्त्र पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम एक गुट में विलीन हो जायें। इस के माने क्या हैं? इस के माने साफ यह होते हैं हम यह एक गुट में विलीन हो कर अपना अस्तित्व खो बैठें। हम किसी के हाथ की कठपुतली बन जायें। क्या इस के माने यह नहीं होते हैं? उन की नीति जो है उस का अर्थ यही होता है, उस का नतीजा यही होता है कि हमारी स्वतन्त्रता में फर्क आ जाये। इस से उस पर बट्टा लगता है और हम उसे खो बैठें। मैं समझता हूं कि जितने हमारे उत्पादन के साधन हैं, जितनी हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है, जो पार्टी उस का भी विरोध करती है, वह एक तरह से हमारी जनता को गुमराह करना चाहती है जिस से कि हम अपनी स्वतन्त्रता को खो बैठें और हमारी स्वतन्त्रता चली जाय। हम किसी के हाथ की कठपुतली बन जायें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के लोग देशद्रोही नहीं कहे जा सकते? क्या वह पार्टी यह कह सकती है कि उस को अपने राष्ट्र में पूरी निष्ठा है और वह स्वतन्त्रता की वाकई हामी और मददगार है? हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वह स्वतन्त्र रहे। मेरी समझ में इस समय इन प्रश्नों को उठाना और यह कहना कि इस पार्टी को बैन कर दो या उस पार्टी को बैन कर दो, यह ठीक नहीं है। अगर यही नीति अख्त्यार करनी है तो पहले स्वतन्त्र पार्टी को बैन कर देना चाहिये जो कि हमारे राष्ट्र को इस तरह से गुमराह करना चाहती है और गलत रास्ते पर ले जाना चाहती है।

हम ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उस सिलसिले में हमारी सरकार के ऊपर आक्षेप लगाये जाते हैं गोया राउंड टेबल कान्फरेंस के लिये हम बहुत ही आतुर हैं, हम चाहते हैं कि किसी तरह से राउंड टेबल कांफ्रेंस जरूर हो और हम उस में जा कर बैठें। लेकिन विरोधी पार्टियां इस बात को भूल जाती हैं कि जो शर्तें हम ने रक्खी थीं, वह, हमारे ऊपर नेफा और लद्दाख में मैसिव अटैक होने के पहले ही रक्खी गई थीं, उस के पहले ही उन का एलान हो गया था और उस की घोषणा कर दी गई थी कि ८ सितम्बर की लाइन जो है अगर चाइना उस का मंजूर करता है तो हम बात चीत करने के लिये तैयार हैं, वर्ना तैयार नहीं हैं। अब अगर कोलम्बो प्रस्ताव हुए, और वे बहुत कुछ उन से मिलते जुलते हैं जो कि हम ने पहले घोषित कर रक्खे थे, तो उन को अस्वीकार करने के माने क्या होते हैं? क्या उस को स्वीकार न करने के माने यह नहीं होते हैं कि हम एक बात कहते हैं और जब मौका आता है तो उस से पीछे हट जाते हैं। यह आक्षेप क्या हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। कोलम्बो प्रस्ताव, जिस पर इस सदन में काफी बहस मुबाहसा हुआ और जिस में यह बात साफ की गई कि इस से हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, उस से कुछ मदद मिलती है, उस को स्वीकार करने में हानि क्या है? ऐसा नहीं है कि हम किसी डर की वजह से उन को स्वीकार कर रहे हैं। यह चीज यहां पैदा नहीं होती है। इस लिये मैं समझता हूं कि यह कहना कि हम इस

के लिये आतुर हैं, सही नहीं है। बल्कि चाइना इस के लिये आतुर था, बराबर निमंत्रण हमें देता था कि आओ बात चीत करें। हम ने उस को हिकारत से ठुकराया और हम कभी इस बात के लिये राजी नहीं होंगे कि हम उस के साथ बिना उस के ८ सितम्बर वाली बात माने हुए, बिना शर्त के बात करें। कोलम्बो पावर्स में भी शायद दो एक राष्ट्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ठीक है, बिना शर्त बात चीत की जाय। लेकिन हम ने उस से भी इन्कार कर दिया। यह चीज कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम इस के लिये आतुर हैं कि राउंड टेबल कांफ्रेंस बुलाई जाय।

हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। यह कहना भी कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। हम अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं। और अब तो यह व्यवस्था हो गई है कि हर गांव सभा में जो १८ से ले कर ४५ वर्ष तक के व्यक्ति हैं उन को ट्रेनिंग दी जाय। दलपति वगैरह चुन लिये गये हैं, और विकास क्षेत्र के स्तर पर जो दलपति हैं, उन की ट्रेनिंग हो रही है ताकि वह जा कर दूसरों को ट्रेनिंग दें। सब लोग जानते हैं कि एन० सी० सी० के इन्स्ट्रक्टर्स के लिये भी व्यवस्था हुई है कि उन को जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग दी जाय। वे जल्दी से जल्दी भर्ती किये जायें ट्रेनिंग लेने के लिये। तो कहां पर ढीलापन है, कहां कम्प्लेसेंसी है? कहीं पर भी इस तरह की कोई चीज नहीं है कि हम सुरक्षा के लिये कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर धन की बात हो तो हम धन भी एकत्र कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम अपने देश में कर सकते हैं वह कर रहे हैं। यह भी हम को मालूम है कि जो बाहर के विशेषज्ञ हैं, बाहर के जो मित्र राष्ट्र हैं, उन के भी डेलिगेशन और मिशन हम ने बुलाये हैं। ऐसी दशा में यह कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी समझ में जनता को गुमराह करना है। मैं विरोधी पार्टियों पर यह चार्ज लगाता हूं कि वह गलत वाकयात को इस तरह से कह कर देश में इस किस्म का वातावरण बनाना चाहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार निकम्मी है। इस तरह से जनता के नैतिक स्तर को कमजोर किया जा रहा है। यह देशद्रोह है न कि उन की देशभक्ति है और देश के प्रति निष्ठा है। मैं उन से अपील करूंगा कि जो रचनात्मक सुझाव उन को देने हों वे उन्हें दें, और हम लोग उन का स्वागत करेंगे। लेकिन जब तक युद्धकाल है, आपातकाल है, तब तक उन्हें चाहिये कि हमारी जनता के नैतिक स्तर को कमजोर न करें। इस समय देश में ऐसा वातावरण न बनायें कि सुरक्षा के लिये कोई चीज नहीं की जा रही है, या हम चीन से लड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। हम चीन से लड़ने के लिये तैयार हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी जनता को इस से सन्तोष है।

इतना कह कर राष्ट्रपति जी ने जो कुछ भी अपने अभिभाषण में कहा है उस का मैं स्वागत करता हूं और उन को धन्यवाद देता हूं।

†**श्री मुथिया** (तिरुनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैं अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या सभा और बैठेगी या इसे स्थगित कर दिया जाये?

†**कुछ माननीय सदस्य**: सभा स्थगित कर दी जाय।

**अध्यक्ष महोदय**: अगले दिन तक के लिये स्थगित होती है।

**इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार २७ फरवरी, सन् १९६३/८ फाल्गुन १८८४ (शक) के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

# दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार २५ फरवरी, १९६३ / ६ फाल्गुन १८८५ (शक)]


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | ४१५—४० |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | |
| १०५ लद्दाख से चीनियों का हटाना | ४१५—१८ |
| १०६ मरमागाओ बन्दरगाह | ४१८—१९ |
| १०७ कोलम्बो प्रस्ताव | ४१९—२४ |
| १०८ हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड | ४२४—२५ |
| १०९ संयुक्त समिति द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा | ४२५—२७ |
| ११० विदेशी वायुसेना विशेषज्ञ दल की भारत यात्रा | ४२८—३० |
| १११ अमरीकी सैनिक सहायता | ४३०—३१ |
| ११२ चीन-पाक सीमा करार | ४३२—३४ |
| ११३ नेफा में असैनिक प्रशासन | ४३५—३८ |
| ११४ सैनिक स्कूल | ४३८—४० |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | ४४०—७१ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | |
| ११५ विदेशी सैनिक सहायता | ४४० |
| ११६ अफ्रीकी एशियाई एकता सम्मेलन | ४४१—४२ |
| ११७ "नाइन आवर्स टु राम" | ४४३ |
| ११८ नेफा में आदिम जाति के व्यक्तियों का पुनर्वास | ४४३—४४ |
| ११९ समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन | ४४४ |
| १२० पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार | ४४४—४५ |
| १२१ त्रिदलीय सम्मेलन | ४४५ |
| १२२ भारतीय प्रदेश में चीनियों का अवैध प्रवेश | ४४६ |
| १२३ भारतीय नौ सेना | ४४६ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

| | | |
|---|---|---|
| १२४ | औद्योगिक श्रमिकों में तपेदिक तथा नैत्र रोग | ४४६–४७ |
| १२५ | प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये संयंत्र | ४४७ |
| १२६ | भारतीय युद्ध बन्दी | ४४८–४९ |
| १२७ | प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये रूसी सहायता | ४४९ |
| १२८ | संचार माध्यम का विकास | ४५० |
| १२९ | केन्द्रीय चाय मजूरी बोर्ड | ४५० |
| १३० | नई दिल्ली के चीनी दूतावास में नियुक्त भारतीय | ४५१ |
| १३१ | पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय राष्ट्रजन | ४५१–५२ |
| १३२ | मिग विमान तथा मिग विमान बनाने का कारखाना | ४५२–५३ |

अतारांकित प्रश्न संख्या

| | | |
|---|---|---|
| १५१ | काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग | ४५३ |
| १५२ | बोमडीला (नेफा) में अस्पताल | ४५४ |
| १५३ | औद्योगिक समितियों की बैठकें | ४५४ |
| १५४ | न्याय निर्णयन के लिये औद्योगिक विवाद | ४५४–५५ |
| १५५ | विकलांग जवान | ४५५ |
| १५६ | असैनिक रक्षा के लिये उपाय | ४५५–५६ |
| १५७ | चीनी आक्रमण | ४५६–५७ |
| १५८ | सेना में रखे गये भूतपूर्व आई० एन० ए० कर्मचारी | ४५७ |
| १५९ | राष्ट्रीय रक्षा कोष | ४५७ |
| १६० | जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करना | ४५७–५८ |
| १६१ | जवानों की भर्ती | ४५८ |
| १६२ | उत्पादन की गति | ४४८–५९ |
| १६३ | भारत इलेक्ट्रानिक्स | ४५९ |
| १६४ | आसाम में औद्योगिक एकक | ४५९ |
| १६५ | आयुध कारखानों की स्थापना | ४५९–६० |
| १६६ | बी० बी० सी० सिंगापुर से आकाशवाणी के प्रसारण | ४६० |
| १६७ | जवान | ४६०–६१ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या


| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| १६८ | चलचित्र परामर्शदात्री समिति | ४६१ |
| १६९ | शारीरिक रूप से असमर्थ सैनिक | ४६१ |
| १७० | सीमावर्ती क्षेत्रों में नये रेडियो स्टेशन | ४६१ |
| १७१ | केरल सरकार के लिए विशेष सहायता | ४६२ |
| १७२ | सैनिक कारखानों में उत्पादन | ४६२ |
| १७३ | सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का प्रतिरक्षा सेवाओं में उपयोग | ४६२–६३ |
| १७४ | लोहता में युद्ध सामग्री सम्भरण केन्द्र | ४६३ |
| १७५ | लाहौल तथा स्पिती पर वृत्त-चित्र | ४६३ |
| १७६ | गोरखपुर श्रमिक संगठन | ४६३–६४ |
| १७८ | कपड़ा मिलों में श्वास रोगी | ४६४ |
| १७९ | बीमा कराये हुए कर्मकारों के परिवार | ४६४ |
| १८० | भविष्यनिधि अंशदानों का जमा किया जाना | ४६५ |
| १८१ | समाचार एजेंसियां | ४६५–६६ |
| १८२ | नेफा की वर्तमान जनसंख्या | ४६६ |
| १८३ | सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान | ४६६–६७ |
| १८४ | अमरीकी लड़ाकू विमान | ४६७ |
| १८५ | बोमडीला के निकट जीप दुर्घटना | ४६७ |
| १८६ | संविधान के अनुच्छेद ३१(क) का संशोधन | ४६७–६८ |
| १८७ | बेरोजगार स्नातक | ४६८ |
| १८८ | पंजाब के लोक नृत्यों पर वृत्त-चित्र | ४६८ |
| १८९ | पंजाब में पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्ति | ४६९ |
| १९० | जावरा शुगर मिल्स | ४६९ |
| १९१ | श्रम निरीक्षकों को स्थायी बनाया जाना | ४६९ |
| १९२ | श्रम निरीक्षक | ४६९–७० |
| १९३ | ईसापुर रायफल फैक्टरी | ४७० |
| १९४ | कलिंग एयर लाइन्स | ४७० |
| १९५ | गाजीपुर कालेज में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का एयर-विंग | ४७१ |

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . ४७१–७२


(१) श्री प्र० के० देव ने १४ फरवरी, १९६३ को मध्य प्रदेश में सागर नामक स्थान पर मिलिटरी लाइन्स में पानी की एक टंकी के फट जाने के समाचार

विषय पृष्ठ

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना : (क्रमशः)**

की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया, जिसके फलस्वरूप आठ सैनिक कर्मचारी मारे गये तथा कई अन्य घायल हुये ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री य० रा० चव्हाण) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री रामेश्वर टांटिया ने बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और वहां भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने बताया कि वित्त मंत्री इस संबंध में बाद में किसी दिन एक वक्तव्य देंगे ।

**सभा पटल पर रखे गए पत्र** . . . . . ४७२

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) नौसेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत, दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३२९ में प्रकाशित भारतीय रक्षित नौसेना और भारतीय रक्षित स्वयंसेवक नौसेना (संशोधन) विनियम, १९६२ की एक प्रति ।

(३) त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १९८ के अन्तर्गत दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ३९(३८)--राजस्व/६१ की एक प्रति, जिसमें त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार (संशोधन) नियम, १९६२ दिये हुये हैं ।

**कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन––स्वीकृत** . . . ४७३

तेरहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

**राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव** . . . ४७३––५३१

२० फरवरी, १९६३ को प्रस्तुत किये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**बुधवार, २७ फरवरी, १९६३/८ फाल्गुन, १८८४ (शक)––**

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा ।


GMGIPND—LS III—2857 LSD—2-5-63—160.